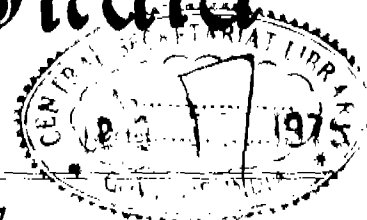




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, 6 दिसम्बर, 1975/अग्रहायण 15, 1897
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 1975/AGRAHAYANA 15, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)

NOTICE

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 30th Sept., 1975 :—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1	2	3	4
336	का० आ० 460(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1975 S.O. 460(E), dated the 2nd September, 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० लि० आ० 2717, दिनांक 23 अगस्त, 1957 में संशोधन। Amendment in the Ministry of Home Affairs notification No. S.R.O. 2717 dated the 23rd August, 1957 (as subsequently amended).
337	का० आ० 461(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1975 S.O. 461(E), dated the 2nd September, 1975	मंत्रिमंडल सचिवालय Cabinet Secretariat	भारत सरकार (कार्य आर्बटन) नियम, 1961 में संशोधन करने के लिए नियम बनाना। Making rules to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961.
338	का० आ० 462(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1975 S.O. 462(E), dated the 4th September, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies	राज्य के सहायक बाट और माप नियंत्रक की और उससे ऊपर की पंक्ति के प्रत्येक अधिकारी को पैकेज में रखी गई वस्तु (विनियमन) आदेश, 1975 के पैरा 8 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत करना। Authorising every officer, of and above the rank of an Assistant Controller of Weights and Measures in a State, to carry out the provisions of paragraph 8 of the Packaged Commodities (Regulation) Order, 1975.

1	2	3	4
339	सां० नि० 463(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1975 S.O. 463(E), dated the 4th September, 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) में उल्लिखित हिमाचल प्रदेश में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी को सक्रिय इयूटी घोषित करना। Declaring the duty by every person referred to in clause (a), sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968)—serving in Himachal Pradesh to be an active duty.
	सां० नि० 464(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1975 S.O. 464(E), dated the 4th September, 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) में उल्लिखित उड़ीसा में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी को सक्रिय इयूटी घोषित करना। Declaring the duty by every person referred to in clause (a), Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 serving in Orissa, as active duty.
	सां० नि० 465(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1975 S.O. 465(E), dated the 4th September, 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) में उल्लिखित गोवा, दमण और दीव में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी को सक्रिय इयूटी घोषित करना। Declaring the duty by every person referred to in clause (a), sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 serving in Goa, Daman and Diu, as active duty.
	सां० नि० 466(अ), दिनांक 4 सितम्बर 1975 S.O. 466(E), dated the 4th September, 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) में उल्लिखित पाण्डिचेरी में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी को सक्रिय इयूटी घोषित करना। Declaring the duty by every person referred to in clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 serving in Pondichery, as active duty.
	सां० नि० 467(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1975 S.O. 467(E), dated the 4th September, 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) में उल्लिखित अरुणाचल प्रदेश में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी को सक्रिय इयूटी घोषित करना। Declaring the duty by every person referred to in clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 serving in Arunachal Pradesh, as active duty.
	सां० नि० 468(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1975 S.O. 468(E), dated the 4th September, 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) में उल्लिखित दादर और नागर हवेली में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी को सक्रिय इयूटी घोषित करना। Declaring the duty by every person referred to in clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 serving in Dadra and Nagar Haveli, as active duty.
	सां० नि० 469(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1975 S.O. 469(E), dated the 4th September, 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) में उल्लिखित तमिलनाडु में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी को सक्रिय इयूटी घोषित करना। Declaring the duty by every person referred to in clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 serving in Tamil Nadu, as active duty.
	सां० नि० 470(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1975 S.O. 470(E), dated the 4th September, 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) में उल्लिखित सिक्किम में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति की इयूटी को सक्रिय इयूटी घोषित करना। Declaring the duty by every person referred to in clause (a), sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 serving in Sikkim, as active duty.
340	सां० प्रा० 471(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1975 S.O. 471(E), dated the 4th September, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies	श्री वी० पी० गुप्त, अवर सचिव, उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) को भारत में निर्मित ट्रैक्टरों के संबंध में नियंत्रक नियुक्त करना। Appointing Shri V.P. Gupta, Under Secretary, Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Heavy Industry) as a Controller in respect of tractors manufactured in India.
341	S.O. 472(E), dated the 5th September, 1975	Ministry of Finance	Making the Scheme to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974.
342	S.O. 473(E), dated the 5th September, 1975	Ministry of Industry and Civil Supplies	Corrigendum to the Ministry of Industry and Civil Supplies Order No. F. WM-15(9)/75 published as S.O. 443(E), dated the 22nd August, 1975.

1	2	3	4
343	का० प्रा० 474(अ), उ० वि० वि० अ/ 29अ/75, दिनांक 5 सितम्बर, 1975 S.O. 474(E), IDRA/29B/75, dated the 5th September, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies	समस्त संशोधित औद्योगिक उपक्रमों को उल्लिखित शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रवर्तन से छूट देना। Exempting from the Operation of clause (d) of sub-section (1) of section 13 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the rules made thereunder all enunciated Industrial Undertakings to the extent specified subject to the conditions mentioned.
344	का० प्रा० 475(अ), दिनांक 5 सितम्बर, 1975 S.O. 475(E), dated the 5th September, 1975	वित्त मंत्रालय Ministry of Finance	सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करना जिस तारीख को उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे। Appointing the date specified in column (1) of the table as the date on which the provisions of the Taxation Laws (Amendment) Act, 1975 specified in the corresponding entry in column (2) of the said table shall come into force.
345	का० प्रा० 476(अ), दिनांक 5 सितम्बर, 1975 S.O. 476(E), dated the 5th September, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपसचिव, श्री जी० रामनाथन को इलेक्ट्रिकल केबल्स एण्ड वायर्स कंट्रोल ऑर्डर, 1970 के अनुच्छेद 2 की धारा (क) के प्रयोजनार्थ नियंत्रक नियुक्त करना। Appointing Shri G. Ramanathan, Deputy Secretary, Ministry of Industry and Civil Supplies as Controller for the purpose of Clause (a) of paragraph 2 of the Electrical Cables and Wires Control Order, 1970.
346	का० प्रा० 477(अ), दिनांक 6 सितम्बर, 1975 S.O. 477(E), dated the 6th September, 1975	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में संशोधन करने के लिए आदेश का निर्माण करना। Making the Order to amend the Exports (Control) Order, 1968.
347	का० प्रा० 478(अ), दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 478(E), dated 8th Sept. 1975 का० प्रा० 479(अ), दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 479(E), dated 8th Sept. 1975 का० प्रा० 480(अ), दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 480(E), dated 8th Sept., 1975	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 का सिक्किम राज्य में प्रवृत्त होना। Fixation of date of enforcement of Civil Defence Act, 1968 in the State Sikkim. नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 का सिक्किम राज्य में विस्तार तथा प्रवर्तन होना। Extension and enforcement of Civil Defence Rules, 1968 in the State Sikkim. नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 का सिक्किम राज्य में विस्तार तथा प्रवर्तन होना। Extension and enforcements of Civil Defence Regulations, 1968 in the State of Sikkim.
348	का० प्रा० 481(अ)/18क/ उ० वि० वि० अ/75, दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 481(E)/18AA/ IDRA/75, dated 8th Sept., 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies	भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा मैसर्स सेन रेलेह लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करना। Take over of the managements of M/s. Sen Raleigh Ltd., Calcutta by Industrial Reconstruction Corporation of India Limited.
349	का० प्रा० 482(अ) 18क/ उ० वि० वि० अ०/75, दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 482(E)/18AA/ IDRA/75, dated 8th Sept., 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies	भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा मैसर्स एन्सी-लरी इण्डस्ट्रीज (लग्स) प्रा० लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करना। Take over of managements of M/s. Ancillary Industries (Lugs) Private Ltd., by Industrial Reconstruction Corporation of India Limited.
350	का० प्रा० 483(अ) 18क/ उ० वि० वि० अ०/75, दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 483(E)/18AA/ IDRA/75, dated 8th Sept., 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies	भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा मैसर्स सेन एण्ड पण्डित इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करना। Take over of managements of M/s. Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta by the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited.

1	2	3	4
351	का० प्रा० 484(प्र)/18कक/ उ० वि० वि० प्रा०/75, दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 484(E)/18AA/ IDRA/75, dated the 8th Sept., 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies	भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन नियम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा मैसर्स एन्स-लरी इण्डस्ट्रीज (कोजिमस) प्रा० लि० कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करना। Take over of the managements of M/s. Ancillary Industries (Forgings) Pvt. Ltd., Calcutta by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd.
352	का० प्रा० 485(प्र)/18कक/ उ० वि० वि० प्रा०/75, दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 485(E)/18AA/ IDRA/75, dated the 8th Sept., 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies	भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन नियम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा मैसर्स एन्स-लरी इण्डस्ट्रीज (क्रैंक्स) प्रा० लि० कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करना। Take over of the managements of M/s. Ancillary Industries (Cranks) Pvt. Ltd., Calcutta by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd.
353	का० प्रा० 486(प्र), दिनांक 8 सितम्बर, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) प्रादेश सं० का० प्रा० 443(प्र), दिनांक 22 अगस्त, 1975 का शुद्धि-पत्र
354	का० प्रा० 487(प्र), दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 487(E), dated the 8th Sept., 1975 का० प्रा० 488(प्र), दिनांक 8 सितम्बर, 1975 S.O. 488(E), dated 8th September, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry & Civil Supplies.	कागज (उत्पादन का नियंत्रण) प्रादेश, 1974 में प्राप्ति संशोधन Further amendment to Paper (Control of Production) Order, 1974. कागज (उत्पादन का नियंत्रण) तृतीय संशोधन प्रादेश, 1975 Paper (Control of Production) 3rd Amendment Order, 1975
355	का० प्रा० 489(प्र), दिनांक 10 सितम्बर, 1975 S.O. 489(E), dated 10th September, 1975	श्रम मंत्रालय Ministry of Labour	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का पब्लिश हारियाणा राज्य के कुछ क्षेत्रों में प्रवृत्त करना। Enforcement of Employees' State Insurance Act, 1948 of certain places in the State of Haryana.
356	का० प्रा० 490(प्र), दिनांक 10 सितम्बर, 1975 S.O. 490(E), dated 10th September, 1975 का० प्रा० 491(प्र), दिनांक 10 सितम्बर, 1975 S.O. 491(E), dated 10th September, 1975 का० प्रा० 492(प्र), दिनांक 10 सितम्बर, 1975 S.O. 492(E), dated 10th September, 1975 का० प्रा० 493(प्र), दिनांक 10 सितम्बर, 1975 S.O. 493(E), dated 10th September, 1975 का० प्रा० 494(प्र), दिनांक 10 सितम्बर, 1975 S.O. 494(E), dated 10th September, 1975 का० प्रा० 495(प्र), दिनांक 10 सितम्बर, 1975 S.O. 495(E), dated 10th September, 1975	सूचना और प्रसारण मंत्रालय Ministry of Information & Broadcasting तदैव Do. सूचना और प्रसारण मंत्रालय Ministry of Information & Broadcasting तदैव Do. तदैव Do. तदैव Do. तदैव Do.	उन फिल्मों की स्वीकृति जो अनुसूची में दी गई हैं। Approval of Films specified in the Schedule. उन फिल्मों की स्वीकृति जो अनुसूची में दी गई हैं। Approval of films specified in the schedule. उन फिल्मों की स्वीकृति जो अनुसूची में दी गई हैं। Approval of films specified in the schedule. उन फिल्मों की स्वीकृति जो अनुसूची में दी गई हैं। Approval of films specified in the schedule. उन फिल्मों की स्वीकृति जो अनुसूची में दी गई हैं। Approval of films specified in the schedule. उन फिल्मों की स्वीकृति जो अनुसूची में दी गई हैं। Approval of films specified in the schedule. उन फिल्मों की स्वीकृति जो अनुसूची में दी गई हैं। Approval of films specified in the schedule.
357	का० प्रा० 496(प्र), दिनांक 10 सितम्बर, 1975 S.O. 496(E), dated 10th September, 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय Ministry of Law, Justice & Company Affairs.	संसदीय निर्वाचन संचालन (सिक्किम) नियम, 1975 Conduct of Parliamentary Elections (Sikkim) Rules, 1975

1	2	3	4
358	का० प्रा० 497(प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 497(E), dated 12th September, 1975 का० प्रा० 498(प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 498(E), dated 12th September, 1975 का० प्रा० 499(प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 499(E), dated 12th September, 1975 का० प्रा० 500(प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 500(E), dated 12th September, 1975 का० प्रा० 501(प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 501(E), dated 12th September, 1975 का० प्रा० 502(प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 502(E), dated 12th September, 1975 का० प्रा० 503(प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 503(E), dated 12th September, 1975 का० प्रा० 504(प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 504(E), dated 12th September, 1975	भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India तदैव Do. भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India तदैव Do. तदैव Do. भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India तदैव Do. तदैव Do. तदैव Do. तदैव Do. तदैव Do.	श्री डी० सी० लुक्सोम, सचिव, सिक्किम राज्य को उस राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नाम निर्देशन होना। Nomination of Shri D.C. Lucksom, Secy. to the Govt. of Sikkim as Chief Electoral Officer for that state. निर्वाचन आयोग सिक्किम राज्य के विधान सभा के सदस्यों द्वारा लोक सभा के लिए मेम्बर निर्वाचित करना। Election Commission hereby calls upon the members of Legislative Assembly of Sikkim to elect the members for House of the People. सिक्किम राज्य के विधान सभा मेम्बरों द्वारा निर्वाचन के लिए तारीख नियत करना। Fixation of dates by members of Legislative Assembly of Sikkim for Election. लोक सभा के निर्वाचन के लिये सिक्किम राज्य के लिये समय नियत करना। Fixation of time for Poll by the House of the People in Sikkim श्री भार० के० गुप्त सचिव, सिक्किम राज्य को रिटर्निंग आफिसर और श्री बी० एन० शर्मा के सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करना। Appointment of Shri R. K. Gupta, Secy., Sikkim & Shri B. N. Sharma A.D.O. Gangtok as Returning Officer & to assist the returning Officer respectively. राज्य सभा के लिए एक सदस्य जो सिक्किम की विधान सभा द्वारा निर्वाचित करने की तिथि नियत करना। Dated fixed for Election of one member to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Sikkim. राज्य सभा के लिए निर्वाचन के लिए सिक्किम राज्य में निर्वाचन के लिए समय नियत करना। Times fixed for the Poll in Sikkim of Election to the Council of State. रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर का सिक्किम में निर्वाचन कराने के लिए नियुक्त करना। Appointment of Returning Officer & Assisting Returning Officer for the Election in Sikkim.
359	का० प्रा० 505 (प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 505(E), dated the 12th Sept. 1975. का० प्रा० 506 (प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 506(E) dated 12th September, 1975.	ऊर्जा मंत्रालय Ministry of Energy. ऊर्जा मंत्रालय Ministry of Energy.	केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना। Notices given by central Govt. of its intention to prospect for coal. केन्द्रीय सरकार द्वारा भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1950, दिनांक 29 मई, 1969 को विषयित करना। Resignation of late Min. of Steel and Mines (Deptt. of Mines and Metal Notification No. S.O. 1950 of 29th May 1969 by the Central Govt.
360	का० प्रा० 507 (प्र), दिनांक 12 सितम्बर 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	राष्ट्रपति सिक्किम राज्य को विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को राज्य सभा में एक सदस्य का निर्वाचन करने हेतु आहूत करना। The President Calls upon the elected members of the Legislature Assembly of the State of Sikkim to elect a member for the Council of States.
361	S.O. 507(E), dated 12th September, 1975. का० प्रा० 508(प्र), दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 508 (E), dated, 12th September, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय। Ministry of Industry and Civil Supplies.	भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में संशोधन करना। Amendment in the order of Govt. of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies.

1	2	3	4
362	का० प्रा० 509(अ)/18एए/आई०डी० भार० ए०/75, दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 509(E), 18AA/IDRA/75, dated 12th September, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय। Ministry of Industry and Civil Supplies.	भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में आदेश सं० का० प्रा० 482(अ)/18एए/आई०डी० भार० ए०/75, दिनांक 8-9-75 में संशोधन करना। Amendment in the order of the Govt of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies No. S.O. 482(E)/18 AA/IDRA/75, dated 8-9-75.
363	का० प्रा० 510(अ)/18एए/आई०डी० भार० ए०/75, दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 510(E)/18AA/IDRA/75, dated, 12th September, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 483 (अ) 18एए/आई०डी० भार० ए० 75, दिनांक 8-9-75 में संशोधन। Amendment in the order of Govt. of India in the Min. of Industry and Civil Supplies No. S.O. 483(E)/18AA/IDRA/75, dated 8-9-75.
364	का० प्रा० 511(अ)/18एए/आई०डी० भार० ए०/75, दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 511(E) /18 AA/IDRA/75, dated 12th September, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय। Ministry of Industry and Civil Supplies.	भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० 484(अ)/18एए/आई०डी० भार० ए०/75, दिनांक 8-9-75 में संशोधन। Amendment in the order of Govt. of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies No. S.O. 484(E)/18 AA/IDRA/75, dated 8-9-75.
365	का० प्रा० 512(अ)/18एए/आई०डी० भार० ए०/75, दिनांक 12 सितम्बर, 1975 S.O. 512E/18AA/IDRA/75, dated 12th September, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय। Ministry of Industry and Civil Supplies.	भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 485(अ)/18एए/आई०डी० भार० ए०/75, दिनांक 8-9-75 संशोधन। Amendment in the order of Govt of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies No. S.O. 485(E)/18 AA/IDRA/75, dated 8-9-75.
366	का० प्रा० 513(अ)/18एए/आई०डी० भार० ए०/75, दिनांक 15 सितम्बर, 1975। S.O. 513(E)/18 AA/IDRA/75, dated 15 Sept. 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय। Ministry of Industry and Civil Supplies.	भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय में और आगे संशोधन। Further amendment in the order of Govt of India in the Late Ministry of Industrial and Development.
367	का० प्रा० 514(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1975। S.O. 514(E), dated 15th September, 1975.	मंत्रिमण्डल सचिवालय Cabinet Secretariat.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अपराधों की खोज। Investigation of Officers by Delhi Special Police Establishment.
	का० प्रा 515(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1975 S.O.515(E) dated 15th September, 1975.	मंत्रिमण्डल सचिवालय Cabinet Secretariat	पटना और भागलपुर कोतवाली मामलों के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की सदस्यों की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का विस्तार करना। Extension of power and jurisdiction to the Delhi Special Police Establishment for Patna and Bhagalpur kotwali Cases.
368	का० प्रा० 516(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1975 S.O. 516(E), dated 15th September, 1975.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय। Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	सिक्किम विधियों का अनुकूलन (संख्या 1) (संशोधन) आदेश, 1975। The Adaptation of Sikkim Laws (No. 1) Amendment Order 1975.
369	का० प्रा० 517 (अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1975 S.O. 517(E), dated, 15th September 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce.	नियति (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन। Further amendment to Export (Control) Order, 1968.
370	का० प्रा० 518 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 1975 S.O. 518(E), dated 16th September 1975.	कृषि और सिंचाई मंत्रालय Ministry of Agriculture and Irrigation.	भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कृष्णा जल विवाद के अधिकरण के लिए न्यायभूमि श्री दिव्यन्दु मोहन सेन को मनोनीत करना। Nomination of the Shri Justice Dibyendru Mohan Sen by the Chief Justice of India for Krishna Water disputes Tribunal.
	का० प्रा० 519 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 1975 S.O. 519(E), dated 16th September 1975.	कृषि और सिंचाई मंत्रालय Ministry of Agriculture and Irrigation.	भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1421, दिनांक 10 अप्रैल, 1969 में संशोधन। Amendment to late Ministry of Irrigation and Power Notification No. S.O. 1421 of 10th April, 1969.
371	का० प्रा० 520(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 1975 S.O. 520(E), dated 16 September, 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce.	आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में संशोधन। Amendment to imports (Control) Order, 1955.

1	2	3	4
372	S.O. 521(E), dated 17th September, 1975.	Ministry of Finance.	General Ins. (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975.
373	S.O. 522(E), dated 18th September, 1975.	Election Commission of India.	Proposals made by Election Commission for the delimitation of 2 Parliamentary and 30 single member territorial constituencies.
374	S.O. 523(E), dated 18th September 1975. S.O. 524(E), dated 18th September, 1975.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs. Do.	Application of Companies Act, 1956 to all classes of Financial Companies. Rules to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.
375	का० प्रा० 525 (अ), दिनांक 19 सितम्बर, 1975 S.O. 525(E), dated 19th September, 1975. का० प्रा० 526 (अ), दिनांक 19 सितम्बर, 1975 S.O. 526(F), dated 19th December, 1971.	वित्त मंत्रालय Ministry of Finance. वित्त मंत्रालय Ministry of Finance.	वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 5483, दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 के साथ आपात जोखिम (माल) में और प्रागे संशोधन। Further amendment of Emergency Risks (Goods) in the Min. of Finance (Deptt. of Revenue and Insurance) No. S.O. 5483, dated 10th December, 1971. वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 5486, दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 के आपात जोखिम (उपक्रम) में और प्रागे संशोधन। Further amendment of Emergency Risks (Undertakings) in the Ministry of Finance (Deptt. Revenue and Insurance) No. S.O. 5486, dated 10th December, 1971)
376	का० प्रा० 527(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1975 S.O. 527(E), dated 20th September, 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce.	पटसन उपायुक्त द्वारा आन्ध्र प्रदेश के पदधारियों को शक्तियों का निहित करना। Vesting of Powers by the Jute Commissioner to the Officials of the Govt. of Andhra Pradesh.
377	का० प्रा० 528 (अ), दिनांक 22 सितम्बर, 1975 S.O. 528(E), dated 22nd September, 1975. का० प्रा० 529(अ), दिनांक 22 सितम्बर, 1975 S.O. 529(E), dated 22nd September, 1975.	भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India. भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India.	राजस्थान राज्य के लिये परिसीमन आयोग अपने आदेश सं 44, दिनांक 30 जून, 1975 में अध्याधरित करना। Specification of Delimitation Commission in its order No. 44 dated 30 June, 1975 for the State of Rajasthan. राजस्थान राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर सहायता करने के लिये सहायक के रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करना। Appointments of Asstt. Returning Officer to assist the Returning Officers of the Parliamentary Constituency of Rajasthan State.
378	का० प्रा० 530 (अ), दिनांक 22 सितम्बर, 1975 S.O. 530(E), dated 22nd September, 1975. का० प्रा० 531 (अ), दिनांक 22 सितम्बर, 1975 S.O. 531(E), dated 22nd September, 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce. वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	वस्त्र आयुक्त के आदेश सं० सी० एल० बी० आई० 1/1-1/72 दिनांक 24 अक्तूबर, 1972 में संशोधन। Amendment to the textile Commissioner's order No. CLBI/1/1-J/72 dated the 24th October, 1972. नियंत्रित वस्त्र आयुक्त निर्दिष्ट शर्तों पर बेचेगा। Conditions of Textile Commissioner to mills for sale of Controlled Cloth.
379	का० प्रा० 532 (अ)/18 एफ० बी०/आई० डी० आर० ए०/75 दिनांक 22 सितम्बर, 1975 S.O. 532(E)/18FB/IDRA/75, dated 22nd September, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	आन्ध्र प्रदेश राज्य के उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 का और विस्तार करना। Further extension of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 in the State of Andhra Pradesh.
380	का० प्रा० 533 (अ), दिनांक 23 सितम्बर, 1975 S.O. 533(E), dated 23rd September 1975	भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India.	निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचनार्थ। Publication of Conduct election of Rules, 1961 for General information.
381	का० प्रा० 534(अ) दिनांक 24 सितम्बर 1975 S.O. 534(E), dated 24th September, 1975.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड Central Board of Direct Taxes.	आयकर नियम, 1962 में संशोधन Amendment to Income-tax Rules, 1962.
382	का० प्रा० 535(अ), दिनांक 24 सितम्बर, 1975 S.O. 535(E), dated 24th September, 1975,	वित्त मंत्रालय Ministry of Finance.	भारतीय रिजर्व बैंक किसी प्राधिकृत व्यक्ति से अनुसूची 2, 3 और 4 में कैंसी खरीदना या बेचना। Reserve Bank of India shall buy from or sell to any authorised person for currency specified in Col. 2, 3 and 4 in the schedule.

1	2	3	4
	S.O. 536(E), dated 26th September, 1975. का० प्रा० 537(प्र), दिनांक 26 सितम्बर, 1975	Ministry of Tourism and Civil Aviation. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय।	Corrigendum to Ministry of Tourism and Civil Aviation Notfin. No. S.O. 450 (E), dated 27th August 1975. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० 450(प्र), दिनांक 27 अगस्त, 1975 में सुद्धियां करना।
384	का० प्रा० 538 (प्र), दिनांक 26 सितम्बर, 1975	ग्रह मंत्रालय	पाण्डीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 का और प्रागे बढ़ाना।
	S.O. 538 (E), dated 26th September, 1975.	Ministry of Home Affairs.	Further continuation of Govt. of Union Territories Act, 1963 in the Union Territory of Pondicherry.
385	का० प्रा० 539 (प्र), 18ए०/आई० डी० प्रार० ए०/75, दिनांक 26 सितम्बर, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 13 (प्र) दिनांक 3 जनवरी, 1974 में संशोधन।
	S.O. 539(E), 18/A/IDRA/75, dated 26th September, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Amendment in the Late Ministry of Industrial Development No. S.O. 13(E), dated 3rd January, 1974.
386	का० प्रा० 540(प्र)/18ए०/आई० डी० प्रार० ए०/75, दिनांक 26 सितम्बर, 1975	तदेव	भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का प्रा० 14(प्र), दिनांक 3 जनवरी, 1974 में संशोधन।
	S.O. 540(E)/18A/IDRA/75, dated 26th September, 1975.	Do.	Amendment in the Late Ministry of Industrial Development No. S.O. 14(E), dated 3rd January, 1974.
387	का० प्रा० 541(प्र)/18 एफ० बी०/ आई० डी० प्रार० ए०/75, दिनांक 26 सितम्बर, 1975	तदेव	आदेश सं० का० प्रा० 700 (प्र)/18 एफ० बी०/74, दिनांक 6 सितम्बर 1974 की उक्त आदेश अधि 30 अगस्त, 1975 तक बढ़ाना।
	S.O. 541(E)/18FB/IDRA/75, dated, 26th September, 1975.	Do.	Extension of Order No. S.O. 700(E)/18FB/IDRA/74 dated the 6th December, 1974 up to 30th August, 1975.
388	का० प्रा० 542(प्र), दिनांक 26 सितम्बर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	नियति (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और प्रागे संशोधन।
	S.O. 542(E), dated 26th September, 1975.	Ministry of Commerce.	Further amendment of Export (Control) Order, 1968.
389	का० प्रा० 543(प्र), दिनांक 26 सितम्बर, 1975	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	आय-कर नियम, 1962 में और प्रागे संशोधन।
	S.O. 543(E), dated 26th September, 1975.	Central Board of Direct Taxes	Further rules to amend the Income-tax Rules, 1962.
390	का० प्रा० 544(प्र), दिनांक 27 सितम्बर, 1975	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाहप लाहमों को विछाने का प्रयोजन।
	S.O. 544 (E), dated, 27th September, 1975.	Ministry of Petroleum and Chemicals	Acquisition of lands for the purpose of laying pipelines by the Central Government.
391	का० प्रा० 545(प्र)/18 एफ० बी०/ आई० डी० प्रार० ए०/75, दिनांक 27 सितम्बर, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन मैसम सेन रेले लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध को ग्रहण करना।
	S.O. 545(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Take over of management of M/s. Sen Relaiigh Ltd., Calcutta under Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
392	का० प्रा० 546 (प्र)/18 एफ० बी०/ आई० डी० प्रार० ए०/75, दिनांक 27 सितम्बर, 1975	तदेव	मैसर्स एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज (लम्स) प्रा० लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा ग्रहण करना।
	S.O. 546(E)/18 FB/IDRA/75, dated 27th Septemr, 1975.	Do.	Take over of the management of M/s. Ancillary Industries (Lugs) Private Limited, Calcutta by Govt. of India.
393	का० प्रा० 547 (प्र)/18 एफ० बी०/ आई० डी० प्रा० ए०/75, दिनांक 27 सितम्बर, 1975।	तदेव	मैसर्स सेन एण्ड पंडित इण्डस्ट्रीज, लि०, कलकत्ता का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा ग्रहण करना।
	S.O. 547(E)/18FB/IDRA/75 dated 27th September, 1975.	Do.	Take over of the management of M/s. Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta by the Govt. of India.
394	का० प्रा० 548(प्र)/18 एफ० बी०/ आई० डी० प्रार० ए०/75, दिनांक 27 सितम्बर, 1975।	तदेव	मैसर्स एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज (फोर्जिंग) प्रा० लि०, कलकत्ता का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा ग्रहण करना।
	S.O. 548(E)/18FB/IDRA/75, dated 27th Septemr, 1975.	Do.	Take over of the Management of M/s. Ancillary Industries (Forg- ing) Private Ltd., Calcutta by Govt. of India.
395	का० प्रा० 549(प्र)/18 एफ० बी०/ आई० डी० प्रार० ए०/75, दिनांक 27 सितम्बर 1975	तदेव	मैसर्स एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज (क्रैंक) प्रा० लि०, कलकत्ता का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा ग्रहण करना।
	S.O. 549(E)/18FB/IDRA/75, dated 27th Sept., 1975.	Do.	Take over of the Management of M/s. Ancillary Industries (Cranks) Private Ltd., Calcutta by the Govt. of India.

1	2	3	4
396	का० प्रा० 550 (घ), दिनांक 29 सितम्बर, 1975 S.O. 550(E), dated 29th September, 1975.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय Ministry of Shipping and Transport.	परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० 225 (ई) दिनांक 2 मई, 1973 में संशोधन। Amendments of Min. of Shipping and Transport (Transport Wing) Notfn. No. S.O. 255(E) of 2-5-73.
397	का० प्रा० 551 (घ) / 18E/उ० वि० वि० प्र०/75, दिनांक 29 सितम्बर, 1975 S.O. 551(E)/18E/IDRA/75, dated 29th September, 1975.	औद्योगिक और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	विकास और विनियम अधिनियम, 1951 के अधीन मेसर्स हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई के गाजियाबाद एकक का प्रबन्ध ग्रहण करना। Take over of management of the Ghaziabad unit of M/s. Hind Cycles Ltd., Bombay under Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
398	का० प्रा० 552 (घ)/18 एक०बी०/ आई० डी० आर० ए०/75, दिनांक 29 सितम्बर, 1975 S.O. 552(E)/18E/IDRA/75, dated 29th September, 1975.	तदेव Do.	मेसर्स हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई का उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अधीन प्रबन्ध को ग्रहण करना। Take over of management of the Bombay unit of M/s. Hind Cycles Ltd., Bombay under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
399	का० प्रा० 553 (घ), दिनांक 29 सितम्बर 1975 S.O. 553(E), dated 29th September, 1975. का० प्रा० 554 (घ), दिनांक 29 सितम्बर 1975 S.O. 554(E), dated 29th September, 1975.	भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India. तदेव Do.	जम्मू-कश्मीर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करना। Appointments of Returning Officer of the Parliamentary Constituencies for the State of Jammu and Kashmir. जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए रिटर्निंग आफिसर की कृत्यों के पालन के सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करना। Appointments of Asstt. Returning officer to assist the Returning Officers for the State of Jammu and Kashmir.
400	का० प्रा० 555 (घ), दिनांक 29 सितम्बर, 1975 S.O. 555(E), dated, 29th September 1975. का० प्रा० 556 (घ), दिनांक 29 सितम्बर, 1975 S.O. 556(E), dated 29th September, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies. तदेव Do.	नागरिक पूर्ति मंत्रालय में निदेशक (घाट और माप) के प्राधिकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना। Specification of the Director (Weight and Measures) in the Ministry of Industry and Civil Supplies. उद्योग और नागरिक मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 443 (घ) दिनांक 22 अगस्त, 1975 में सुधार करना। Corrigenda in the Ministry of Industry and Civil Supplies No. S.O. 443(E), dated 22nd August, 1975.
401	का० प्रा० 557 (घ), दिनांक 30 सितम्बर, 1975 S.O. 557(E), dated 30th September, 1975.	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs.	2 अक्तूबर 1975 को राजभाषा अधिनियम, 1963 का सिक्किम राज्य में प्रवृत्त होना। Enforcement of the Official Languages, Act, 1963 on 2nd October, 1975 in the State of Sikkim.
402	का० प्रा० 558 (घ), दिनांक 30 सितम्बर, 1975	वित्त मंत्रालय	वित्त मंत्रालय (केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 369 (घा) में संशोधन।
403	का० प्रा० 559 (घ), दिनांक 30 सितम्बर, 1975 S.O. 559(E), dated 30th September, 1975.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड Central Board of Direct Taxes	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा धन कर नियम, 1957 में संशोधन। Further amendment of Wealth-tax Rules, 1957 by the Central Board of Direct Taxes.
404	का० प्रा० 560 (घ), दिनांक 30 सितम्बर, 1975 S.O. 560(E), dated 30th September, 1975. का० प्रा 561 (घ), दिनांक 30 सितम्बर, 1975 S.O. 561(E), dated 30th September, 1975.	भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India	जम्मू-कश्मीर राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर नियुक्त करना। Appointment of Electoral Registration Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Jammu and Kashmir. जम्मू-कश्मीर राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की सहायता के लिए नियुक्त करना। Appointment of Assistant Electoral Registration Officer to assist Electoral Registration Officer in the Parliamentary Constituency in the State of Jammu-Kashmir.
405	का० प्रा० 562 (घ), दिनांक 30 सितम्बर, 1975 S.O. 562(E), dated, 30th September, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, 1967 में अतिरिक्त संशोधन करना। Further amendment of the Cement Control Orders, 1967.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1975

का०आ० 5114.--यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 185-गोरखपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राधे श्याम, मुहल्ला छोटे काजीपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यायोजित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राधे श्याम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/185/74(255)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th October, 1975

S.O. 5114.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Radhey Shyam, Mohalla Chhote Kazipur, Gorakhpur Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 185-Gorakhpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Radhey Shyam to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/185/74 (255)]

आदेश

का०आ० 5115.--यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 185-गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम कुमार उर्फ राज कुमार यादव, मुहल्ला राम दत्तपुर, 35, जाफरा बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यायोजित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम कुमार उर्फ राज कुमार यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/185/74(256)]

ORDER

S.O. 5115.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Kumar alias Raj Kumar Yadav, Mohalla Ramdutt pur, 35-Jafra Bazar, Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 185-Gorakhpur, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Kumar alias Raj Kumar Yadav to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. UP-LA/185/74 (256)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1975

का०आ० 5116.--यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 83-बेनीगंज (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विपिन बिहारी लाल, 565/1441, पूरन नगर (मेलावा) जिला सखनऊ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यायोजित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री विपिन बिहारी लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/83/74(292)]

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1975

S.O. 5116.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bipin Behari Lal, 565/1441 Pooran Nagar (Bhela-wan) District Lucknow, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 83-Beniganj (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bipin Behari Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-JA/83/74 (292)]

आदेश

कांआ० 5117.--यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 122-गौरीगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम नरेश सिंह, ग्राम प. पो० सैंठा, जिला मुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विषयक बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यायोजित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम नरेश सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/122/74(294)]

ORDER

S.O. 5117.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Naresh Singh, Village and Post Office Saintha, District—Sultan Pur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 122-Gauriganj, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Naresh Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/122/74 (294)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1975

कांआ० 5118.--यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 19-अफजलगढ़ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम गोपाल, ग्राम प. डा० कादराबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विषयक बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यायोजित्य नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम गोपाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/19/74(299)]

ORDER

New Delhi, the 18th October, 1975

S.O. 5118.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Gopal, Village and Post Office Qadriabad, District Bijnor, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 19-Afzalgarh, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Gopal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/19/74 (299)]

आदेश

कांआ० 5119.--यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 85-अहिरोरी (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उदय प्रताप, ग्राम गोल खरी डा० झाँडा-साँट, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विषयक बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या व्यायोजित्य नहीं है;

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री उदय प्रताप को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०सं०/85/74(301)]

ORDER

S.O. 5119.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Uday Pratap, Village Gulkhari, Post Office Ant Sant, District—Hardoi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 85-Ahironi (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Uday Pratap to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/85/74 (301)]

आदेश

का०आ० 5120.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 89-शाहाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राज बहादुर, पोस्ट शाहाबाद, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्पर्क सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री राज बहादुर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०सं०/89/74(302)]

ORDER

S.O. 5120.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raj Bahadur, Post Office Shahabad, District—Hardoi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 89-Shahabad, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raj Bahadur to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/89/74 (302)]

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1975

का० आ० 5121.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 434/असम/75, तारीख 15 जुलाई, 1975 द्वारा नियुक्त आफिसरों के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट असम सरकार के आफिसर को उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिये नियुक्त करता है :—

सारणी	
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1	2
14. लखीमपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर।	5. उप-खण्ड आफिसर, धेमाजी

आदेश से,

[सं० 434/असम/75 (2)]

ए०एन० सैन, सचिव

New Delhi, the 6th November, 1975

S.O. 5121.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints, in addition to the officers appointed in its notification No. 434/AS/75, dated 15th July, 1975, the officer of the Government of Assam as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency specified in Column 1 of the said Table :—

Table	
Sl. No. and name of the Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
Returning Officer of 14 Lakhimpur Parliamentary Constituency.	5. Sub-Division Officer, Dhemaaji.

By Order,

[No. 434/AS/75(2)]

A. N. SEN, Secy.

विधि स्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975

नोटिस

का०आ० 5122.—इसके द्वारा, मुख्य प्रमाणक मिसम (नोटरीज ऑफिस), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी की श्री गोकुल मल, एडवोकेट,

सिकार (राजस्थान) ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, सिकार जिले (जिसका मुख्यालय सिकार में होगा) में लेख्य प्रमाणक (नोटरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति को लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्तर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें।

[सं० 22/23/75-न्याय]

प्रार०एल० परदीप, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NYAYA-VIBHAG

NOTICE

New Delhi, the 18th November, 1975

S.O. 5122.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Pokar Mal, Advocate Sikar (Rajasthan) for appointment as a Notary to practice in Sikar District (at D.H. Quarter Sikar).

Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/23/75-Jus.]

R. L. PARDEEP, Competent Authority.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

(समाहर्ता, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय)

कानपुर, 8 अक्टूबर, 1975

सीमा-शुल्क

का० प्र० 5123—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के खंड (ए) के अधीन अधिसूचना सं० 79-कस्टम् 75/एफ०नं० 473/2/75/कस्टम्-7 दिनांक 18 जुलाई, 1975 के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा प्रसारित और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में जिला मेरठ के गाजियाबाद को भण्डागारण स्टेशन घोषित करता हूँ।

[अधिसूचना सं०-1-कस०/75/एफ० नं०-8-86-कस०/75]

के० एस० दिलीप सिंह, समाहर्ता

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CUSTOMS AND

CENTRAL EXCISE

Kanpur, the 8th October, 1975

CUSTOMS

S.O. 5123.—In exercise of powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), as delegated by the Ministry of Finance vide Notification No. 79-Customs/75/F. No. 473/2/75-Customs-VII dated 18th July, 1975, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I hereby declare Ghaziabad, District Meerut in the State of Uttar Pradesh, to be a warehousing station.

[No. 1-Cus/75/F. No. VIII-86-Cus/75.]

K. S. DILIP SINGH, Collector.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय पूर्ण अक्षय निधि के कोषपाल का कार्यालय)

गुड्डि-गल

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1975

का० प्र० 5124—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (भारतीय पूर्ण अक्षय निधि के कोषपाल का कार्यालय) की दिनांक 13 जून, 1975 की अधिसूचना संख्या एक० 1/1/73-टी०सी०ई०

की 2 अगस्त, 1975 भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3(II) पृष्ठ संख्या 2741 से 2778 में प्रकाशित की गई है का शुद्ध पत्र

पृष्ठ संख्या	क्रम संख्या	कालम संख्या	अणुद	शुद्ध
2747	मद्रास	7	1,26,475.99	1,26,475.00
2750	3	10	55.00	1,335.29
2757	8	8	288.00	3,288.00
2758	13	10	18,872.50	18,892.50
2760	18	12	(फ) के नीचे से टिप्पणी जोड़ दी जाये (म) यह रकम निम्नलिखित की शेषतक है:-	

अथशेष

12.00

400 रुपये के मूल्य

के 4 प्रतिशत व्याज वाले

महाराष्ट्र ऋण पत्र 1974

की परिशोधन प्राप्ति

जिन्हें 27 अगस्त, 1974

को चुका दिया गया था

400.00

412.00

(य) यह रकम 400 रुपये

के मूल्य के 6 प्रतिशत

व्याज वाले महाराष्ट्र

ऋण 1984 की लागत

की शेषतक है

2760	19	11	24.00	—
2762	26	3	4½ प्रतिशत व्याज वाला मद्रास ऋण 1976 पालिका के ऋण पत्र 7,000.00	4½ प्रतिशत व्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1976
2762	26	6	कालम 6 में दी गयी 26,29,300 रकम को अन्त में कालम 5 में पढ़ें।	
2762	26	8	1,45,489.37	1,65,489.37
2766	1(मद्रास)	3	कालम 3 के नीचे से जोड़ दिया जाये : 6 प्रतिशत व्याज वाला तमिलनाडु ऋण 1984	3,49,400.00
2767	3	9	9,000.00	3,000.00
2768	1(पश्चिम बंगाल)	6	—	98,352.00
2768	2	6	—	3,782.74
2769	1(मध्य प्रदेश)	7	766.18	10,766.18
2770	2	8	28,555.45	28,583.45
2770	3	8	62,521.99	62,522.99
2778	पंजाब और इसके सीचे दी गयी टिप्पणी की क्रम संख्या 1 के नीचे पढ़ा जाये। क्रम संख्या 1 के ऊपर पाँचवीं पढ़ा जाये और इसके 7,8,9,10,11 कालम में पढ़ा जाये।			

[सं० फ० 1/1/74-टी०सी०ई०]

म०ड० पाल, उपसचिव (पेन खर्चा)

(Department of Economic Affairs)
Office of the Treasurer of Charitable
Endowments for India
ERRATA

New Delhi, the 21st October, 1975

S.O. 5124—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Office of the Treasurer of Charitable Endowments for India) No. F. 1/1/75-TCE dated the 15th June, 1975, Published as S.O. 2416 in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated the 2nd August, 1975, at pages 2778 to 2799.

- Page 2780 Case Nos. 6 and 7, Column 6, Line, 13,
Read 'or' For 'of'.
- Page 2783 Madras
Case No. 1.
(i) Column 5, para (c), Read 'A parent'
For 'Aparent'
(ii) Column 9. (a) Line 51, Read 'U.T. 2'
For 'V.T.2'
(b) Line 57 and 58, Read '
'transferring' For
'transferring'.
- Page 2785 Case No. 3, Column 7, Read '80, 015.29'
For '81, 015.29'.
- Page 2786 Case No. 9. Column 2, Line 2, Read
'Teachers' For 'Teacher's'.
- Page 2787-88 (i) Case No. 13, Column 4, Line 18,
Read 'Co-op' For 'Corp'.
(ii) Maharashtra—Case No. 3, Column 11,
Insert '(s)' against the figure '414.00'.
- Page 2788 Case No. 5, Column 8, Read '2,520.00'
For '2,820.00'.
- Page 2789 Case No. 8, Insert (i) the following under
Columns 7—11.

7	8	9	10	11
(n) 3,006.00	3,288.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	285.12 2.88 288.00	3,000.00 (n) 6.00 3,006.00 3,006.00
				Represents— Opening Balance Redemption pro- ceeds of 4% B.P.T. Loan 1974-75 of Rs. 3,000/- repaid on 1-1-1975. Order of reinvestment are awaited.

- (ii) Case No. 9, Column, 8, Read '43, 188.24'
For '48, 188.24'.
- (iii) Case No. 10, Column 9, Read '14.70' For
'84.70' against 'Fee paid to Govt.'.
- Page 2790 Case No. 18, Column 11, (x) Line 7, Read
'27-8-1974' For '27-8-84'.
- Page 2793-94 (i) Case No. 28, Column 7, Read '1,080.00'
For '1,430.00'.
- (ii) Case No. 29, The words and figures under Columns 4-10 may be read as under :—

4	5	6	7	8	9	10
3% Conversion Loan 1946	49,100.00	50,300.00	3,772.50	..	3,772.50	..
3% Loan 1896-97	1,260.00					

Interest remitted 3,734.77
Fee paid to Govt. 37.73
3,772.50

- (iii) Madras—Case No. 1, Column 11, Lines 5 and 6, Read 'F, 5-15/68/(BSE-6)/U.T.2' For
'F, 5-15/68/(CBSE-6)/W.T.2'.
- (iv) Case No. 3.(a) Column 2, Line 2,
Read 'Chetty' For 'Cheety'.
(b) Column 9, Read '3,000.00'
For '9,000.00'.
(c) Column 11, Last line,
Read 'Source' For 'sources'
- (v) West Bengal—Case No. 2, Column 4, Insert '59,700.00' against
'5½ % West Bengal Loan 1983'.

4	5	6	7	8	9	10
Page 2795	Madhya Pradesh	(i) Case No. 1, Insert '40. 148. 74' under Column 6.				
		(ii) Case No. 3, Column 3, Lines 1 and 2, Read 'Governing' For 'concerning'				
		(iii) Case No. 4, (a) Column 6, Read '354.00' For '3,54.00'				
		(b) Column 11, Line 4, Read 'recovered' For 'recorded'				
Page 2796	Case No. 8, Column 5, Read '13.800.00' For '3,800.00'.					
Page 2799	(i) Case No. 12, Column 3, Line 2, Read 'Hindu' For 'Hindi'.					
	(ii) Pondicherry—Case No. 1,					
	(a) Delete '1,000.00' from Column 4 and insert it under Column 5.					
	(b) Insert '...' under Columns 7-10 against this fund.					

[No. F. 1/1/74-TCE]

M. D. PAL, Dy. Secy. & Ex-Officio Treasurer.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1975

का०आ० 5125.—केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ग) और धारा 12 की उपधारा (5) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा डा० जी० पी० सिंह, चेयरमैन, स्टेट फार्म्स कारपोरेशन प्राफ इंडिया लि०, नई दिल्ली को 13 नवम्बर, 1975 से प्रारम्भ होने वाली और 5 सितम्बर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये डा० जी० पार्थसारथी के के स्थान पर, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं० एक० 7/10/75-बी०प्रो०-I-1]

(Department of Banking)

New Delhi, the 13th November, 1975

S.O. 5125.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 12 read with sub-section (5) thereof and clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Dr. D. P. Singh, Chairman, State Farms Corporation of India Ltd., New Delhi to be the Director of the Central Board of the Reserve Bank of India for the period commencing on 13th November, 1975 and ending with 5th September, 1976, vice Dr. G. Parthasarathy.

[No. F. 7/10/75-BO. I-1.]

का० आ० 5126.—केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ग) और धारा 12 की उपधारा (5) के साथ पठित उक्तधारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री प्रकवर हैदरी, चेयरमैन, बीस्टर्न इंडिया मच कंपनी लि०, बम्बई को 13 नवम्बर, 1975 से प्रारम्भ होने वाली और 16 फरवरी, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये श्री सी०पी० श्रीवास्तव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[सं० एक० 7/10/75-बी०प्रो०-I-2]

S.O. 5126.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 12 read with sub-section (5) thereof and clause (c) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Shri Akbar Hydari, Chairman, Western India Match Co. Ltd., Bombay to be the Director of the Central Board of the Reserve Bank of India for the period commencing on 13th November, 1975 and ending with 16th February, 1976, vice Shri C. P. Srivastava.

[No. F. 7/10/75-BO. I-2]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1975

का०आ० 5127.—वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग की दिनांक 13 नवम्बर, 1975 की समसंख्यक अधिसूचना में नाम "डा० जी० पार्थसारथी" के स्थान पर नाम "श्री जी० पार्थसारथी" रखा जायेगा।

[सं० एक० 7/10/75-बी०प्रो०-I-1]

ल० व० कटारिया, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th November, 1975

S.O. 5127.—In the Ministry of Finance, Department of Banking Notification of even number dated the 13th November, 1975, the name "Dr. G. Parthasarathy" shall be substituted by the name "Shri G. Parthasarathi".

[No. F. 7/10/75-BO. I-1]

L. D. KATARIA, Director

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975

का०आ० 5128.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी०पी० चारी को 17 नवम्बर, 1975 से प्रारम्भ होकर 30 नवम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त करती है।

[सं० एक० 7/12/75-बी०प्रो०-I]

निर्मल सेन गुप्ता, सचिव

New Delhi, the 15th November, 1975

S.O. 5128.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby reappoints Shri V. V. Chari as a Deputy Governor of the Reserve Bank of India for the period commencing on 17th November, 1975 and ending with 30th November, 1975.

[No. F. 7/12/75-BO. I]

N. C. SEN GUPTA, Secy.

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975

क्रा०आ० 5129.—कृषि पुनर्वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 45) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 15 नवम्बर, 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करता है जिससे उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं० एफ० 14-2/74-ए०सी०]

अमल कुमार दल, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 15th November, 1975

S.O. 5129.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Act, 1975 (45 of 1975), the Central Government hereby appoints the 15th November, 1975 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 14-2/74-AC]

A. K. DUTT, Jr. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975

क्रा० आ० 5130.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में नवम्बर 1975 के दिनांक 7 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा विभाग

देयताएँ	रुपये	रुपये	आस्तियाँ	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	14,62,52,000		सोने का सिक्का और बुलियन :		
संचालन में नोट	6480,14,44,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,56,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ		
जारी किये गये कुल नोट		6494,76,96,000	विदेशी प्रतिभूतियाँ	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,53,000
			रुपये का सिक्का		10,09,51,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ		6180,40,92,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		
कुल देयताएँ		6494,76,96,000	कुल आस्तियाँ		6494,76,96,000

दिनांक : 11 नवंबर, 1975

धार० के० हजारी, उप गवर्नर

7 सितंबर 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वैश्व विभाग के कार्यकलाप का विवरण

विवरण	रुपये	विवरण	रुपये
चुकना पूंजी	5,00,00,000	नोट	14,62,52,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	5,06,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	4,97,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	84,79,75,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	385,52,77,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	निवेशों में रखा हुआ ऋण*	789,62,73,000
जमा राशियाँ :—		निवेश**	882,64,63,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	54,00,31,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	9,71,17,000	(ii) राज्य सरकारों को @	110,81,00,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	603,30,95,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को †	319,20,00,000
(ii) अनुसूचित राज्य	15,99,22,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को ‡	342,61,03,000
सहकारी बैंक		(iii) दूसरों को	13,15,06,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
सहकारी बैंक	1,63,99,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
(iv) अन्य बैंक	67,63,000	(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,59,74,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	13,13,51,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्निर्माण निगम को	86,70,00,000
(ग) अन्य	1255,19,99,000	(घ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,13,000
देय बिल	144,57,32,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण	
अन्य देयताएँ	795,31,60,000	और अग्रिम	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	94,52,95,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	
		से ऋण अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक का ऋण और अग्रिम	333,25,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/	
		डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य प्राप्तियाँ	348,50,80,000
रुपये	3899,42,21,000	रुपये	3899,42,21,000

*नकदी, आर्थिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

(a) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवर-ड्राफ्ट शामिल हैं।

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 68,40,00,000 रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

आर० के० हजारी, उप गवर्नर

दिनांक : 11 नवंबर, 1975

[फ० सं० 10 (1)/75-वी० प्रो 1]

च० व० मोरचन्दानी, सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 15th November, 1975

S. O. 5130.—An account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 7th day of November 1975

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	14,62,52,000		Gold Coin and Bullion :		
Notes in circulation	6480,14,44,000		(a) Held in India	182,52,56,000	
			(b) Held outside India	..	
Total notes issued		6494,76,96,000	Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total		304,26,53,000
			Rupee Coin		10,09,51,000
			Government of India		
			Rupee Securities		6180,40,92,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper .		..
Total Liabilities		6494,76,96,000	Total Asset		6494,76,96,000

R. K. HAZARI, Dy. Governor

Dated the 11th day of November, 1975.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 7th November, 1975

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
1	2	3	4
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	14,62,52,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	5,06,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	Small Coin	4,97,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Bills Purchased and Discounted :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(a) Internal	84,79,75,000
		(b) External
		(c) Government Treasury Bills	385,52,77,000
		Balances Held Abroad*	789,62,73,000
		Investments**	882,64,63,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Central Government
		(ii) State Governments@	110,81,00,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Bank†	319,20,00,000
Deposits :		(ii) State Co-operative Banks††	342,61,03,000
		(iii) Others	13,15,06,000
a) Government			
(i) Central Government	54,00,34,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(ii) State Governments	9,71,17,000	(a) Loans and Advances to :—	
		(i) State Governments	69,59,74,000
		(ii) State Co-operative Banks	13,13,51,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	86,70,00,000

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
(b) Banks			
(i) Scheduled Commercial Banks	603,30,95,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	15,99,22,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,63,99,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	94,52,95,000
(iv) Other Banks	67,63,000	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	333,25,56,000
(c) Others	1255,19,99,000	(b) Investment in bonds/ debentures issued by the Development Bank	
Bills Payable	144,57,32,000	Other Assets	348,50,80,000
Other Liabilities	795,31,60,000		
RUPEES	3899,42,21,000	RUPEES	3899,42,21,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 68,40,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 11th day of November, 1975.

R. K. Hazari, Dy. Governor,

[F 10(1)/75-BOI]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी

चण्डीगढ़, 23 जुलाई, 1975

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का० आ० 5131.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निधमावली, 1944

के नियम 5 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी० के० सेठ, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बजकटरी, चण्डीगढ़, एतद्वारा चण्डीगढ़ और फरीदाबाद के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप समाहर्ताओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निधमावली, 1944 के नियम 173-जी(4) के अधीन समाहर्ता में निहित अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता हूँ।

[अधिसूचना सं० 1/सी-ई/75(सी) सं० 4(16) 45 सी० ई० टी०/75]
बी० के० सेठ, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, CHANDIGARH

Chandigarh, 23rd July, 1975

CENTRAL EXCISES

S.O. 5131.—In exercise of the powers conferred upon me under rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, B. K. Seth, Collector of Central Excise Collectorate, Chandigarh hereby authorise the Deputy Collector of Central Excise, Chandigarh and Faridabad to exercise the powers vested in the Collector under Rule 173-G(4) of the Central Excise Rules, 1944.

[Notn. No. 1/CE/75 C. No. IV(16) 45-CET/75]

B. K. SETH, Collector.

वारिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य निरीक्षक, आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

कलकत्ता, 1 सितम्बर, 1975

का० आ० 5132.—भारत के राज्य व्यापार नियम लि०, 36 जनपथ, नई दिल्ली को अत्काइल बेजीन के लिए कुल 40,007 रुपये, मुख्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी (एम) 2698801/सी/एक्स एक्स/54/सी/39-40/टी० 1-4 दिनांक 13-3-75 सर्वश्री कुसुम प्रोडक्ट्स लि०, कलकत्ता के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ प्रदान किया गया था। अब सर्वश्री कुसुम प्रोडक्ट्स लि०, कलकत्ता ने लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों की अनुलिपि प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां उपयोग करने से पहले ही और किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत कराए बिना ही अम्पानस्थ हो गई हैं।

अपने तर्कों के समर्थन में आवेदकों ने मोटरी पब्लिक के सामने शपथ लेकर इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है और वह न तो उनके द्वारा रद्द किया गया, गिरवी रखा गया, हस्तांतरित किया गया और न उनकी ओर से किसी भी आय पत्र द्वारा किसी आय उद्देश्य या लाभ के लिए उपयोग किया गया है। आवेदक के मूल लाइसेंस की रद्द करने के लिए आवेदन

किया है जिसके बदले में उन्होंने अनुलिपि प्रतियों के लिए आवेदन किया है और इस बात के लिए सहमत होने हुए, वचन दिया है कि यदि मूल लाइसेंस बाद में पाया गया तो वह निर्णय प्राधिकारी को लौटा दिया जायेगा।

मैं संतुष्ट हूँ कि मूल लाइसेंस सं० पी/एम/2698801/सी/एक्स एक्स/54सी/39-40/डी० 1-4 दिनांक 13-3-75 अस्थायित्व हाँ गया है और निदेश देता हूँ कि इस अनुलिपि (सीमाशुल्क निकासी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों) आवेदक को जारी की जाएं। मूल लाइसेंस एतद्वारा रद्द किया जाता है।

[संख्या रेक्सप/03989 एल/47-ओ-डी'73/6/एल-15]

एम० के० मण्डल, उप-मुख्य नियंत्रक
कुल्ले संयुक्त मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE
OFFICE OF JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS
AND EXPORTS

ORDER

Calcutta, the 1st September, 1975

S.O. 5132.—The State Trading Corporation of India Ltd., 36, Janapath, New Delhi, were granted import licence No. P/M/2698801/C/XX/54/C/39-40/D. 1.4 dated 13-3-75 for Alkyl Benzene for a total value of Rs. 40,007/- with letter of authority on M/s. Kusum Products Ltd., Calcutta. M/s. Kusum Products Ltd., Calcutta have now applied for duplicate copy of the licence both customs purpose and exchange control copies on the ground that the original copies have been misplaced before utilisation and without having been registered with any customs authority.

In support of their contention the applicant have filed an affidavit sworn in before the Notary Public to the effect that the licence has not been utilised at all and the same has not been cancelled, pledged, transferred or handed over by them or on their behalf to any other party for any other purpose, consideration whatsoever. The applicant have made a request to cancel the original licence in lieu of which the duplicate copy has been applied for by them and agree and undertake to return the original licence, if traced later to the issuing authority.

I am satisfied that the original licence No. P/M/2698801/C/XX/54/C/39-40/D 1-4 dated 13-3-75 has been misplaced and direct that a duplicate licence (Customs and Exchange Control copies) be issued to the applicant. The original licence is hereby cancelled.

[No. Rexp/03989-L/47/O-D'73/V1/L-15]

S. K. MANDAL, Dy. Chief Controller

for Jt. Chief Controller

आदेश

कलकत्ता 26, सितम्बर, 1975

का० आ० 5133.—सर्वश्री के० डी० विश्वास एंड कं०, आर० आई० सी० इन्डस्ट्रियल इस्टेट, ब्लाक नं० 2 शेड नं० ए/18 बाणहुगली, कलकत्ता को 4,00,000 रुपये का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एम/1771426/सी/एक्स एक्स/52/सी/37-38 दिनांक 28 सितम्बर, 1974 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उग की मूल प्रति चोरी हो गई है। यागे यह बताया गया कि लाइसेंस सीमाशुल्क कार्यालय, कलकत्ता के पास पंजीकृत करवाया गया है और उग में शेष अग्रयुक्त 3,62,603.30 पैसे को छोड़कर 37,396.70 पैसे के लिए उस का आंशिक रूप से उपयोग कर लिया गया है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति चोरी हो गई है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं० पी/एम/1771426/सी/एक्स एक्स/52/सी/37-38 दिनांक 28-9-74 जिनमें अग्रयुक्त 3,62,603 रुपये है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति चोरी हो गई है निदेश देता हूँ कि आवेदक को उस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या : ए यू/35273/7/ए एम, 74/4/722]

ORDER

Calcutta, the 26th September, 1975

S.O. 5133.—M/s. K. D. Biswas & company, R.I.C. Industrial Estate, Block No. II, Shed No. A/18, Bonhooghly, Calcutta-35 were granted import lic. No. P/S/17714226/C/XX/52/C/37-38 dated 28-9-74 for Rs. 4,00,000/-. They have applied for duplicate customs purposes copy of the said licence on the ground that the original of the same has been stolen. It is further stated that the licence has been registered with the customs House, Calcutta and partly utilised for an amount of Rs. 37,396.70 & remains unutilised balance of Rs. 3,62,603.30P.

In support of this contention the applicant firm has filed an affidavit to the effect that the original customs purpose copy of the licence has been stolen. I am satisfied that the original custom purpose copy of the licence No. P/S/1771426/C/XX/52/C/37-38 dated 28-9-74 for unutilised balance of Rs. 3,62,603/- has been stolen and directed that a duplicate copy of the same should be issued to the applicant. The original custom purpose copy of the licence is cancelled.

[No. AU/35273/7/AM'74/IV/722.]

आदेश

का० आ० 5134.—सर्वे श्री के० डी० विश्वास एंड कं० आर० आई० सी० इन्डस्ट्रियल इस्टेट, ब्लाक नं० 2 शेड नं० ए/18 बाणहुगली कलकत्ता को 2,00,000 रुपये का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एम/1771427/आर/एम एल/52/सी/37-38 दिनांक 28-9-74 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस चोरी हो गया है। यागे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है और लाइसेंस के पूरे मूल्य (अर्थात् 2,00,000 रुपये) का उपयोग नहीं किया गया है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति चोरी हो गई है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं० पी/एम/1771427/आर/एम एल/52/सी/37-38 दिनांक 28-9-74 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति चोरी हो गई है निदेश देता हूँ कि आवेदक को उसकी अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या : ए यू/35273/7/ए एम 74/4/722]

ORDER

S.O. 5134.—M/s. K. D. Biswas & Company, R.I.C. Industrial Estate, Block No. II, shed No. A/18, Banhooghly, Calcutta 35 were granted import licence No. P/S/1771427/R/ML/52/C/37-38 dated 28-9-74 for Rs. 2,00,000/-. They have applied for duplicate customs purpose copy of the said licence on the ground that the original licence has been stolen. It is further stated that the original licence has not been registered with any custom authority and the full value of the licence (i.e. Rs. 200,000/-) remained unutilised.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit to the effect that the original customs purpose copy of the licence has been stolen. I am satisfied that the original customs purpose copy of the licence No. P/S/1771427/R/ML/52/C/37-38 dated 28-9-1974 has been stolen and directed that a duplicate copy of the same should be issued to the applicant. The original customs purpose copy of the licence is cancelled.

[No. AU/35273/7/A-M'74/IV/722]

आदेश

का० आ० 5135.—सर्वश्री के० जी० बिस्वास एंड कंपनी आर० आई० सी० इन्डस्ट्रियल इस्टेट, ब्लाक नं० 2 शेड नं० ए/18 बाणहुभी कलकत्ता की 2,00,000 रुपये का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एम/1771428/टी/ओ आर/52/सी/37-38 दिनांक 28-9-74 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुमति सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उसकी मूल प्रति चोरी हो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है और लाइसेंस के पूरे मूल्य (अर्थात् 2,00,000 रुपये) का उपयोग नहीं किया गया है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति चोरी हो गई है। संतुष्ट हैं कि लाइसेंस सं० पी/एम/1771428/आई/ओ आर/52/सी/37-38 दिनांक 28-9-74 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति चोरी हो गई है और निवेदन देता है कि आवेदक को उसी की अनुमति प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

[सं० ए. यू./35273/7/एम-एम-74/1/722]

के० पी नारायण, उप मुख्य नियंत्रक

ऊ से संयुक्त मुख्य नियंत्रक

ORDER

S.O. 5135.—M/s. K.D. Biswas & Company, R.J.C. Industrial Estate, Block No. II Shed No. A/18, Banhooghly, Calcutta-35 were granted import Lic. No. P/S/1771428/T/OR/52/C/37-38 dated 28-9-1974 for Rs. 2,00,000/-. They have applied for duplicate customs purpose copy of the said licence on the ground that the original of the same has been stolen. It is further stated that the original licence has not been registered with any customs authorities and the full value of the licence (i.e. Rs. 2,00,000/-) remained unutilised.

In support of this contention the applicant has filed an affidavit to the effect that the original custom purpose copy of the licence has been stolen. I am satisfied that the original customs purpose copy of the licence No. P/S/1771428/T/OR/52/C/37-38 dated 28-9-1974 has been stolen and directed that a duplicate copy of the same should be issued to the applicant. The Original Customs Purpose copy of the licence is cancelled.

[No. AU/35273/7/A-M-74/IV/722]

for Jt. Chief Controller

K. P. NARAYAN, Dy. Chief Controller

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975

का० आ० 5136.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नामी क्षेत्र (अर्थात् और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग)

की अधिसूचना सं० का० आ० 1550, तारीख 6 मई, 1975 द्वारा, उस अधिसूचना से उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में भूमियों का अर्जन करने के अपने आणय की सूचना दी थी;

और मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वांक रिपोर्ट पर विचार करने और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इसमें उपावध अनुसूची में वर्णित 1260.00 एकड़ (लगभग) अथवा 509.90 हेक्टेयर (लगभग) वाली भूमियां अर्जित की जानी चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 1260.00 एकड़ (लगभग) अथवा 509.90 हेक्टेयर (लगभग) वाली भूमियां अर्जित की जाती हैं।

2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांकों का निरीक्षण कलक्टर, सीधी (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1, कार्डमिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (राजस्थान अनुभाग) के कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) में किया जा सकेगा।

अनुसूची

जयंत खण्ड

(मिर्गौली कोयला क्षेत्र)

मध्य प्रदेश

डा० सं० रा०/27/75

31 जुलाई, 1975

सभी अधिकार

(जिसमें अर्जित भूमियां दर्शित हैं)

क्रम संख्या	ग्राम	तहसील	तहसील संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	मुरहबानी	मिर्गौली	205	सीधी	भाग	
2.	सयमाबाहू					
	राजाटोला	"	224	"	"	"
3.	निगाई	"	288	"	"	"
4.	मतीली	"	446	"	"	"

कुल क्षेत्र :- 1260.00 एकड़ (लगभग)

या :- 509.90 हेक्टेयर (लगभग)

मुरहबानी ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्याएं :-

1 (पी), 5 (पी), 6, 7 (पी), 8 (पी), 9 (पी), 10 (पी), 11, 12 (पी), 13, 14, 15, 16 (पी), 25 (पी), 26 (पी), 32 (पी), 33, 34 (पी) और 50 (पी)

सयमाबाहू राजाटोला ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्याएं :-

1 (पी), 2 (पी), 3 (पी), 4 (पी), और 5 (पी)।

निगाई ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्याएँ :-

109(पी), 111(पी), 113(पी), 114(पी), 153(पी), 154(पी),
155(पी), और 172(पी)।

मत्तौली ग्राम में अर्जित प्लॉट संख्याएँ :-

537 (पी), 538 (पी), 539(पी), 541 (पी), 569(पी),
570(पी), 571 से 574, 575(पी), 581(पी), 582(पी), 583(पी),
584(पी), 585(पी), 586 से 591, 592 (पी), 593, 594(पी) और
595 (पी)।

सीमा वर्णन :-

ए-बी लाइन निगाई ग्राम के प्लॉट सं० 111 से
होकर जाती है और 'बी' बिन्दु पर मिलती
है।

बी-सी-डी-ई-एफ-जी-
एच-आई लाइन निगाई ग्राम के प्लॉट सं० 111 से
होकर मत्तौली ग्राम के प्लॉट सं० 582,
583, 584, 585 और 584 से होकर मुरह-
बानी ग्राम के प्लॉट सं० 9, 10, 7 और 8 से
होकर और निगाई ग्राम के प्लॉट सं० 155,
113 और 114 से होकर जो खान और
खनिज (बिनियमन और विकास) अधिनियम
की धारा 17 के अधीन 373.00 एकड़
वाले क्षेत्र की आंशिक सामान्य सीमा भी है,
जाती है और 'आई' बिन्दु पर मिलती है।

आई-जे-के लाइन निगाई ग्राम के प्लॉट सं० 114, 154
और 153 से होकर मुरहबानी ग्राम के प्लॉट
संख्या 1 से होकर जाती है और 'के' बिन्दु
पर मिलती है।

के-एल

लाइन मुरहबानी ग्राम से होकर जो प्लॉट
सं० 4 और 35 की उत्तरी सीमा तथा प्लॉट
सं० 31 (नाले की आंशिक उत्तरी
सीमा) भी है, जाती है और 'एल' बिन्दु पर
मिलती है।

एल-एम

लाइन मुरहबानी ग्राम के प्लॉट सं० 32,
26, 25, 12 और 16 से होकर, सरसाबाह
राजाटोला ग्राम के प्लॉट सं० 5, 4, 3, 2
और 1 से होकर जाती है और 'एम' बिन्दु
पर मिलती है।

एम-एन

लाइन सरसाबाह राजाटोला और दुधीचुवा
ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-
साथ जाती है और 'एन' बिन्दु पर मिलती है।

एन-ओ-पी

लाइन मत्तौली ग्राम की प्लॉट सं० 594,
595, 592, 537, 538 और 539 से
होकर जाती है और 'पी' बिन्दु पर मिलती है।

पी-ए

लाइन मत्तौली ग्राम के प्लॉट सं० 539 की
आंशिक उत्तरी सीमा के साथ-साथ प्लॉट
सं० 541, 570, 569, 575 और 581
से होकर, निगाई ग्राम के प्लॉट सं० 111,
172 109 और पुनः 111 से होकर,
जो खान और खनिज (बिनियमन और
विकास) अधिनियम की धारा 17 के
अधीन अर्जित 3417.00 एकड़ के क्षेत्र की
आंशिक सामान्य सीमा भी है, जाती है और
आरंभ बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

[सं० 4(15)/74-सी 5/सी ई एल]

एस० आर० ए० रिजबी, उप सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, 15th November, 1975

S.O. 5136.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Department of Coal) No. S.O. 1550 dated the 6th May, 1975 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Madhya Pradesh is satisfied that the lands measuring 1260.00 acres (approximately) or 509.90 hectares (approximately), described in the scheduled appended hereto, should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 1260.00 acres (approximately) or 509.90 hectares (approximately) described in the said schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Sidhi (Madhya Pradesh) or in the Office of the Coal Collector, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the National Coal Development Corporation Ltd. (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

Jayant Block

(Singrouli Coalfield)

(Madhya Pradesh)

Drg. No. Rev/27/75

Dated 31-7-1975

All Rights

(Showing lands acquired)

Serial Number	Village	Tahsil	Tahsil Number	District	Area	Remarks
1.	Murhbani	Singrauli	205	Sidhi		Part
2.	Sarsabah Raja Tola	"	224	"		"
3.	Nigai	"	283	"		"
4.	Matouli	"	446	"		"

Total Area :—1260.00 acres (approximately)

or :— 509.90 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Murhbani :—

1 (p), 5(P), 6,7(P), 8(P), 9(P), 10(P), 11, 12(P), 13, 14, 15, 16(P), 25(P), 26(P), 32(P), 33, 34 & 59.

Plot numbers acquired in village Sarsabah Rajatola :—

1(P), 2(P), 3(P), 4(P), & 5(P).

Plot numbers acquired in village Nigai :—

109(P), 111(P), 113(P), 114(P), 153(P), 154(P), 155(P) & 172 (P).

Plot numbers acquired in village Matouli :—

537(P), 538(P), 539(L), 541(P), 569(P), 570(P), 571 to 574, 575(P), 581(P), 582(P), 583(P), 584(P), 585(P), 586 to 591, 592(P), 593, 594(P), & 595 (P).

BOUNDARY DESCRIPTION :—

A-B line passes through plot no 111 of village Nigai and meets at point 'B'.

B-C-D-E-G-H-I lines pass through plot no. 111 of village Nigai through plot nos. 582, 583, 584, 585 and 584 of village Matouli through plot nos. 9, 10, 7 and 8 of village Murhbani through plot nos. 155, 113 and 114 of village Nigai which is also the part common boundary of the area of 373.00 acres u/s 17 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, and meets at point 'I'.

J-K lines pass through plot nos. 114, 154 and 153 of village Nigai, through plot no. 1 of village Murhbani and meets at point 'K'.

K-L line passes through village Murhbani which is also the northern boundary of plot nos. 4 and 35 and part northern boundary of plot no. 31 (part northern boundary of Nala) and meets at point 'L'.

L-M line passes through plot nos. 32, 26, 25, 12 and 16 of village Murhbani, through plot nos. 5, 4, 3, 2 and 1 of village Sarsabah Rajatola and meets at point 'M'.

M-N line passes along the part common boundary of villages Sarsabah Rajatola and Doudhichuwa and meets at point 'N'.

N-P lines pass through plot nos. 594, 595, 592, 537, 538 and 539 of village Matouli and meet at point 'P'.

P-A line passes along the part northern boundary of plot No. 539 through plot nos. 541, 570, 569, 575 and 581 of village Matouli through plot nos. 111, 172, 109 and again 111 of village Nigai, which is also the part common boundary of Area of 3417.00 acres acquired u/s 17 of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, and meets at starting point 'A'.

[No. 4(15)/74-C5/CEL]

S. R. A. RIZVI, Dy. Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1975

का० आ० 5137.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होती है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में अंकलेश्वर 'जे' से कूप नं. 178 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों की बिछाने के प्रयोजन के लिये एन्व्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्द्वारा घोषित किया है ।

यद्यपि कि उक्त भूमि में हिंसक कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आश्रय मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आश्रय करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० अंकलेश्वर 'जे' से कूप नं० 178 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात	जिला : बरोच	तालुका : अंकलेश्वर			
गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	ए आर ई	सेन्टी-
अडोल	369	0	03	38	
	370	0	05	07	
	301	0	20	54	
	300	0	18	85	

[सं० 12016/11/75-एल एण्ड एल]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 14th November, 1975

S.O. 5137.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. Ankleshwar 'J' to Well No. 178 in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the RIGHT OF USER in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from Well No. Ankleshwar—'J' to well No. 178

State : Gujarat	District : Broach	Taluka : Ankleshwar			
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare	
ADOL	369	0	03	38	
	370	0	05	07	
	301	0	20	54	
	300	0	18	85	

[No. 12016/11/75-L & L

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1975

का० आ० 5138.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3428 तारीख 17-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों की बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था ।

और यतः मक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और

प्राकृतिक गैस, प्रायोग में सभी, संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के-165 से सी० टी० एफ० कालोल तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : गांधीनगर/मेहसाना तालुका : गांधी-नगर और कालोल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेण्टी-ऐर
सेरथा	1000	0	04	75
	1001/2	0	05	70
	1002/2	0	06	37
	1003	0	07	80
	1004/2	0	01	00
	कार्ट ट्रैक	0	00	75
	1005	0	10	43
धानाज	137/1	0	05	25
	135	0	24	25
	133	0	01	00
	134	0	11	25
	128	0	09	00
	129	0	01	35
	127	0	08	05
	103	0	33	58
	102	0	08	05
	101	0	19	20
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	108	0	01	65
	कार्ट ट्रैक	0	01	00
	72	0	06	00
	71	0	16	65
	47	0	11	34
	46	0	05	70
	50	0	13	50
	53	0	00	75
	51	0	03	00
	52	0	06	30
	57	0	06	30

[सं० 12016/9/74-एल एण्ड एल/5]

New Delhi, the 17th November, 1975

S.O. 5138.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3428 Dated 27-12-74 under sub-section (I) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

108 GI/75—5

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from K-163 to CTF KALOL

State : Gujarat		District : Gandhinagar/ Taluka : Mehsana Gandhinagar & KALOL		
Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
SERTHA	1000	0	04	75
	1001/2	0	05	70
	1002/2	0	06	37
	1003	0	07	80
	1004/2	0	01	00
	Cart-track	0	00	75
	1005	0	10	43
DHANAJ	137/1	0	05	25
	135	0	24	25
	133	0	01	00
	134	0	11	25
	128	0	09	00
	129	0	01	35
	127	0	08	05
	103	0	33	58
	102	0	08	05
	101	0	19	20
	Cart-track	0	01	00
	108	0	01	65
	Cart-track	0	01	00
	72	0	06	00
	71	0	16	65
	47	0	11	34
	46	0	05	70
	50	0	13	50
	53	0	00	75
	51	0	03	00
	52	0	06	30
	57	0	06	30

[No. 12016/9/74-L & L/V]

का० प्रा० 5139.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पत्तन से उत्तर प्रवेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्व्यावृद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रजित करना आवश्यक है;

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, सलाया-कोयाली/मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, "डोली"-33-बी हरिहर सोसाइटी, राजकोट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची		
तालुका : विरामगाम	जिला : अहमदाबाद	गुजरात : राज्य
गांव	सर्वेक्षण नं०	तक
		एच ए वर्गमील
विरामगाम	1233	0-12-25
	1231	0-28-90
हंसलपुर	55	0-07-35
सुरेश्वर		

[सं० 12017/1/75-एल० एण्ड एल०]

S.O. 5139.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto :

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali/Mathura Pipeline Project, "DOLI" 33-B Harihar Society, Rajkot.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Taluka : Viramgam	District : Ahmedabad	Gujarat State
Village	Survey No.	Extent
		H.A. Sq. M.
VIRAMGAM	1233	0—12—25
	1231	0—28—90
HANSALPUR	55	0—07—35
SURESHVAR		

[No. 12017/1/75-L & L]

का० भा० 5140.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर कूप नम्बर 46 से रुद्रसागर कूप नम्बर 30 तक की पाइपलाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में अर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

यतः, अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार, अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप अथवा प्रमण्डल पदाधिकारी शिवसागर असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रुद्रसागर कूप नम्बर 46 से रुद्रसागर कूप नम्बर 30 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुक : नगर-महल
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टेयर एर सेन्टी-एर
शिवसागर टाउन	5941 ख	0 0 67
	6390 ख	0 4 01
	6496 ख	0 0 13
	5942 ख	0 4 55
	5944 ख	0 3 21
	5945 ख	0 1 87
	6001 ख	0 2 27
	6044 ख	0 0 27
	6002 ख	0 4 15
	6003 ख	0 2 14
	6053 ख	0 6 42
	6054 ख	0 5 89
	6055 ख	0 7 63
शिवसागर टाउन	6058 ख	0 1 47
	6059 ख	0 1 61
	6385 ख	0 2 01
	6388 ख	0 2 94
	6391 ख	0 2 94
	6392 ख	0 1 47
	6046 ख	0 0 80
	6137 ख	0 5 35
	6318 ख	0 7 22
	6321 ख	0 4 41

[सं० 12020/4/75-एल० एण्ड एल०/1]

S.O. 5140.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar Well No. 46 to Rudrasagar Well No. 30 in Sibsagar Dist., Assam, Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar Well No. 46 to Rudrasagar Well No. 30

State : Assam	District : Sibsagar	Taluk : Nagarmahal		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
SIBSAGAR TOWN	5941 Kha	0	0	67
	6390 Kha	0	4	01
	6496 Kha	0	0	13
	5942 Kha	0	4	55
	5944 Kha	0	3	21
	5945 Kha	0	1	87
	6001 Kha	0	2	27
	6044 Kha	0	0	27
	6002 Kha	0	4	15
	6003 Kha	0	2	14
	6053 Kha	0	6	42
	6054 Kha	0	5	89
	6055 Kha	0	7	63
	6058 Kha	0	1	47
	6059 Kha	0	1	61
	6385 Kha	0	2	01
	6388 Kha	0	2	94
	6391 Kha	0	2	94
	6392 Kha	0	1	47
	6046 Kha	0	0	80
	6137 Kha	0	5	35
	6318 Kha	0	7	22
	6321 Kha	0	4	41

[No. 12020/4/75-L & L/1]

क्र० भा० 5141.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर जी० जी० एस० नम्बर 1 से रुद्रसागर कूप नम्बर 38 तक की पाइप लाइन 1 के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एम्पायर्स अधिनियम में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

यतः, अधिपेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार, अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है ;

उक्त भूमि में हितवादी कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप प्रमण्डल पदाधिकारी शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त ।

अनुसूची

रुद्रसागर जी० जी० एस० नम्बर 1 से रुद्रसागर कूप नम्बर 38 तक की पाइपलाइन

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुक : मैतकाबोनगांव
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर एर सेन्टीएर
पठलियाल	261ख	0 1 61
	262ख	0 0 67
	308ख	0 0 67
	310ख	0 0 67
	354ख	0 0 80
	311ख	0 0 67
	312ख	0 0 67
	358ख	0 0 67
	313ख	0 1 34
	314ख	0 1 61
	315ख	0 1 87
	316ख	0 2 41
	357ख	0 0 67
	259ख	0 0 67
	350ख	0 2 41
	355ख	0 0 40
	353ख	0 0 67
	517ख	0 2 54
	352ख	0 0 67
	351ख	0 2 41
	521ख	0 1 74
	522ख	0 1 34
	547ख	0 2 01

[सं० 12020/4/75-एस० तथा एल०-2]

S.O. 5141.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar G.G.S. No. 1 to Rudrasagar Well No. 38 in Sibsagar Dist., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar GGS No. 1 to Rudrasagar Well No. 38

State : Assam	District : Sibsagar		Taluk : Meteka Bongaon	
Village	Survey No.	Hec- tor	Are	Cent- tiar
PATHALIAL	261 Kha		1	61
	262 Kha	0	0	67
	308 Kha	0	0	67
	310 Kha	0	0	67
	354 Kha	0	0	80
	311 Kha	0	0	67
	312 Kha	0	0	67
	358 Kha	0	0	67
	313 Kha	0	1	34
	314 Kha	0	1	61
	315 Kha	0	1	87
	316 Kha	0	2	41
	357 Kha	0	0	67
	259 Kha	0	0	67
	350 Kha	0	2	41
	355 Kha	0	0	40
	353 Kha	0	0	67
	517 Kha	0	2	54
	352 Kha	0	0	67
	351 Kha	0	2	41
	521 Kha	0	1	74
	522 Kha	0	1	34
	547 Kha	0	2	01

[No. 12020/4/75-L & L/II]

का०आ० 5142—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर कूप नम्बर 75 से रुद्रसागर डी०डी० पस नम्बर 3 तक की पाइप लाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः, अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप द्वाारा प्रमण्डल पदाधिकारी शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रुद्रसागर कूप नम्बर 75 से रुद्रसागर डी० डी० एस नम्बर 3 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुक : मेटका बोंग-गाँव

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टेयर पेरे	सेन्टी- पेरे
सलगुरिया	261 ख	0	2 54
	262 ख	0	3 21
	201 ख	0	7 09
	202 ख	0	0 54
	260 ख	0	9 23

[सं० 12020/4/75-एल० तथा एल०/3]

S.O. 5142.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar AcII No. 75 to Rudrasagar G.G.S. No. 3 in Sibsagar dist., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar Well No. 75 to Rudrasagar G.G.S. No. 3

State: Assam	Dist: Sibsagar	Taluk: Meteka Bongaon		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Salaguria Gaon	261/Kha	0	2	54
	262/Kha	0	3	21
	201/Kha	0	7	09
	202/Kha	0	0	54
	260/Kha	0	9	23

[No. 12020/4/75-L&L/III]

का० आ० 5143.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर कूप नम्बर 26 से रुद्रसागर कूप नम्बर 67 तक की पाइप लाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आशेष अथवा प्रमुख पदाधिकारी, मिथमागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

रुद्रसागर कूप नम्बर 26 से रुद्रसागर कूप नम्बर 67 तक की पाइप लाइन।

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुका : मेतका	ग्रामगांव	
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐं०रे०	सें०तो०ऐं०रे०
1	2	3	4	5
रूपलिविल	405 घ	0	0	27
	404 घ	0	0	94
	403 घ	0	1	61
	402 घ	0	1	61
	401 घ	0	1	61
	400 घ	0	1	61
	399 घ	0	1	61
	398 घ	0	1	61
	397 घ	0	1	61
	396 घ	0	1	61
	395 घ	0	1	61
	394 घ	0	1	61
	393 घ	0	1	61
	392 घ	0	1	61
	391 घ	0	1	20
	390 घ	0	0	94
	388 घ	0	0	94
	387 घ	0	1	20
	386 घ	0	1	61
	385 घ	0	1	61
	384 घ	0	1	61
	383 घ	0	1	61
	382 घ	0	1	61
	381 घ	0	1	61
	380 घ	0	1	61
	379 घ	0	1	61

1	2	3	4	5
	378 घ	0	1	61
	377 घ	0	1	20
	376 घ	0	1	61
	375 घ	0	1	61
	374 घ	0	1	61
	373 घ	0	1	61
	372 घ	0	1	61
	371 घ	0	1	61
	370 घ	0	1	61
	369 घ	0	1	61
	368 घ	0	1	61
	367 घ	0	1	61
	366 घ	0	1	61
	365 घ	0	0	94
	349 ख	0	9	77
	348 ख	0	1	87
	324 ख	0	0	27
	325 ख	0	1	74
	326 ख	0	1	61
	327 ख	0	2	94
	328 ख	0	1	34
	329 ख	0	4	55
	330 ख	0	1	47
	331 ख	0	1	87

[सं० 12020/4/75-एल० तथा एल०/IV]

S.O. 5143.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar Well No. 26 to Rudrasagar Well No. 67 in Sibsagar Dist., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in lands Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Subsagar. Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar Drill Site 26 to 67

State: Assam Dist: Sibsagar Taluk: Meteka Bongaon

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Rupahibil	405/Gha	0	0	27
	404/Gha	0	0	94
	403/Gha	0	1	61
	402/Gha	0	1	61
	401/Gha	0	1	61
	400/Gha	0	1	61
	399/Gha	0	1	61
	398/Gha	0	1	61
	397/Gha	0	1	61
	396/Gha	0	1	61
	395/Gha	0	1	61
	394/Gha	0	1	61
	393/Gha	0	1	61
	392/Gha	0	1	61
	391/Gha	0	1	20
	390/Gha	0	0	94
	388/Gha	0	0	94
	387/Gha	0	1	20
	386/Gha	0	1	61
	385/Gha	0	1	61
	384/Gha	0	1	61
	383/Gha	0	1	61
	382/Gha	0	1	61
	381/Gha	0	1	61
	380/Gha	0	1	61
	379/Gha	0	1	61
	378/Gha	0	1	61
	377/Gha	0	1	20
	376/Gha	0	1	61
	375/Gha	0	1	61
	374/Gha	0	1	61
	373/Gha	0	1	61
	372/Gha	0	1	61
	371/Gha	0	1	61
	370/Gha	0	1	61
	369/Gha	0	1	61
	368/Gha	0	1	61
	367/Gha	0	1	61
	366/Gha	0	1	61
	365/Gha	0	0	94
	349/Kha	0	9	77
	348/Kha	0	1	87
	324/Kha	0	0	27
	325/Kha	0	1	74
	326/Kha	0	1	61
	327/Kha	0	2	94
	328/Kha	0	1	34
	329/Kha	0	4	55
	330/Kha	0	1	47
	331/Kha	0	1	87

[No. 12020/4/75-L&L/IV]

का० आ० 5144—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर कूप नम्बर 25 से रुद्रसागर कूप नम्बर 38 तक की पाइप लाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तथा एवं प्राकृतिक गैस आयाम द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अतुल्य में वजित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणव्य एतद्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप अथवा प्रमण्डल पत्राधिकारी से शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई अतिगत हो या किसी बिधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रुद्रसागर कूप नम्बर 25 से रुद्रसागर कूप नम्बर 38 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुक : भेतका बोनगांव			
ग्राम	सर्वे नम्बर	हैक्टर	ऐ०रे०	से०तो०ऐ०रे०	
भतियापार	13 क	0	7	63	
	11 ख	0	1	07	
	48 ख	0	17	53	
	10 ख	0	2	27	
	42 ख	0	19	53	
	361 ख	0	4	55	
	374 ख	0	6	02	
	377 ख	0	9	36	
	378 ख	0	17	26	
	362 ख	0	2	81	
	362 ख	0	5	75	
	371 ख	0	1	47	
	372 ख	0	1	07	
	373 ख	0	7	22	
	388 ख	0	1	47	

[सं० 12020/4/75-एल०एन०एल०/5]

S.O. 5144.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar Well No. 25 to Rudrasagar Well No. 38 in Sibsagar Dist., Assam, Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed thereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar Well No. 25 to Rudrasagar Well No. 38

State: Assam District: Sibsagar Taluk: Metekabongaon

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bhatiapar	13 Ka	0	7	63
	11 Kha	0	1	07
	48 Kha	0	17	53
	10 Kha	0	2	27
	42 Kha	0	19	53
	361 Kha	0	4	55
	374 Kha	0	6	02
	377 Kha	0	9	36
	378 Kha	0	17	26
	362 Kha	0	2	81
	362 Gha	0	5	75
	371 Kha	0	1	47
	372 Kha	0	1	07
	373 Kha	0	7	22
	388 Kha	0	1	47

[No. 12020/4/75-L&L/V]

का० आ० 5145.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर कूप नम्बर 25 से रुद्रसागर कूप नम्बर 38 तक की पाइप लाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

यतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप भ्रवर प्रमण्डल पदाधिकारी से शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रुद्रसागर कूप नम्बर 25 से रुद्रसागर कूप नम्बर 38 तक की पाइप लाइन

राज्य: असम जिला: शिवसागर तालुका: मेटका बोनगाँव

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सें तो ऐरे
पथलियाल	539 ख	0	3	61
	540 ख	0	7	22
	577 ख	0	2	01
	541 ख	0	2	14
	578 ख	0	2	81

[सं० 12020/4/75-एल० तथा एल०/6]

S. O. 4145.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar Well No. 25 to Rudrasagar Well No. 38 in Sibsagar Dist., Assam, Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar Well No. 25 to Rudrasagar Well No. 38

State: Assam District: Sibsagar Taluk: Metekabongaon

Village	Survey No.	Hector	Are	Centiare
Pathalial	539 Kha	0	3	61
	540 Kha	0	7	22
	577 Kha	0	2	01
	541 Kha	0	2	14
	578 Kha	0	2	81

[No. 12020/4/75-L&L/VI]

का० आ० 5246.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर कूप नम्बर 53 से रुद्रसागर कूप नम्बर 23 तक की पाइप लाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

यतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप भ्रवर प्रमण्डल पदाधिकारी से शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रुद्र सागर कूप नम्बर 53 से रुद्र सागर कूप नम्बर 23 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुक : मेतकाबोनगांव			
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेंटीऐरे	
भतियापार	230 ख	0	1	47	
	238 ख	0	2	68	
	239 ख	0	1	74	
	240 ख	0	1	47	
	299 ख	0	1	74	
	298 ख	0	0	80	
	265 ख	0	5	89	
	295 ख	0	5	35	
	294 ख	0	1	20	
	293 ख	0	1	07	
	264 ख	0	0	80	

[सं० 12020/4/75-एल० तथा एल०/7]

S.O. 5146.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar Well No. 53 to Rudrasagar Well No. 23 in Sibsagar Distt., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission,

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar Well No. 53 to Rudrasagar Well No. 23

State: Assam District: Sibsagar Taluk: Metekabongaon

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiares
Bhatiaapar	230/Kha	0	1	47
	238/Kha	0	2	68
	239/Kha	0	1	74
	240/Kha	0	1	47
	299/Kha	0	1	74
	298/Kha	0	0	80
	265/Kha	0	5	89
	295/Kha	0	5	35
	294/Kha	0	1	20
	293/Kha	0	1	07
	264/Kha	0	0	80

[No. 12020/4/75-L&L/VII]

का० आ० 5147.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्र सागर कूप नम्बर 81 से रुद्र सागर जी०जी० एस० नम्बर 2 तक की पाइप लाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों

के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

यतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप अथवा प्रमण्डल पदाधिकारी से रुद्र सागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

रुद्र सागर कूप नम्बर 81 से रुद्र सागर जी०जी० एस० नम्बर 2 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुक : मेतकाबोनगांव			
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेंटीऐरे	
रुपलिवील	675 च	0	0	80	
	675 ग	0	4	18	
	678 ख	0	2	01	
	676 क	0	21	94	

[सं० 12020/4/75-एल० तथा एल०/8]

S.O. 5147.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar Well No. 81 to Rudrasagar G.G.S. No. 2 in Sibsagar Dist., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar Well No. 81 to Rudrasagar GGS No. 2

State: Assam District: Sibsagar Taluk: Metekabongaon

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiares
Rupahibil	675 Cha	0	0	80
	675 Ga	0	4	18
	678 Kha	0	2	01
	676 Ka	0	21	94

[No. 12020/4/75-L&L/VIII]

का० आ० 5148.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गेलिकी जी०जी०एस० नम्बर 2 से रुद्र-सागर लकवा ट्रंक पाइप लाइन का जंक्शन पइन्ट तक की पाइप लाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्जित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप प्रवर प्रमण्डल पदाधिकारी से शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

गेलिकी जी०जी०एस० नम्बर 2 से रुद्रसागर लकवा ट्रंक पाइप लाइन का जंक्शन पइन्ट तक की पाइप लाइन।

राज्य : असम जिला : शिवसागर तालुक : आठखेल

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेंटीऐरे
बलाखरीया वाम गांव	204 ख	0	4	55
	207 ख	0	17	53
	211 ख	0	5	35
	390 ख	0	0	94
	392 ख	0	4	82
	387 ख	0	9	63
	386 ख	0	3	75
	386 घ	0	9	23
	421 ख	0	7	76
	536 ख	0	6	56
	532 ख	0	12	58
	552 ख	0	4	95
	554 ख	0	1	20
	517 ख	0	1	47
	553 ख	0	0	40
	385 ख	0	5	35
	423 ख	0	17	93
	1228 ख	0	3	61
	1315 ख	0	2	94
	549 ख	0	4	55
	556 ख	0	4	95
	557 ख	0	2	01
	1224 ख	0	9	10
	1310 ख	0	4	55
	1474 ख	0	0	94
	819 ख	0	0	67
	821 ख	0	2	54
	828 ख	0	14	05

ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेंटी ऐरे
	1224 ख	0	6	29
	822 ख	0	4	41
	1021 ख	0	0	80
	1022 ख	0	8	70
	1039 ख	0	10	17
	1038 ख	0	8	16
	1206 ख	0	8	29
	1207 ख	0	11	10
	1208 ख	0	0	67
	1227 ख	0	2	54
	1226 ख	0	3	48
	1467 ख	0	2	27
	1230 ख	0	2	94
	1313 ख	0	2	94
	1312 ख	0	5	35
	1311 ख	0	3	75
	1470 ख	0	4	55
	1489 ख	0	3	21
	1329 ख	0	3	88
	1324 ख	0	4	41
	1325 ख	0	10	70
	1330 ख	0	5	62
	1229 ख	0	5	22
	1331 ख	0	11	91
	1339 ख	0	15	92
	1341 ख	0	6	69
	1475 ख	0	4	68
	1473 ख	0	0	13
	1343 ख	0	4	01
	1468 ख	0	4	95
	1469 ख	0	6	96
	1488 ख	0	4	01
	1539 ख	0	4	01
	212 ख	0	2	54
	550 ख	0	6	02
	1657 ख	0	3	81
	542 ख	0	0	27
	544 ख	0	2	41
	820 ख	0	5	35
	1641 ख	0	0	80
	823 ख	0	2	94

[सं० 12020/4/75-एल० तथा एल०/9]

S.O. 5148.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Geleky GGS No. 2 to Junction Point at Rudrasagar Lakwa Trunk pipeline in Sibsagar Dist., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Galeky GGS No. 2 to Junction Point at Rudrasagar Lakwa Trunk Pipeline

State: Assam District: Sibsagar Mouza: Atkhel

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Dulakhoria Bam Gaon	204 Kha	0	4	55
	207 Kha	0	17	53
	211 Kha	0	5	35
	390 Kha	0	0	94
	392 Kha	0	4	82
	387 Kha	0	9	63
	386 Kha	0	3	75
	386 Gha	0	9	23
	421 Kha	0	7	76
	536 Kha	0	6	56
	532 Kha	0	12	58
	552 Kha	0	4	95
	554 Kha	0	1	20
	517 Kha	0	1	47
	553 Kha	0	0	40
	385 Kha	0	5	35
	423 Kha	0	17	93
	1228 Kha	0	3	61
	1315 Kha	0	2	94
	549 Kha	0	4	55
	556 Kha	0	4	95
	557 Kha	0	2	01
	1222 Kha	0	9	10
	1310 Kha	0	4	55
	1474 Kha	0	0	94
	819 Kha	0	0	67
	821 Kha	0	2	54
	828 Kha	0	14	05
	1224 Kha	0	6	29
	822 Kha	0	4	41
	1021 Kha	0	0	80
	1022 Kha	0	8	70
	1039 Kha	0	10	17
	1038 Kha	0	8	16
	1206 Kha	0	8	29
	1207 Kha	0	11	10
	1208 Kha	0	0	67
	1227 Kha	0	2	54
	1226 Kha	0	3	48
	1467 Kha	0	2	27
	1230 Kha	0	2	94
	1313 Kha	0	2	94
	1312 Kha	0	5	35
	1311 Kha	0	3	75
	1470 Kha	0	4	55
	1489 Kha	0	3	21
	1329 Kha	0	3	88
	1324 Kha	0	4	41
	1325 Kha	0	10	70
	1330 Kha	0	5	62
	1329 Kha	0	5	22
	1331 Kha	0	11	91

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Dulakhoria Bam Gaon	1339 Kha	0	15	92
	1341 Kha	0	6	69
	1475 Kha	0	4	68
	1473 Kha	0	0	13
	1343 Kha	0	4	01
	1468 Kha	0	4	95
	1469 Kha	0	6	96
	1488 Kha	0	4	01
	1539 Kha	0	4	01
	212 Kha	0	2	54
	550 Kha	0	6	02
	1657 Kha	0	3	61
	542 Kha	0	0	27
	544 Kha	0	2	41
	820 Kha	0	5	35
	1641 Kha	0	0	80
	823 Kha	0	2	94

[No. 12020/4/75-L&L/IX]

का० प्रा० 5149.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गेलिकी जी० जी० एस० नम्बर 2 से रुद्र सागर लकवा ट्रंक पाइप लाइन का जंकसन पइन्ट तक की पाइप लाइन के बीच पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस उपयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करता आवश्यक है।

यतः अब पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप अथवा प्रमण्डल पदाधिकारी से शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह कथन भी करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

गेलिकी जी० जी० एस० नम्बर 2 से रुद्रसागर लकवा ट्रंक पाइप लाइन का जंकसन पइन्ट तक की—पाइप लाइन

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालू : जोकतली		
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेंटी ऐरे
मलागाँव	227ख	0	2	81
	288ख	0	1	87
	228ख	0	2	94
	229ख	0	1	07
	273ख	0	13	92
	278ख	0	6	02
	279ख	0	0	27

1	2	3	4	5
	280ख	0	7	09
	282ख	0	0	67
	283ख	0	2	54
	284ख	0	2	54
	286ख	0	3	61
	696ख	0	9	63
	287ख	0	3	61
	297ख	0	2	81
	289ख	0	2	01
	336ख	0	5	35
	341ख	0	1	07
	291ख	0	2	01
	292ख	0	0	54
	299ख	0	2	81
	962ख	0	1	87
	298ख	0	2	81
	302ख	0	2	01
	335ख	0	6	56
	303ख	0	2	81
	691ख	0	1	74
	304ख	0	2	81
	326ख	0	4	01
	305ख	0	2	81
	306ख	0	4	01
	308ख	0	3	88
	689ख	0	2	01
	327ख	0	1	34
	328ख	0	1	34
	338ख	0	12	71
	285ख	0	0	40
	340ख	0	4	95
	343ख	0	2	54
	669ख	0	8	29
	670ख	0	3	34
	671ख	0	14	72
	694ख	0	7	22
	695ख	0	2	41
	963ख	0	0	94

[सं० 120201/4/75-एल० तथा एल०/10]

S.O. 5149.—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Geleky G.G.S. No. 2 to junction point at Rudrasagar Lakwa Trunk pipeline in Sibsagar Dist., Assam, Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Geleky CGS No. 2 to Junction point at Rudrasagar Lakwa Trunk Pipeline.

State : Assam	District : Sibsagar	Taluk : Jocktali
Village	Survey No.	Hec-tare Arc Centiare
Mola Gaon	277 Kha	0 2 81
	288 Kha	0 1 87
	228 Kha	0 2 94
	229 Kha	0 1 01
	273 Kha	0 13 92
	278 Kha	0 6 02
	279 Kha	0 0 27
	280 Kha	0 7 09
	282 Kha	0 0 67
	283 Kha	0 2 54
	284 Kha	0 2 54
	286 Kha	0 3 61
	696 Kha	0 9 63
	287 Kha	0 3 61
	297 Kha	0 2 81
	289 Kha	0 2 01
	336 Kha	0 5 35
	341 Kha	0 1 07
	291 Kha	0 2 01
	292 Kha	0 0 54
	299 Kha	0 2 81
	962 Kha	0 1 87
	298 Kha	0 2 81
	302 Kha	0 2 01
	335 Kha	0 6 56
	303 Kha	0 2 81
	691 Kha	0 1 74
	304 Kha	0 2 81
	326 Kha	0 4 01
	305 Kha	0 2 91
	306 Kha	0 4 01
	308 Kha	0 3 88
	689 Kha	0 2 01
	327 Kha	0 1 34
	328 Kha	0 1 34
	338 Kha	0 12 71
	285 Kha	0 0 40
	340 Kha	0 4 95
	343 Kha	0 2 54
	669 Kha	0 8 29
	670 Kha	0 3 34
	671 Kha	0 14 72
	694 Kha	0 7 22
	695 Kha	0 2 41
	963 Kha	0 0 94

[No. 12020/4/75-L&L/X]

का०आ० 5150.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि रुद्रसागर जी० जी० एस० नं० 1 से लक्ष्मी जी० जी० एस० नं० 1 के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विद्यार्थी जानी चाहिये ।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में बंजित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार, अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है :

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप अथवा प्रमण्डल पदाधिकारी से शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

रुद्रसागर जी० जी० एस नम्बर 1 से लक्वा जी० जी० एस नम्बर 1 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुक : शिलाकूटी			
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेटी ऐरे	
घोराचोवा	622ग	0	4	01	
	641ख	0	1	07	
	642ग	0	0	94	
	623ख	0	0	27	
	559ग	0	2	94	
	639ख	0	2	41	
	624ख	0	0	27	
	640ख	0	2	54	
	627ख	0	1	20	
	625ख	0	0	94	
	626ख	0	6	56	
	643ख	0	9	77	
	637ख	0	2	94	
	637ङ	0	0	27	
	330ख	0	11	64	

[सं० 120201/4/75-एल० तथा एस० 11]

S.O. 5150.— whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar GGS1 to Lakwa GGS1 in Sibsagar Dist., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Rudrasagar GGS No. 1 to Lakwa GGS No.1

State : Assam	Dist : Sibsagar	Taluk : Silakauti			
Village	Survey No.	Hec-tare	Arer	Centi-are	
Ghorachowa	622/GA	0	4	01	
	641/Kha	0	1	07	
	642/Ga	0	0	94	
	623/Kha	0	0	27	
	559/Ga	0	2	94	
	639/Kha	0	2	41	
	624/Kha	0	0	27	
	640/Kha	0	2	54	
	627/Kha	0	1	20	
	625/Kha	0	0	94	
	626/Kha	0	6	56	
	643/Kha	0	9	77	
	637/Kha	0	2	94	
	637/Unga	0	0	27	
	330/Kha	0	11	64	

[No. 12020/4/75-L&L/XI]

का०आ० 5151.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गेलिकी जी० जी० एस नम्बर 2 से गेलिकी जी० जी० एस० नम्बर 1 तक की पाइप लाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में बंजित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप अथवा प्रमण्डल पदाधिकारी से शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह ही कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

गेलिकी जी० जी० एस० नम्बर 2 से गेलिकी जी० जी० एस० नम्बर 1 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुक : भाठखेल			
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेटी ऐरे	
भूतिया गांव	252ख	0	4	68	
	253ख	0	21	94	
	286ख	0	21	54	

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुक : आठखेल		
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	ऐरे	सेन्टीऐरे
चुतिया गांव (जारी)	237ख	0	4	82
	357ख	0	5	89
	311ख	0	16	06
	291ख	0	3	48
	292ख	0	1	20
	312ख	0	8	96
	348ख	0	6	96
	348घ	0	1	07
	350ख	0	1	07
	351ख	0	6	42
	356ख	0	1	20
	356ग	0	2	94
	494ख	0	16	06
	496ख	0	15	92
	497ख	0	9	77
	516ख	0	2	94
	516ग	0	0	13
	517ख	0	12	04
	518ख	0	22	08
	519ख	0	24	89
	520ख	0	5	35
	813ख	0	29	57
	849ख	0	6	29
	851ख	0	15	12
	881ख	0	0	27
	914ग	0	6	15
	935ग	0	6	02
	937ग	0	4	41
	938ग	0	4	01
	992ख	0	2	54
	938घ	0	1	74
	993ख	0	14	85
	1026ख	0	18	33
	1037ख	0	15	12
	1034ख	0	20	07
	358ख	0	0	40

[सं० 12020/4/75-एल० तथा एल०/12]

S.O. 5151.—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Geleki G.G.S. No. 2 to Geleki G.G.S. No. 1 in Sibsagar Dist., Assam. Pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE				
Pipeline from Geleki GGS No. 2 to GGS No. 1				
State : Assam	District : Sibsagar	Taluk : Athkhel		
Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Chutia Gaon	252 Kha	0	4	68
	253 Kha	0	21	94
	286 Kha	0	21	54
	287 Kha	0	4	82
	357 Kha	0	5	89
	311 Kha	0	16	06
	291 Kha	0	3	48
	292 Kha	0	1	20
	312 Kha	0	8	96
	348 Kha	0	6	96
	348 Gha	0	1	07
	350 Kha	0	1	07
	351 Kha	0	6	42
	356 Kha	0	1	20
	356 Ga	0	2	94
	494 Kha	0	16	06
	496 Kha	0	15	92
	497 Kha	0	9	77
	516 Kha	0	2	94
	516 Ga	0	0	13
	517 Kha	0	12	04
	518 Kha	0	22	08
	519 Kha	0	24	89
	520 Kha	0	5	35
	813 Kha	0	29	57
	849 Kha	0	6	29
	851 Kha	0	15	12
	881 Kha	0	0	27
	914 Ga	0	6	15
	935 Ga	0	6	02
	937 Ga	0	4	41
	938 Ga	0	4	01
	992 Kha	0	2	54
	938 Gha	0	1	74
	993 Kha	0	14	85
	1026 Kha	0	18	33
	1037 Kha	0	15	12
	1034 Kha	0	20	07
	358 Kha	0	0	40

[No. 12020/4/75-L&L/XII]

का० आ० 5152.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि शिवसागर कूप नम्बर 81 से खद-सागर जी० जी० एस० नम्बर 2 तक की पाइप लाइन के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपायध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप एवं प्रमाण्य पदाधिकारी से शिवसागर, असम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसाई की मार्फत।

अनुसूची

रुद्रसागर कूप नम्बर 81 से रुद्रसागर जी० जी० एस० नम्बर 2 तक की पाइप लाइन

राज्य : असम	जिला : शिवसागर	तालुक : मेतेका दोनगांव			
ग्राम	सर्वे नम्बर	हेक्टर	घेरे	सेन्टीघेरे	
लाहिगीया	346ख	0	2	81	
	426ख	0	0	27	
	425ख	0	1	34	
	424ख	0	8	96	
	423ख	0	1	20	
	347ख	0	2	54	
	348ख	0	0	13	
	283ख	0	1	47	
	282ख	0	1	61	
	281ख	0	1	61	
	280ख	0	1	74	
	279ख	0	1	74	
	429ख	0	1	34	
	410ख	0	1	34	
	428ख	0	1	34	
	352ख	0	1	61	
	353ख	0	2	68	
	368ख	0	2	01	

[सं० 12020/4/75-एल० तथा एन०/13]

टी० पी० सुब्रह्मन्यम, अधर सचिव

S.O. 5152.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Rudrasagar Well No. 81 to Rudrasagar GGS No. 2 in Sibsagar Dist., Assam, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, viz. the Sub-Divisional Officer, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline (Feeder Line) from Rudrasagar Well No. 81 to Rudrasagar GGS No. 2.

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Metekabongaon

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Lahingia	346 Kha	0	2	81
	426 Kha	0	0	27
	425 Kha	0	1	34
	424 Kha	0	8	96
	423 Kha	0	1	20
	347 Kha	0	2	54
	348 Kha	0	0	13
	283 Kha	0	1	47
	282 Kha	0	1	61
	281 Kha	0	1	61
	280 Kha	0	1	74
	279 Kha	0	1	74
	429 Kha	0	1	34
	410 Kha	0	1	34
	428 Kha	0	1	34
	352 Kha	0	1	61
	353 Kha	0	2	68
	368 Kha	0	2	01

[No. 12020/4/75-L&L/XIII]

T.P. SUBRAHMANYAM, Under Secy.

(परमाणु ऊर्जा विभाग)

मुम्बई नवम्बर 13, 1975

का० आ० 5153.— केन्द्रीय सरकार सरकारी स्थान (अनाधिकृत अधिकारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और निवेश देती है, कि वह उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रबंध
(1)	(2)
प्रशासन अधिकारी III भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, झाकधर-तारापुर, जिला थाना (महाराष्ट्र)	पावर रिक्टर फूल रिप्रोसेसिंग प्रोजेक्ट तथा वेस्ट मेनेजमेंट फेमिलिटोन ग्राफ डिसेलीनेशन एवं एफ्लुएंट इंजीनियरी प्रखण्ड के या उनके प्रबंधतंत्र के अधीन आने वाले भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, पालघर और बहानु तालुका में जिला थाना (महाराष्ट्र) में स्थान।

[का० सं० 13/2/73-एच]

जिसोक सिंह, अधर सचिव

(Department of Atomic Energy)

Bombay, 13th November, 1975

S.O. 5153—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being a gazetted officer of Government to be the estate officer for the purposes of the said Act, and directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act in respect of the categories of public premises specified in the corresponding entry in column (2) of said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises
Administrative officer-III, Bhabha Atomic Research Centre, Post Office Tarapur, District : Thana, (Maharashtra).	Premises belonging to or under the management of the Power Reactor Fuel Reprocessing Project and Waste Management Facility of Desalination and Effluent Engineering Division, Bhabha Atomic Research Centre, in Palghar and Dahanu Talukas, District : Thana (Maharashtra).

[F. No. 13/2/73 H]

TARLOK SINGH, Under Secy.

उद्योग तथा नागरिक पूति 'मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1975

क्र० प्र० 5154.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिमूर्चित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिन्ह निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन शाब्दिक विवरण हिन और भारतीय मानक के शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है :

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने विधियों के निमित्त यह मानक चिन्ह 16 जनवरी, 1975 से लागू होगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या मानक चिन्ह की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	तत्समसम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक चिन्ह की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1 IS : 3897	हस्तचलित ऐटोमाइजर टाइप स्प्रेयर	IS : 3897-1966 हस्तचलित ऐटोमाइजर टाइप स्प्रेयर की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें IS शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई पैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है ।



[सं० सीएमडी/13: 9]

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)


INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, 9th October, 1975

S.O. 5154—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark, design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 16 January 1975.

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. IS : 3897		Sprayer atomizer type, hand operated.	IS : 3897—1966 Specification for sprayer atomizer type hand operated.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का०प्रा० 5155—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विज्ञान) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि हस्ताचालित ऐटोमाइजर टाइप के स्प्रेयर की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिये गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है। यह फीस 16 जनवरी, 1975 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की परसंख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
1.	हस्ताचालित ऐटोमाइजर टाइप के स्प्रेयर	IS: 3897-1966 हस्ताचालित ऐटोमाइजर टाइप के स्प्रेयर की विधि	एक स्प्रेयर	50 पैसे

[सं० सीएमडी/13 : 10]

S.O. 5155.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee per unit for sprayer atomizer type, hand operated details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee(s) shall come into force with effect from 16 January 1975.

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
1.	Sprayer atomizer type, hand operated.	IS: 3897-1966 Specification for sprayer atomizer type, hand operated.	One Sprayer	50 paise

[No. CMD/13 : 10]

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1975

का०प्रा० 5156—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विज्ञान) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या (सी एम/एल-3201) जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गए हैं, लाइसेंसधारी द्वारा अपना नाम मैसर्स नागपाल अम्बेदी पेट्रो-केमि रिफाइनिंग लिमिटेड से बदलकर मैसर्स नागपाल पेट्रो-केमि लिमिटेड कर देने के कारण रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किये गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बन्धी भारतीय मानक
1.	सीएम/एल-3201 27 अक्टूबर, 1972	मैसर्स नागपाल अम्बेदी पेट्रो-केमि रिफाइनिंग लि०, मनाली, मद्रास-68 (तमिलनाडु)	ट्रांसफार्मरों तथा स्विचगियर के नये रोधन तेल मार्का : 'इंसोल' और 'इलेक्ट्रा'	IS: 335-1972 ट्रांसफार्मरों और स्विचगियर के नए रोधन तेलों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

[संख्या सीएमडी/55 : 3201 (सीडी)]

New Delhi, 15 October, 1975

S. O. 5156.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-2301 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1 September 1975 due to change in licensee's name from M/s. Nagpal Ambadi Petro-Chem Refining Ltd. to M/s. Nagpal Petro-Chem Ltd.—

SCHEDULE

Licence No. and date	Name and Address of the Licensee	Article/Process covered by the Licence cancelled	Relevant Indian Standard
CM/L-3201 27 October, 1972	M/s. Nagpal Ambadi Petro-Chem Refining Ltd., Manali, Madras-68. (Tamil Nadu)	New insulating oils for transformers and switchgear. Brand : 'INSOL & 'ELECTRA'	IS : 335-1972 Specification for new insulating oils for transformers and switchgear. (Second Revision).

[CMD/55 : 3201(ET)]

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1975

क्रा० प्रो० 5157.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विज्ञान) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन वाइसों के बारे में दिये गए हैं, फर्म द्वारा अपना नाम बदल लेने के कारण 16 अगस्त, 1975 से रद्द कर दिये गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	अनुसूची संख्या और तिथि	वाइसों के नाम और पता	रद्द किये गए वाइसों के अधीन वस्तु/पर किया	सम्बन्धी भारतीय मानक
1.	सीएम/एल-3998 21-10-1974	मैसर्स पोचम्पाद पैस्टीसिड्स प्रा० लि०, करीमनगर, इंड-स्ट्रियल इस्टेट, निरमिता रोड, करीमनगर (घा० प्र)	एन्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव	IS : 1310-1974 एन्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)
2.	सीएम/एल-4025 1-11-1974	"	डिडटी जल विमर्जनीय पाउडर	IS : 565-1961 डिडटी जल विमर्जनीय तेज पाउडर की विशिष्टि (पुनरीक्षण)
3.	सीएम/एल-4031 5-11-1974	"	बीएचसी जल विमर्जनीय पाउडर	IS : 562-1972 बीएचसी जल विमर्जनीय तेज पाउडर की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)

[नोटमही/55 : 3998 (एपी)]

New Delhi, 17th October, 1975

S.O. 5157.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L—given below particulars of which are given below has been cancelled with effect from 16 August 1975 due to change in the name of the firm.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and date	Name and Address of the Licensee	Article/Process Governed by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-3998 21-10-74	M/s. Pochampad Pesticides Pvt. Ltd, Karimnagar, Industrial Estate, Sircilla Road, Karimnagar (A.P.)	Endrin EC	IS : 1310—1974 Specification for Endrin Emulsifiable Concentrates (First Revision).
2.	CM/L-4025 1-11-1974	Do.	DDT WDP	IS : 565—1961 Specification for DDT Water Dispersible Powder Concentrates. (Revised).
3.	CM/L-4031 5-11-1974	Do.	BHC WDP	IS : 562—1972 Specification for BHC Water Dispersible Powder Concentrates. (Third Revision).

[CMD/55 : 3998 (AP)]

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1975

क्रा० प्रो० 5158.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विज्ञान) विनियम 1955 के विनियम (4) के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किये हैं जिनको डिजाइन शाब्दिक विवरण सहित और भारतीय मानक शीर्षक सहित नीचे अनुसूची में दी गई है :

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विज्ञान) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1 अगस्त, 1975 से लागू होंगे :

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बन्धी भारतीय मानक को पत्र संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IS : 3749	डिई कार्य के लिये रूत और डाई इस्पात	IS : 3749-1966 डिई कार्य के लिये रूत और डाई इस्पात की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें 'IS' शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।




[संख्या सीएमबी/13:9]

New Delhi, 23rd October, 1975

S.O. 5158.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1 August 1975.

SCHEDULE


Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. IS : 3749		Tool and die steels for cold work	IS : 3749—1966 Specification for tool and die steels for cold work.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

का०आ० 5159.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चिह्न निर्धारित किये हैं जिनकी डिजाइन शाब्दिक विवरण सहित और भारतीय मानक के शीर्षक सहित सीधे अनुसूची में दी गई है :

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक चिह्न 1 मिनम्बर 1975 से लागू होगा :

अनुसूची


क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइनें	उत्पाद/उत्पादन की श्रेणी	सम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
1. IS : 5672		मुगियों के चारे में पूरक रूप में मिलाए जाने वाले खनिज मिश्रण	IS : 5672-1970 मुगियों के चारे में मिलाए जाने वाले खनिज मिश्रण की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था के मोनोग्राम जिसमें 'ISI' शब्द होते हैं, स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसे डिजाइन में दिखाया गया है मोनोग्राम में ऊपर की ओर भारतीय मानक की पदसंख्या दी गई है।

[सं० सीएमडी/13:9]

S.O. 5159.—In pursuance of sub-rule (1) of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark design of which together with the verbal description of the design and the title of the relevant Indian Standards is given in the Schedule hereto annexed, has been specified.

This Standard Mark for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1 September, 1975.

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. and Title of the Relevant Indian Standard	Verbal description of the Design of the Standard Mark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. IS : 5672		Mineral mixtures for supplementing poultry feeds.	IS : 5672—1970 Specification for mineral mixtures for supplementing poultry feeds.	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letters 'ISI', drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col. (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

क्र० आ० 5150—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ठंडे कार्य के लिए टूल और डाई-इस्पात की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्योरे के अनुसार निर्धारित की गई है। ये फीस 1 अगस्त, 1975 से लागू होंगी।

अनुसूची

क्रम संख्या उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	संबद्ध भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
(1)	(2)	(3)	(4)
1. ठंडे कार्य के लिये टूल और डाई इस्पात	IS: 3749-1966 ठंडे कार्य के लिये टूल और डाई इस्पात की विशिष्टि	एक मीटरी टन	50 पैसे

[संख्या सीएमडी/13:10]

S.O. 5160.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee per unit for tool and die steel for cold work details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1 August 1975 :—

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tool and die steels for cold work.	IS : 3749—1966 Specification for tool and die steels for cold work.	One Tonne	50 Paise

[No. CMD/13 : 10]

क्र० आ० 2561—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मुगियों के चारे में पूरक रूप में मिलाए जाने वाले खनिज मिश्रण की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्योरे के अनुसार निर्धारित की गई है। यह फीस 1 सितम्बर, 1975 से लागू होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	संबद्ध भारतीय मानक की पद-संख्या और शीर्षक	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस
1. मुगियों के चारे में पूरक रूप में मिलाए जाने वाले खनिज मिश्रण	IS : 5672-1970 मुगियों के चारे में पूरक रूप में मिलाए जाने वाले खनिज मिश्रण की विशिष्टि	एक मीटरी टन	(1) 500 इकाइयों तक रु० 2.00 प्रति इकाई और (2) 501वीं और इससे ऊपर की इकाइयों के लिए 1.00 प्रति इकाई

[संख्या सीएमडी/13:10]

ए० बी० राव, उपमहानिदेशक

S.O. 5161.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking fee per unit for mineral mixtures for supplementing poultry feeds details of which are given in the Schedule hereto annexed, has been determined and the fee shall come into force with effect from 1 September 1975.

SCHEDULE

Sl. No.	Product/Class of Product	No. and Title of Relevant Indian Standard	Unit	Marking Fee per Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mineral mixtures for supplementing poultry feeds.	IS : 5672-1970 Specification for mineral mixtures for supplementing poultry feeds.	One Tonne	(i) Rs. 2.00 per unit upto 500 units and (ii) Rs. 1.00 per unit from 501st unit and above.

[No. CMD/13 : 10]

A. B. RAO, Deputy Director General

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1975

का० प्रा० 5162—यतः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (इ) के अनुसरण में मणिपुर सरकार ने 1 सितम्बर, 1975 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मणिपुर के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं के निदेशक डा० एन० बी० राय को उक्त राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति का सदस्य मनोनीत कर दिया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि मणिपुर, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं के निदेशक डा० एन० बी० राय खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के सदस्य होंगे और भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 1 जून, 1955 की अधिसूचना सं० एस० आर० प्रो० 1236 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में, मद संख्या 35 और इससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखनी जाय, नामतः "36.

डा० एन० बी० राय,

निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवा, मणिपुर)

[सं० पी० 15016/1/74-पी० एच०/डी० एण्ड एम० एस०]

रमेश बहादुर, अवसर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 19th November, 1975

S.O. 5162.—Whereas in pursuance of clause (e) of sub-section (2) of section 3 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Government of Manipur have nominated Dr. N. B. Roy, Director of Medical, Health and Family Planning Services, Manipur as a member of the Central Committee for Food Standards representing that Government for a term of 3 years with effect from the 1st September, 1975.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that Dr. N. B. Roy, Director of Medical, Health and Family Planning Services, Manipur shall be a member of the Central Committee for Food Standards and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health S.R.O. 1236 dated the 1st June, 1955 namely :—

In the said notification, after item 35 and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely :—

"36. Dr. N. B. Roy,

Director of Medical, Health and
Family Planning Services,
Manipur."

[No. P. 15016/1/74-PH(D&MS)]

RAMESH BAHADUR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रादेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1975

का० प्रा० 5163—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों की गुजराती भाषा में, जिनका विवरण प्रत्येक के समयने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 27) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का बम्बई अधिनियम 17) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या बैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	महिती चित्र सं० 209	274.32 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, गांधी नगर।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात सिनेमा के लिये)।	
2.	महिती चित्र संख्या 210	259.08 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, गांधी नगर।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात सिनेमा के लिये)।	
3.	महिती चित्र सं० 211	228.60 मीटर	-तद्वै-	-तद्वै-	-तद्वै-
4.	स्टीनलज आफ दो बोर्डर	375.20 मीटर	-तद्वै-	-तद्वै-	-तद्वै-

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1975

S. O. 5163.—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film/films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it each in column 6 of the said Second Schedule.

FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Mahitichitra No. 209	274.32 Metres	Director of Information Govt. of Gujarat, Gandhi Nagar.		Film dealing with news and current events (For release in Gujrat Circuit only)
2.	Mahitichitra No. 210	259.08 Metres		Do.	Do.
3.	Mahitichitra No. 211	228.60 Metres		Do.	Do.
4.	Sentinels of the Border	375.20 Metres		Do.	Do.

[File No. 61/75-F(P) App. 2027]

आदेश

क्र० प्र० 5164.—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गए निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, किन्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कायम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कायम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) चित्रचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 27) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 (1953 का बम्बई अधिनियम 11) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	जिंदगी और मौत के दरम्यान।	276.76 मीटर	सूचना और जन-संपर्क निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।	महाराष्ट्र	डाकुमेंट्री (महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिये)।
2.	अनुशासन	182.88 मीटर	-तदीव-		शिक्षा सम्बन्धी (महाराष्ट्र सर्किट के लिये)।
3.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 287	297.00 मीटर	सूचना और जन-संपर्क निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।	महाराष्ट्र	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (महाराष्ट्र सर्किट के लिये)
4.	स्वप्न इन्फ्यूमेंट	383.13 मीटर	-तदीव-		डाकुमेंट्री (महाराष्ट्र सर्किट के लिये)।

[क्र० सं० 61/75-एफ०पी० पर्सिप्ट-2028]
 चार०डी० जाणी, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

S. O. 5164.—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

FIRST SCHEDULE

(1) Sub-section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXVII of 1952).

(2) Sub-section (3) of sections 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Zindgi Aur Maut Ke Darmyan	276.76 Metres	The Director of Information & Public Relations, Government of Maharashtra, Bombay.		Documentary (for release in Maharashtra circuit).
2.	Anushasan	182.88 Metres		Do.	Educational release in Maharashtra circuit.
3.	Maharashtra News No. 287	297.00 Metres		Do.	News & Current events (Release in Maharashtra circuit).
4.	Slum Improvement	383.13 Metres		Do.	Documentary (Release in Maharashtra circuit).

[File No. 6/1/75-F(P) App. 2028]

R. D. JOSHI, Section Officer (Special)

अन मन्त्रालय

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1975

का० आ० 5165.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कीर्तिजय एंड कंपनी रामनिवास कम्पाउण्ड, विजलपुर, नवसारी, नामक स्थापन में सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इस्तीमवे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[संख्या एम० 35019(68)/75-पी० एफ० 2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 30th October, 1975

S.O. 5165.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kirtijay and Company Ramnivas Compound, Vijalpore, Navasari have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1975.

[No. S. 35019(68)/75-PF.II]

का० आ० 5166.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि नवसारी वार्डिंग वर्क्स, पोस्ट बॉक्स सं० 37, राम निवास कम्पाउण्ड विजलपुर, नवसारी नामक स्थापन में सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध, उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इस्तीमवे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एम० 35019/(72)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5166.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Navsari Winding Works, Post Box No. 37, Ramnivas Compound, Vijalpore, Navsari have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1975.

[No. S. 35019(72)/75-PF.II]

का० आ० 5167.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री बालगणेशन मेटल्स (कारखाना) 9/84 सीडेल्हम रोड, मद्रास नामक स्थापन में सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन

निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० 35019(150)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5167.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shri Balaganesan Metals (Factory) 9/84, Sydenhams Road, Madras-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1974.

[No. S. 35019(150)/75-PF.II]

का० आ० 5168:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री बाल गणेशन मेटल्स 39 मिण्ट स्ट्रीट, मद्रास-3 नामक स्थापन जिसके अन्तर्गत (i) 4/488 मिण्ट स्ट्रीट मद्रास-3 और (ii) 11, निनीअप्पा नायकन स्ट्रीट, मद्रास-3 स्थित उनकी शाखाएँ भी आती हैं, से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एम० 35019(151)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5168.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shri Balaganesan Metals, 39, Mint Street, Madras-3 including its branches at (i) 4/488, Mint Street, Madras-3 and (ii) 11, Nyniappa Naicken Street, Madras-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1974.

[No. S. 35019(151)/75-PF.II]

का० आ० 5169:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० बी० सी० एम्सपोर्ट्स एंड प्राइवेट लिमिटेड अर्न्तर्गत गुजरात 2 जालन्धर सिटी, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब

पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० 35019(152)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5169.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A.B.C. Export House, Private Limited, Basti Gurjan, Jullundur City have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1974.

[No. S. 35019(152)/75-PF.II]

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1975

का० आ० 5170:—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2255 तारीख 17 अगस्त, 1974 के अनुक्रम में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (परिकरणी और पाइप लाइन प्रभाग) कानपुर टी स्टेशन, डाकघर अरमापुर, कानपुर को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 31 अगस्त, 1975 से 30 अगस्त, 1976 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है:

पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:-

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की वास्तव (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, ऐसी शिथिलता, ऐसे प्रसंग में और ऐसी परिस्थितियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थीं।

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदाधिकारी जो उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो:-

(i) उक्त अवधि की वास्तव धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की वास्तव कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा सहायित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे: या

- (iii) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए जाने वाले उन फायदों को पाने के अब भी हकदार हैं, जिनके प्रतिफल स्वयं इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या
- (iv) यह अधिनियमित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उस अवधि के दौरान जब उपर्युक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उप-बन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए संभव होगा, अर्थात्:—
- (क) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह ऐसी सूचना दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाए;
- (ख) ऐसे प्रधान या अध्यक्षित नियोजक के अधिनियमों की किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी व्यक्तिगत समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारमात्रन कर रहा हो, यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजों, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों प्रस्तुत करें, और उसकी परीक्षा करने दे उन्हें जैसी वे आवश्यक समझें वैसी जानकारी दें; या
- (ग) प्रधान या अध्यक्षित नियोजक, उसके अधिकारी या सेवक या किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या
- (घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करे या उससे उद्धरण उतारता।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वपक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के मंजूरी संबंधी प्रस्ताव पर कार्यवाही करने में समय लग गया। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियाँ, जिनमें कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी अभी तक भी विद्यमान हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वपक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[मं० नं० 38014/9/74-एच० आई०]

New Delhi, the 1st November, 1975

S.O. 5170.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2255, dated the 17th August, 1974, the Central Government hereby exempts the India Oil Corporation Limited (Refineries and Pipe Lines Division) Kanpur T/Station, Post Office Armapur, Kanpur from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 31st August, 1975 upto and inclusive of the 30th August, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

- (1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns

in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.

- (2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—
- (i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or
- (ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or
- (iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or
- (iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory, be empowered to—
- (a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found in charge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or
- (c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or
- (d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the proposal for grant of exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest or anybody adversely.

[No. S. 38014/9/74-H1]

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1975

नं० आ० 5171.—समस्त परान लिमिटेड, उद्योग मन्दिर, सं० 1, 7वीं पीताम्बर लेन, माहिम, मुम्बई-400016 (जिसे हमने उसके परान उपर्युक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अधिनियम और कृद्म वेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार की राय में अधिनियम की दणों की वास्तविकता के अधिनियम निधि नियम उसके कर्मचारियों के लिए उन नियमों

से कम अनुकूल नहीं हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 8 में विनिर्दिष्ट हैं, और कर्मचारी भविष्य निधि की अन्य प्रसुविधायें भी पा रहे हैं, जो कर्मचारियों के लिए कुल मिलाकर उन प्रसुविधायों से कम अनुकूल नहीं हैं, जो, उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन के कर्मचारियों के संबंध में, उक्त अधिनियम के अधीन या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन की जाती है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपा-बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है और उक्त धारा 17 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त स्थापन से सम्बद्ध नियोजक उक्त स्थापन के उन कर्मचारियों को, जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन सबस्थ हो गए होते, तत्समय देय वेतन (प्राधारित मजहूरी, संहाराई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, और उस पर अनुज्ञेय खाद्य रियायत का नकद मूल्य) के 0.09 (शून्य दशमसब शून्य नौ) प्रतिशत की दर से निरीक्षण-प्रभार, मासान्त के पंद्रह दिन के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि में देगा ;

अनुसूची

1. नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विश्लेषित करे ।

2. नियोजक प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा-विवरण या पास बुक देगा ।

3. निधि के प्रशासन, जिसमें लेखाओं का बनाए रखना, लेखाओं और विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, संघर्षों का अन्तरण, निरीक्षण-प्रभारों प्रादि का संवाय सम्मिलित है में अन्तर्भूत सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक समुचित सरकार द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और जब कभी उनमें संशोधन किया जाएगा तब कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य-मुख्य बातों का अनुबाव भी प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी निधि) या छूट प्राप्त किसी अन्य स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही से सबस्थ है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक स्थापन की निधि के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ही दर्ज करेगा और ऐसे कर्मचारी की बाबत उसके पिछले संघर्षों को स्वीकार करके उन्हें उसके खाते में जमा करेगा ।

6. यदि उस वर्ग के स्थापनों के लिए, जिसमें नियोजक का स्थापन आता है, भविष्य निधि के अभिदायों की दर कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के अधीन बढ़ा दी जाए तो नियोजक भविष्य निधि के अभिदायों की दर समुचित रूप से बढ़ा देगा ताकि स्थापन की भविष्य निधि स्कीम के अधीन की प्रसुविधायें उन प्रसुविधायों से कम अनुकूल न हो जाएं जिनकी व्यवस्था उक्त अधिनियम के अधीन की गई है ।

7. स्थापन अपनी भविष्य निधि का संपरीक्षित तुलन-पत्र प्रति वर्ष प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त को वर्षांत के तीन मास के भीतर भेजेगा ।

8. भविष्य निधि नियम में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त के पूर्व अनुमोदित के बिना नहीं किया जाएगा । जहां किसी संशोधन

से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र अपनी अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा ।

[सं० एम-35014/24/75-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 7th November, 1975

S.O. 5171.—Whereas Messrs Paraan Limited, Udyog Mandir, No. 1; 7-C, Pitamber Lane, Mahim, Bombay-400016. (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952);

And whereas in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act, and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme and in pursuance of sub-section (3) of the said section 17, the Central Government hereby directs that the employer in relation to the said establishment shall pay within fifteen days of the close of the month to the Employees' Provident Fund, Inspection charges at the rate of 0.09 per cent (zero point zero nine per cent) of the pay (basic wages, dearness allowance, retaining allowance, if any, and cash value of food concession admissible thereon) for the time being payable to the employees of the said establishment who would have become members under the said Scheme but for this exemption.

SCHEDULE

1. The employer shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government may, from time to time, prescribe.
2. The employer shall furnish to each employee an annual Statement of account or Pass Book.
3. All expenses involved in the administration of the fund including the maintenance of accounts, submission of accounts and returns, transfer of accumulations, payment of inspection charges, etc., shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.
5. Where an employee who is already member of the Employees' Provident Fund (Statutory Fund) or the provident fund of another exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund of the establishment, and accept the past accumulations in respect of such employee and credit to his account.
6. The employer shall enhance the rate of provident fund contribution appropriately, if the rate of provident fund contributions for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the Employees Provident Fund Act, 1952

(19 of 1952) so that the benefits under the provident fund scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

7. The establishment shall submit an audited balance sheet of its provident fund every year to the Regional Provident Fund Commissioner within 3 months of the close of the year.

8. No amendment of the rules of the provident fund shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Where any amendment is likely to affect adversely the interests of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

[F. No. S-35014/24/75-PF-II]

का० आ० 5172.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स, आनन्द पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, 45-बी बेनिया टोला लेन, कलकत्ता-9 मामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017 (5)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5172.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ananda Publishers, Private Limited, 45B, Beniatola Lane, Calcutta-9 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January 1973.

[No. S. 35017(5)/75 PF-II(i)]

का० आ० 5173.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बन्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1973 से मैसर्स आनन्द पब्लिशर्स, प्राइवेट लिमिटेड 45 बी बेनियाटोला लेन, कलकत्ता-9 मामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35017(5)/75-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 5173.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the

matter, hereby specifies with effect from the 1st day of January, 1973, the establishment known as Messrs Ananda Publishers, Private Limited, 45-B, Beniatola Lane, Calcutta-9 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(5)/75 PF. II(ii)]

का० आ० 5174.—केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हेबा होजरी 20/1ए, ब्रिन्दावन बासक स्ट्रीट, कलकत्ता-5, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017 (8)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5174.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Saba Hojery, 20/1A, Brindaban Basak Street, Calcutta-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1974.

[No. S-35017(8)/75-PF-III]

का० आ० 5175.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ब्रिस्क मशीन वर्क्स ए/17 श्री राम इण्डस्ट्रियल एस्टेट अम्बेकर रोड वाडला मुम्बई, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई मानी जाएगी

[सं० एस-35018 (3) 75-पी० एफ० 2]

S.O. 5175.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Brisk Machine Works, A/7 Sairam Industrial Estate, 13, Ambedkar Road, Wadala, Bombay have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment;

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1973.

[No. S. 35018(3)/75-PF.II]

का० आ० 5176.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेर्स भारती ट्रेडिंग कम्पनी, पोस्ट बॉक्स सं० 37, राम निवास कम्पाउण्ड, वीजलपुर, नवसारी नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019 (58)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5176.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharati Trading Company, Post Box No. 37, Ramnivas Compound, Vijalpore, Navsari, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1975.

[No. S. 35019(58)/75-PF. II]

का० आ० 5177.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेर्स पी० एन० पी० ट्रांसपोर्ट्स, 6-बी/21 टाउन इक्सटेंशन 2 स्ट्रीट, तिरुपुर-4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019 (61)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5177.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs P. N. P. Transports, 6-B/21, Town Extension, 2nd Street, Tiruppur-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1975.

[No. S. 35019(61)/75-PF. II]

का० आ० 5178.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेर्स ए० पी० एस० हाल, 69 वेस्ट टाउन स्ट्रीट, मदुराई-1, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019 (68)/74-पी० एफ० 2]

S.O. 5178.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. A. P. S. Hall, 69, West Tower Street, Madras 1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1974.

[No. S. 35019(68)/74-PF. II]

का० आ० 5179.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेर्स एवाई रेयान फैब्रिक्स पोस्ट बॉक्स सं० 37 राम निवास कम्पाउण्ड विजलपुर, नवसारी, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019 (69)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5179.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Powai Rayon Fabrics, Post Box No. 37, Ramnivas Compound Vijalpore, Navasari, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1975.

[No. S-35019(69)/75-PF. II]

का० आ० 5180.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ऐरो रेमान फ़ैब्रिक्स, रामनिवास कम्पाउण्ड बिजलपुर, नवसारी, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(71)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5180.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Arrow Rayon Fabrics, Ramniwas Compound, Vijalpore Navsari have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1975.

[No. S-35019(71)/75-PF. II]

का० आ० 5181.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्टीलोक्रिट कांस्ट्रक्टेस लिमिटेड, महादेव पुरा, डाकघर ब्लाइट फील्ड रोड, बंगलूर-48, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(82)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5181.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Steelcrete Consultants Limited, Mahadevapura, Post Office, Whitefield Road, Bangalore-48, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central

Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1975.

[No. S-35019(82)/75-PF. II]

का० आ० 5182.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी० गोविन्दा शेटी और कम्पनी, गांधी बाजार, हसन, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(85)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5182.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. B. Govinda Setty and Son, Gandhi Bazar, Hassan, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1975.

[No. S-35019(85)/75-PF. II]

का० आ० 5183.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री सत्यानारायण ट्रांसपोर्ट, गांधी बाजार, हसन, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 का जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(86)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5183.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sri Satyanarayana Transport, Gandhi Bazar, Hassan, have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1975.

[No. S-35019(86)/75-PF. II]

का० आ० 5184.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डिल्टाइट इंडस्ट्रीज, डी-7, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरवा रोड, बड़ोदा नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अप्रैल के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(90)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5184.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Delite Industries, D-7, Industrial Estate, Gorva Road, Baroda, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1973.

[No. S-35019(90)/75-PF. II]

का० आ० 5185.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कन्या कुमारी पंचायत ग्राम सहकारी कृषि उधार सोसाइटी, बार्ड-297, महादानपुरम, जिला कन्याकुमारी, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अप्रैल के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(91)/75-पी०एफ० 2 (I)]

S.O. 5185.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kanyakumari Panchayat Village Co-operative Agricultural Credit Society, Y-297, Mahadanapuram, Kanyakumari District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1975.

[No. S-35019(91)/75-PF. II(i)]

का० आ० 5186.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विधय में प्राबन्धक जांच करने के पश्चात् 31 अप्रैल, 1975 से मैसर्स कन्याकुमारी पंचायत ग्राम सहकारी कृषि उधार सोसाइटी, बार्ड-297 महादानपुरम जिला कन्याकुमारी नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए चिनि-दिष्ट करती है।

[सं०एस०-35019(91)/75-पी०एफ० 2 (ii)]

S.O. 5186.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of April, 1975 the establishment known as Messrs. Kanyakumari Panchayat Village Cooperative Agricultural Credit Society, Y-297, Mahadanapuram, Kanyakumari District, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(91)/75-PF. II(ii)]

का० आ० 5187.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री साई बाबा स्टोर्स, गांधी बाजार, हसन, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(103)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5187.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sree Saibaba Stores, Gandhi Bazar, Hassan, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1975.

[No. S-35019(103)/75-PF. II]

का० आ० 5188.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तरुण इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, 20 इम्बेसी मार्केट, बिलेश हाल के निकट, प्राश्रम रोड, ग्रहमदाबाद-9 (इसके अंतर्गत गांधी रोड ग्रहमदाबाद स्थित इसका विक्रय कार्यालय भी है) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अक्टूबर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(104)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5188.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Tarun Electrical Industries, 20, Embassy Market, Near Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedabad-9, including its Sale Office at Gandhi Road, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1973.

[No. S-35019(104)/75-PF. II]

का० आ० 5189.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस एफ०डी० खान और कम्पनी, आबिद रोड, हैदराबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(144)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5189.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. F. D. Khan and Company, Abid Road, Hyderabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1975.

[No. S-35019(144)/75-PF. II]

का० आ० 5190.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस कर्नाटक फूड एण्ड सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन लिमिटेड, सी०बी०ए० बी० कंसेक्स डिस्ट्रिक्ट आफिस कम्पाउण्ड, बंगलूर-9, जिसके अन्तर्गत तुमकूर, गंगावती, बेल्लारी, मंगलूर, मैसूर, चित्रदुर्ग, बेलगाम, गुलबर्गा, धारवाड़, हसन, सादया, बंगलूर, शिमोगा, कारवाड़, कोलार, चिकमंगलूर कुर्ग, बिदर और बीजापुर स्थित इसकी शाखाएँ भी हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(153)/75-पी०एफ०-2]

S.O. 5190.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Karnataka Food and Civil Supplies Corporation Limited, C.B.A.B. Complex, District Office Compound, Bangalore-9, including its branches at Tunkur, Gangavathi, Ballary, Mangalore, Mysore, Chitradurga, Belgam, Gulbarga, Dharwar, Hassan Mandhya, Bangalore, Shimoga, Karwar, Kolar, Chickmagalur, Coorg, Bidar and Bijapur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1975.

[No. S-35019(153)/75-PF. II]

का० आ० 5191.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस श्री कालेश्वरी सा मिल्स, पवूरचत्रम-627808, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अक्टूबर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(155)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5191.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sree Kaleeswari Saw Mills, Pavoorchatram-627808, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1974.

[No. S-35019(155)/75-PF. II]

का० आ० 5192.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसेस कलिंग ट्रांसफार्मर्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कटक, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(156)/75-पी०एफ०-2]

S.O. 5192.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kalinga Transformers, Industrial Estate, Cuttack, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1975.

[No. S-35019(156)/75-PF. II]

का० आ० 5193.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मिस्रम मोराझा श्रिवर्स इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सं० ए० ए० ए० सी-5 डाकघर मोराझा, चेरुकुन्नु, कन्नोर जिला कन्नोर, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अगस्त के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(159)/75-पी०एफ०-2]

S.O. 5193.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Morazha Weavers' Industrial Co-operative Society Limited, No. H.I.C. 5 Post Office Morazha, via Cherukunnu, Cannanore District Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1975.

[No. S-35019(159)/75-PF. II]

का० आ० 5194.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मिस्रस इण्डियन मेडीसिन इण्डस्ट्रीज नागालैंड बाराणसी वारी स्ट्रीट सीतापुरम, विजयवाड़ा-4 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(162)/75-पी०एफ०-2]

S.O. 5194.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Indian Medicine Industries, Nagalands, Varanasiwari Street, Sitarampuram, Vijayawada-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1975.

[No. S-35019(162)/75-PF. II]

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

का० आ० 5195.—उत्तर प्रदेश सरकार के, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री मोहन कृष्ण अग्रवाल, संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर को श्री जे० के० द्विवेदी के स्थान पर उक्त धारा के अधीन गठित चिकित्सा प्रमुखिषा परिषद् के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3680 तारीख 21 अगस्त, 1971 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में "धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट" शीर्षक के नीचे, मद 17 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:

"श्री मोहन कृष्ण अग्रवाल,
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा,
कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम,
उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर"

[का० सं० यू०-16012(14)/75-एच० आई०]

New Delhi, the 11th November, 1975

S.O. 5195.—Whereas the State Government of Uttar Pradesh has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri Mohan Krishan Aggarwal, Joint Director of Health Services, Employees' State Insurance Scheme, Government of Uttar Pradesh, Kanpur, as a member of the Medical Benefit Council constituted under the said section, in place of Shri J. K. Dwivedi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3680, dated the 21st August, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading "[Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-

section (1) of section 10]", for the entry against item 17, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Mohan Krishan Aggarwal,
Joint Director of Health Services,
Employees' State Insurance Scheme,
Government of Uttar Pradesh, Kanpur."

[No. F. U-16012 (14)/75-HI]

का० आ० 5198.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मंसमं कालाहस्ती कोषापरेटिव मिल्क सोसाइटी लिमिटेड, यू० सं० 946, श्री कालाहस्ती, जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश जिसके अन्तर्गत इसकी निम्नलिखित शाखाएँ भी हैं, अर्थात् :—

1. उरन्धपुर मिल्क यार्ड उरन्धपुर
2. कन्नाली मिल्क यार्ड कन्नाली
3. चेरलोपल्ली मिल्क यार्ड, चेरलोपल्ली
4. पेन्कालापलम मिल्क यार्ड पेन्कालापलम,
5. पुडी मिल्क यार्ड, पुडी
6. एस० एन० कन्दिगा मिल्क यार्ड, एस० एन० कन्दिगा
7. चिन्ना कन्नाली मिल्क यार्ड, चिन्ना कन्नाली
8. जी० एन० कन्दिगा मिल्क यार्ड, जी० एन० कन्दिगा
9. चेल्लापालम मिल्क यार्ड, चेल्लापालम

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के सितम्बर के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं०-एस-35019 (77)/75-पी०-एफ० 2(i)]

S.O. 5196.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. The Kalahasti Co-operative Milk Supply Society Limited, U. No. 946, Sri Kalahasti, District Chittoor, Andhra Pradesh including its following branches, namely :—

- (1) Urandpur Milk Yard, Urandpur,
- (2) Kannali Milk Yard, Kannali,
- (3) Cherlopalli Milk Yard, Cherlopalli,
- (4) Penkalapalam Milk Yard, Penkalapalam,
- (5) Pudi Milk Yard, Pudi,
- (6) S. N. Kandriga Milk Yard, S. N. Kandriga,
- (7) Chinna Kannali Milk Yard, Chinna Kannali,
- (8) G. N. Kandriga Milk Yard, G. N. Kandriga, and
- (9) Chellapalem Milk Yard, Chellapalem,

have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1973.

[No. S-35019(77)/75-PF. II(i)]

का० आ० 5197.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जाँच करने के पश्चात् 30 सितम्बर, 1973 से मंसमं कालाहस्ती कोषापरेटिव सोसाइटी लिमिटेड यू० सं० 946, श्री कालाहस्ती जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश जिसके अन्तर्गत इसकी निम्नलिखित शाखाएँ भी हैं (1) उरन्धपुर मिल्क यार्ड, उरन्धपुर (2) कन्नाली मिल्क यार्ड कन्नाली (3) चेरलोपल्ली मिल्क यार्ड चेरलोपल्ली (4) पेन्कालापलम मिल्क यार्ड, पेन्कालापलम, (5) पुडी मिल्क यार्ड, पुडी (6) एस० एन० कन्दिगा मिल्क यार्ड, एस० एन० कन्दिगा (7) चिन्ना कन्नाली मिल्क यार्ड चिन्ना कन्नाली (8) जी० एन० कन्दिगा मिल्क यार्ड, जी० एन० कन्दिगा (9) चेल्लापालम मिल्क यार्ड, चेल्लापालम नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019 (77)/75-पी०-एफ० 2 (ii)]

S.O. 5197.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of September, 1973 the establishment known as Messrs. The Kalahasti Cooperative Milk Supply Society Limited U. No. 946 Sri Kalahasti, District Chittoor, Andhra Pradesh including its following branches, namely :—

- (1) Urandpur Milk Yard, Urandpur, (2) Kannali Milk Yard, Kannali, (3) Cherlopalli Milk Yard, Cherlopalli, (4) Penkalapalam Milk Yard, Penkalapalam, (5) Pudi Milk Yard, Pudi, (6) S. N. Kandriga Milk Yard, Kandriga, (7) Chinna Kannali Milk Yard, Chinna Kannali, (8) G. N. Kandriga Milk Yard, G. N. Kandriga and (9) Chellapalam Milk Yard, Chellapalam, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(77)/75-PF. II(ii)]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1975.

का० आ० 5198.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मंसमं पानबारी टी कम्पनी लिमिटेड, बाजार धोबिघान प्रमत्तर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए—

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के नवम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (8)/75-पी०-एफ० II(i)]

New Delhi, the 12th November, 1975

S.O. 5198.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Panbari Tea Company Limited, Bazar Dhabian, Amritsar, have agreed that the provision of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1974.

[No. S-35019(8)/75-PF. II(i)]

का० आ० 5199.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बन्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 नवम्बर, 1975 से मैसर्स पानबारी टी कम्पनी लिमिटेड बाजार धोबियान अमृतसर, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019 (8)/75-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 5199.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 1st day of November, 1974 the establishment known as Messrs. Panbari Tea Company Limited, Bazar Dhabian, Amritsar for the purpose of the said proviso.

[No. S-35019(8)/75-PF. II(ii)]

का० आ० 5200.—वतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बंगलौर वायर रोड मिल्स, महादेवपुर डाकघर बंगलौर-48, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की मई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(53)/75-पी० एफ० II]

S.O. 5200.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Bangalore Wire Rod Mills, Mahadevapura, Post Office Bangalore-48, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1975.

[No. S-35019(53)/75-PF. II]

का० आ० 5201.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जय भारत टेक्स्टाइल राम निबाम कम्पाउण्ड बिजलपुर, नवसारी, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

108 GI/75-10

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(57)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5201.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Jaybharat Textile Ramnivas Compound, Vijalpore Navsari have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1975.

[No. S-35019(57)/75-PF. II]

का० आ० 5202.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कालेरी एस्टेट बिथरकादु डाक घर नील गिरि, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (60)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5202.—Where it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kalleri Estate, Bitherkadu Post Office, The Nilgiris, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1975.

[No. S-35019(60)/75-PF. II]

का० आ० 5203.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कन्याकुमारी ब्रांच स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वार्ड-69 नगरकोदल जिला कन्याकुमारी, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के अप्रैल, के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (64)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5203.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kanyakumari Branch, State Transport Department Employees' Co-operative Society Limited, Y-69, Nagercoil, Kanyakumari District have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1975.

[No. S-35019(64)/75-PF. II]

का० प्रा० 5204.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारत रैपिंग वर्क्स पी० बॉक्स सं० 37 रामनिवास कम्पाउण्ड विजलपुर नवसारी नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019 (70)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5204.—Where it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Bharat Wrapping Works P.O. Box No. 37, Ramnivas Compound Vijal-pore, Navasari have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1975.

[No. S-35019(70)/75-PF. II]

का० प्रा० 5205.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पैरामाउन्ट टेक्सटाइल पोस्ट बॉक्स सं० 37 रामनिवास कम्पाउण्ड विजलपुर, नवसारी, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(73)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 5205.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Paramount Textile, Post Box No. 37 Ramnivas Compound, Vijalpore, Navasari have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applied the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1975.

[No. S-35019(73)/75-PF. II]

का० प्रा० 5206.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अशोक एजेंसीज भूपति बिल्डिंग, विरुद्धनगर रोड, शिवकाशी, जिला रामनाथ नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(99)/75-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 5206.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ashok Agencies, Boopathy Building, Virudhunagar Road, Sivakasi, Ramnad District, have agreed that the provisions of the employees' Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1975.

[No. S-35019(99)/75-PF. II (i)]

का० प्रा० 5207.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक आंच करने के पश्चात् 1 जून, 1975 से मैसर्स अशोक एजेंसीज, भूपति बिल्डिंग, विरुद्धनगर रोड, शिवकाशी, जिला राम नाथ, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस० 35019(99)/75-पी० एफ० 2(ii)]

S.O. 5207.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies with effect from the first day of June, 1975,

the establishment known as Messrs Ashok Agencies, Boodpathy Buildings, Virudhunagar Road, Sivakasi, Ramnad District, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(99)/75-PF. II(ii)]

नई दिल्ली, 14 नवम्बर 1975

का० आ० 5208.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जे० एन० नारजारी को उक्त अधिनियम स्कीम और उसके अधीन विरचित कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग हों सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल राज्य और मध्यप्रान्त और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है।

[सं० ए०-12016/5/74-पी० एफ० I]

New Delhi, the 14th November, 1975

S.O. 5208.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri J. N. Narzary to be an Inspector for the whole of the State of West Bengal and the Union territory of Andaman and Nicobar, Islands for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/5/74-PF. I]

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1975

का० आ० 5209.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री बी० जे० भट्ट, श्रीमति एल० एच० कापडिया और श्रीमती आई० एम० चिटले को उक्त अधिनियम, स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएँ हों, सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए०-12016/2/75-पी० एफ० I (पी० टी०)]

New Delhi, the 15th November, 1975

S.O. 5209.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri B. J. Bhatt, Smt. L. H. Kapadia and Shrimati I. M. Chitale to be an Inspector for the whole of the State of Maharashtra for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed there under in relation to any establishment belonging to or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port,

a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/2/75-PF. I (Pt.)]

का० आ० 5210.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के धर्म मंत्रालय की अधिवृचना सं० ए-12016(7)/72 पी० एफ० 1, तारीख 29 अप्रैल, 1974 को अधिस्तृत करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए० एस० लक्ष्मणन को उक्त अधिनियम स्कीम और उसके अधीन विरचित कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएँ हों, सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य और गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए०-12016(7)/72-पी० एफ० I]

एस० एस० सहस्रनामान, उप सचिव

S.O. 5210.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. A-12016(7)/72-PF. I, dated the 29th April, 1974, the Central Government hereby appoints Shri A. S. Lakhmanan to be an Inspector for the whole of the State of Maharashtra and the Union Territory of Goa, Daman and Diu for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016(7)/72-PF. I]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 15th November, 1975

S.O. 5211.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bhubaneswar, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Pelletizing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited and their workman Shri B. K. Mishra, which was received by the Central Government on the 15th November, 1975.

INDUSTRIAL TRIBUNAL ORISSA, BHUBANESWAR

Industrial Dispute Case No. 6 of 1975 (Central)

PRESENT :

Dr. B. N. Misra, LL.M. (London), Ph.D. (London), Bar-at-Law, Presiding Officer Industrial Tribunal, Bhubaneswar.

BETWEEN

The workman Shri B. K. Mishra... First Party

AND

The employers in relation to the Management of Pelletizing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited. Second Party

APPEARANCES :

Shri B. K. Misra.—First Party-Workman

Shri D. N. Choudhury, Legal Officer (Mines).....
For the second party—Tata Iron & Steel Co.

AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act 1947, the Central Government referred the following dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, vide Government of India, Ministry of Labour, Order dated 21-2-75 :—

"Whether the action of the management of Pelletizing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Noamundi, District, Singhbhum was justified in dismissing from service Sri B. K. Mishra, Fitter-cum-Operator, from the 7th of May, 1971 ?

If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

Thereafter, in exercise of the powers conferred by Section 7A and sub-section (1) of Section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government withdrew the proceedings in relation to the above dispute from the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad and transferred the same to the then Presiding Officer of this Tribunal for disposal, vide Government of India, Ministry of Labour Order dated 9-7-75. Finally, in exercise of the powers conferred by Section 7A and sub-section (1) of Section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act), the Central Government withdrew the proceedings in relation to the above dispute from the then Presiding Officer of this Tribunal and transferred the same to this Tribunal for disposal according to law with a direction that this Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which it is transferred, vide Government of India, Ministry of Labour, Order dated 27-8-75.

2. Admittedly the first party was appointed as a Weekly and posted at the Manganese Mines of the second party at Joda, Keonjhar, Orissa on 4-8-1954. The first party was promoted as a Telephone Operator 'B' from 31-8-1962 and as a Telephone Operator 'A' from 1-10-1965 and the first party worked in that capacity till 15-1-1971. The first party was further promoted as Fitter-cum-Operator and transferred to the second party's Pelletizing Plant at Noamundi, Singhbhum, Bihar with effect from 16-1-1971.

3. The case of the first party may be briefly stated.

According to the first party, he has been dismissed from service on the allegation that on 1-2-1971 at the Joda Time Office he had tampered with the pay-sheet inserting the figure '1' before Rs. 88.05 against the amount payable to him for the month of January 1971. The first party had pleaded not guilty to the charges and denied to have any knowledge thereof. The first party has urged that the entire proceeding against him was misconceived and the order of dismissal has been passed on no evidence. There is no evidence on record and none of the witnesses has said that the first party had inserted the figure '1' before the figure Rs. 88.05 in the original sheet. The first party admits that on 1-2-1971 he had gone to the Office of the Head Time Keeper for securing a bus pass to go to Noamundi from Joda. The first party has alleged that the enquiring officer has surmised that as the insertion of the figure '1' has been made against his Pay Bill, it must have been done by the first party. It is reasserted that the persons who were present in the office at that time have not stated that the first party had made any interpolation. The discrepancies in the evidence of the witnesses have been lightly brushed aside by the enquiring officer. It is also pointed out that the interpolation has not been verified with the help of any expert. It is also stated that the enquiry has been held against the first party in violation of the principles of natural justice. The first party has accordingly prayed that the dismissal order should be set aside and he should be reinstated in his job with full consequential benefits.

4. The case of the second party may be briefly stated.

After the transfer of the first party from Joda to Noamundi, the pay of the first party from 1st to 15th January 1971 was drawn at Joda and that from 16th to 31st

January, 1971 at Noamundi. The pay rolls had been duly drawn up by 31-1-1971 and they were to be signed by the Assistant Town Manager on 1-2-1971 at Joda. The net amount receivable by the first party was Rs. 88.05. After the signature of the Assistant Town Manager on 1-2-1971, the originals of the pay rolls were sent to the Accounts Office at Jamshedpur in the afternoon of 1-2-1971. The first party had gone to the Time Office at Joda during the early hours of 1-2-1971 before the Assistant Town Manager had signed the pay rolls. It is alleged that the first party had surreptitiously inserted the figure '1' before Rs. 88.05 in the pay roll in the net amount receivable by him. It is further alleged that the first party had converted the actual amount payable to him from Rs. 88.05 to Rs. 188.05 with dishonest intention in order to make a wrongful gain of Rs. 100. The surreptitious insertion of the figure '1' before Rs. 88.05 in the 'net' column against the first party's name in the pay rolls had not been detected before the despatch of the pay rolls to Jamshedpur on 1-2-1971. The cash for disbursement of the wages for January 1971 and the original pay roll for January 1971 were brought from Jamshedpur to Joda. In the instant case the wages were disbursed at Joda on 5-2-1971. On 4-2-1971 an officer of the Audit Section checked the pay rolls and found that the vertical total of the net wages in the payable column at page 34 of the pay roll revealed a discrepancy. The total written at the bottom of the page in the 'net' column was Rs. 17,391.12, but the figures came to a total of Rs. 17,491.12 on calculation. After verification the total was correctly recorded as Rs. 17,391.12 on the basis of Rs. 88.05 being the net amount payable to the first party. The total had worked out to Rs. 17,491.12 because of the surreptitious insertion of the figure '1' before Rs. 88.05 in the 'net' column against the name of the first party. On 5-2-71 the pay envelop of the first party containing Rs. 88.05 in cash was made over to the employee Sri Sricharan who had been authorised by the first party to receive his wages. A preliminary investigation into the above matter revealed a prima facie case against the first party and he was charge-sheeted on 3-3-1971. The first party's explanation was not found satisfactory and a domestic enquiry was conducted on 16-3-71. The first party fully participated in the enquiry. The enquiring officer found the first party guilty of the charge and finally dismissed him from service with effect from 7-5-1971 for his misconduct in tampering with the pay roll with dishonest intention.

5. In this proceeding the first party has examined himself as W.W. No. 1. He has not examined any other witness nor as he adduced any documentary evidence. Two witnesses have been examined on behalf of the second party. The second party also relies on documentary evidence.

6. The first party has stated that on 7-5-1971 he was dismissed from service on the false allegation that on 1-2-1971 he had tampered with his pay-sheet by inserting the figure '1' before Rs. 88.05 against his Pay Bill for the period from 1st till 15th January 1971. According to him, he has been dismissed from service without any basis. In his cross-examination he has stated that for the period from 1st till 15th January 1971 he had authorised M.W.1 in the official form to receive the pay amount on his behalf. M.W.1 had received Rs. 88.05 from the Pay Master and had handed over the said sum to the wife of the first party who had not previously known the amount the first party was going to receive as his pay. He has denied that his wife had enquired from M.W.1 as to why he was paying her Rs. 88.05 instead of Rs. 188.05. The first party admits that he has no enmity with Shrimati Merry Deogan, Sri B. K. Patnaik and M.W.1. He has also stated that the second party had served charge-sheet upon him and had asked for his explanation which he had submitted. He had also attended the enquiry and cross-examined the witnesses of the second party. He had not adduced any oral and documentary evidence in the enquiry. On the statement of witness the late R. M. Maiti he had signed under protest saying that his statement was false.

7. On behalf of the second party M.W.1 has stated that the first party is distantly related to him. The first party had authorised him in the official form to receive his pay for the period from 1st till 15th January 1971. M.W.1 received Rs. 88.05 from the Pay Master being the pay of the first party and he had handed over the said sum to the wife of the first party. As he handed over the pay envelop, the wife of the first party enquired from him as to what

happened to Rs. 100 as, according to her, the first party had told her that she was to receive Rs. 188.05. M.W.1 told her that he did not know anything about that. Soon thereafter an enquiry was made by the second party as regards the interpolation of the Pay Bill of the first party. M.W.1 had been examined as a witness in the enquiry against the first party. His statement is Ext. A. In his cross-examination M.W.1 has stated that he did not know what amount the first party was to receive as his pay for the period from 1st till 15th January 1971. On receipt of the pay slip in respect of the first party M.W.1 had signed on the pay-sheet before the Time Keeper. Ext. 1 is that signature of M.W.1. At the time of signing Ext. 1 M.W. 1 did not notice whether Rs. 88.05 or Rs. 188.05 or both the amounts had been written on the pay-sheet against the name of the first party.

M.W. 2 is the Legal Officer of the second party. He has stated that in February 1971 it came to light that the first party had interpolated the figure '1' before Rs. 88.05 in the pay-sheet against his entry. Ext. B is the relevant pay-sheet for the month of January 1971. A preliminary enquiry was held into the above allegation and a prima facie case was established. Thereafter departmental proceedings were started and the first party was asked to show cause. Ext. C is the show cause notice. Ext. C/1 is the explanation submitted by the first party. The enquiry was conducted by Sri N. Sen in the presence of the first party. Sri Sen had recorded the statements of the late R. M. Maiti, Sri B. K. Patnaik, Srimati Merry and M.W. 1 vide Exts. D. D/1, D/2 and A respectively. Sri Sen had also recorded the statements of the first party who had only examined himself on behalf of the defence. Ext. D/3 is that statement of the first party. Exts. E is the enquiry report submitted by the enquiring officer holding the first party guilty of the charge. On consideration of the enquiry report and the materials, the second party dismissed the first party from service with effect from 7-5-71.

8. From the above evidence it is clear that there are no eye-witnesses who had actually seen the first party inserting the figure '1' before Rs. 88.05 in Ext. B. The first party has denied that he had made the above interpolation. His explanation is that he does not know anything about the facts stated in the charge-sheet. The enquiring officer who had conducted the enquiry against the first party has relied upon circumstantial evidence to come to the finding that the first party had made the above interpolation with the dishonest intention of making a wrongful gain of Rs. 100. From the records it appears that the enquiry has been properly conducted in the presence of the first party. No irregularity has been brought to notice. The first party has admitted that the witnesses who have deposed against him at the enquiry do not have any ill-feelings towards him. Thus there is no reason why the witnesses would depose falsely against the first party. The first party has himself admitted that he was present in the Time Office in the early hour of 1-2-1971. The enquiring officer has accepted the statement made before him by M.W. 1 regarding the query made by the wife of the first party as to why M.W. 1 was paying her only Rs. 88.05 when the first party had told her that the amount to be paid was Rs. 188.05. The enquiring officer has further noted in Ext. E that the first party had not challenged the above fact during the enquiry. The circumstance relied upon by the enquiring officer in order to arrive at his finding have been noted by him in Ext. E. It was pointed out by the Supreme Court in the Case of M/s. Banaras Electric Light & Power Co. Ltd. Vs. Labour Court, II, Lucknow and others reported in Supreme Court Labour Judgments, 1972, Volume 9 at page 224 that an Industrial Tribunal would not be justified in characterising the finding recorded in the domestic enquiry as perverse unless it could be shown that such a finding was not supported by any evidence, or was entirely opposed to the whole body of evidence adduced before it. In a domestic enquiry once a conclusion was deduced from the evidence, it was not permissible to assail that conclusion even though it was possible for some other authority to arrive at a different conclusion on the same evidence. In the present case there is nothing on record to hold that the finding of the enquiring officer is not supported by any evidence, or is entirely opposed to the whole body of evidence adduced before him. Since there was no direct evidence before him, the enquiring officer relied upon the circumstantial evidence including the evidence of M.W.1. in order to come to his finding that the first party was guilty of the charge. Before the enquiring officer there was evidence to the effect that the first party was present in the Time Office in the early

hours of 1-2-1971 and the most incriminating circumstance comes from the statement of M.W. 1 that the first party's wife had enquired from M.W. 1 as to why he was paying her only Rs. 88.05 when the first party had told her that Rs. 188.05 was to be paid. The chance of a clerical error in nothing the figure as 188.05 was also considered by the enquiring officer but rightly brushed aside by him on the ground that in that case the total at the bottom of the page should have gone up by Rs. 100. The enquiring officer has also noted that the interpolation was likely to benefit none else than the first party himself. Hence the evidence and materials placed before the enquiring officer clearly justified him in coming to the conclusion that the first party had tampered with the pay-sheet by inserting the figure '1' before Rs. 88.05 against the amount payable to him for the period from 1st till 15th January 1971. This finding cannot be assailed merely on the ground that it is based on circumstantial evidence and not on direct evidence.

9. Hence on consideration I find that the action of the management of Pelletizing Plant of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Noamundi, District Singhbhum was justified in dismissing from service Sri B. K. Mishra, Fitter-cum-Operator, from the 7th of May, 1971 and the said Sri B. K. Mishra is not entitled to any relief.

B. N. MISRA, Presiding Officer,
Industrial Tribunal Bhubaneswar.

Dated : 4-11-1975.

[No. L-29012/22/74-LRIV/D IV (B)]
BHUPENDRA NATH, (Spl.) Section Officer.

New Delhi, the 15th November, 1975

S.O. 5212.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Government of India Press, Minto Road, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th November, 1975.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

PRESENT :

Shri D. D. Gupta,
Central Govt. Industrial Tribunal, Delhi.

New Delhi, the 18th October, 1975

C.G.I.D. No. 24 of 1975

BETWEEN

The management of Govt. of India Press, Minto Road,
New Delhi.

AND

Its workman Shri Prem Parkash Sharma.
Shri A. N. Chadu for the workman.
Shri G. Bhargava for the management.

AWARD

The Central Govt. on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L. 16611(6)/74-I.R. III/D. 2(b) dated the 26th May, 1975 with the following term of reference :—

"Whether the management of the Government of India Press, Minto Road, New Delhi, is justified in denying appointment of Shri Prem Parkash Sharma,

Binder-cum-Guillotine Operator, as Offset Machine Man Grade II, with effect from July, 1974. If not, to what relief is the said workman entitled.

2. The workman averred that he was a binder-cum-guillotine operator in the Govt. of India Press, Minto Road, New Delhi. He was not satisfied with his future prospects. He, therefore, applied for a no objection certificate for getting his name registered with the local employment exchange. This certificate was issued to him by the General Manager. His name was then sponsored by the employment exchange. He was ever interviewed on 12-11-73 for the post of Offset Machineman Grade II. He was given a practical test, also, on the machine. His performance at that test as well as in the interview was considered excellent. Accordingly, he asked that formal appointment order to the post of Offset Machineman grade II be issued. The management, however, did not issue the said order. Instead of it, another man was taken on that post by transfer; hence this dispute with the prayer that the action of the management in denying him the appointment to the post of Offset Machineman grade II be held to be unjustified.

3. The management admitted all the facts alleged by the workman, but stated that the workman had no right of appointment to the post of Offset Machineman grade II. Therefore, he was not appointed as such. It was prayed that the petitioner be dismissed.

4. The workman filed a rejoined and re-iterated his claim.

5. On these pleadings the following issue was settled for decision.

ISSUE :

1. As in the term of reference.

6. Since all the facts had been admitted by the respondent, no evidence was needed and none was produced. Only arguments were heard. My decision is as follows :—

ISSUE No. 1

7. It was contended on behalf of the management that the post of Offset Machineman grade II was to be filled in by direct recruitment. It was for this reason that the name of the workman herein was sponsored by the employment exchange and the workman was given a practical test and was interviewed. The workman, however, did not fulfil the required qualifications, in that, he was above 35 years of age and did not have 5 years of experience of printing on Offset printing machines. Consequently, he was not appointed even though he passed the practical test and the interview test.

8. Shri A. N. Chahu appearing for the workman has frankly conceded that the workman was above 35 years of age on 12-11-73, the material date in this case. He, also, admitted that the workman did not have five years experience of printing on Offset printing machines. He, also, admitted that these were two essential qualifications for an appointment to the post of Offset Machineman grade II.

9. Considering the admissions made by the representative for the workman, I have no hesitation to hold that the workman was not a person qualified to be appointed to the post of Offset machineman grade II. The fact that he had passed a practical test or the interview test did not alone entitled him to be appointed to the said post. The action of the management in denying the said appointment to Shri Prem Prakash Sharma was, therefore, not unjustified in any way. The issue is, accordingly, decided against the workman.

10. The total result is that the action of the management in denying the appointment to Shri Prem Parkash Sharma binder-cum-guillotine operator as Offset machineman grade II was justified and he was not entitled to any relief. An award is made accordingly.

18th October, 1975

[No. L-16011/6/74-LR.III/D-II(B)]

D. D. GUPTA, Central Govt. Industrial Tribunal : Delhi

प्रादेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1975

का० प्रा० 5213.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय खाद्य निगम (पत्तन संक्रियायें), मद्रास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधि-करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थिरु टी० पालानियाप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय खाद्य निगम (पत्तन संक्रियायें) मद्रास के प्रबन्धतन्त्र की श्री के० राजू, मजदूर की सेवायें 11-7-1973 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुसूची का हकदार है?

[संख्या एल०-42012(51)/74-एल० मार०-3/डी०-2 (बी०)]

ORDER

New Delhi, the 30th September, 1975

S.O. 5213.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Food Corporation of India (Port Operations), Madras and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

THE SCHEDULE

Whether the action of the management of the Food Corporation of India (Port Operations), Madras, in terminating the services of Shri K. Raju, Mazdoor with effect from 11-7-1973 was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 42012(51)/74.LR.III/D-II(B)]

प्रादेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1975

का० प्रा० 5214.—भारत सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड, नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व भारत सरकार मुद्रणालय फोटोलिथोग्रफि कर्मचारी संघ नई दिल्ली करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और उक्त नियोजकों और कर्मचारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें धणित

व्यक्ति के माध्यम के लिए निर्देशित करने का करार कर दिया है और उक्त माध्यस्थता करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थता करार को, जो उसे 15 नवम्बर 1975 को मिला था, एतद्वारा प्रकाशित करती है।

करार

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10क के अधीन के बीच पक्षकारों के नाम :

1. मियोजकों का प्रतिनिधित्व श्री जी० भगवान, सहायक प्रबन्धक करने वाले : (प्रशा०) भारत सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड, नई दिल्ली।

2. कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री प्रेम प्रकाश महा सचिव भारत सरकार मुद्रणालय फोटो लिथो विंग कर्मचारी संघ, मिण्टो रोड, नई दिल्ली

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एच० एच० कुरेशी क्षेत्रीय अमानुक्त (केन्द्रीय), 7/201, स्वरूप नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के माध्यस्थता के लिए एतद्वारा निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवाद प्रस्त विषय : क्या सर्वश्री श्री० पी० सूद, चरतजीत भगल, अमरजीत सिंह और मीहिन्द्र पाल, तकनीकी सहायक भारत सरकार मुद्रणालय, फोटो लिथो विंग, मिण्टो रोड, नई दिल्ली, संशोधित छुट्टी के नियम 1933 के अन्तर्गत छुट्टी के हकदार हैं ? यदि नहीं तो वे किस प्रकार की छुट्टी यदि कोई हो, के हकदार हैं ?

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण, (1) महा प्रबन्धक, भारत जिसमें अन्तर्बलित स्थापन या सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड, उपक्रम का नाम और पता भी नई दिल्ली - 1 सम्मिलित है।

2) महा सचिव, भारत सरकार मुद्रणालय फोटो लिथो विंग कर्मचारी संघ, 128/18-सी, चान्द मोहल्ला गांधी नगर, दिल्ली - 31

3. करार का नाम यदि वह स्वयं भारत सरकार मुद्रणालय विवाद में अस्तित्व में हो या यदि फोटोलिथो विंग कर्मचारी कोई संघ प्रसंगत कर्मचारियों का संघ। प्रतिनिधित्व करता हो तो उस का नाम।

4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित 2760 कर्मचारियों की कुल संख्या :

5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभावित चार प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की प्राक्कलित संख्या :

हम यह करार करने हैं कि माध्यस्थता का विनिर्देश हम पर आबद्ध कर होगा। माध्यस्थता प्रस्ताव पचास छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पचास नहीं दिया जाता तो माध्यस्थता के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा। और हम नए माध्यस्थता के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

साक्षी :

हस्ता०- (बी० पी० भार्गव) 1. हस्ता० /- (जी० भगवान)
स० क० (के०) के आशुलिपिक मुद्रणालय के सहायक प्रबन्धक
हस्ता० /- (रूप लाल शर्मा) 2. हस्ता० /- (प्रेम प्रकाश)
भारत सरकार मुद्रणालय में संघ के महा सचिव
निषिक्त।

तारीख 13-11-75

[स० एल० 16012(4)/75-डी-2 (बी०)]
हरबंस बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 24th November, 1975

S.O. 5214.—Whereas an industrial dispute exists between the employer in relation to the management of the Government of India Press, Minto Road, New Delhi and its workman represented by the Government of India Press, Photo Litho Wing Karamchari Sangh, New Delhi.

And whereas the said employers and workmen have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to the arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 15th November, 1975.

AGREEMENT

Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947

B E T W E E N

Names of the Parties

1. Representing Employers :

Shri G. Bhagwan, Assistant Manager (Admn.) Govt. of India Press, Minto Road, New Delhi.

2. Representing Workmen :

Shri Prem Parkash, General Secretary, Govt. of India Press Photo Litho Wing Karmchari Sangh, Minto Road, New Delhi.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri H. H. Quraishy, Regional Labour Commissioner (Central), 7/201, Swaroop Nagar, Kanpur (U.P.)

- (i) Specific matters in dispute. Whether S/Shri O. P. Sood, Charanjit Bhaggal, Amarjit Singh and Mohinder Pal, Technical Assistants Government of India Press Photo Litho Wing Minto Road, New Delhi are entitled to leave under the revised Leave Rules, 1933? If not, to what kind of leave, if any, are they entitled?
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
1. General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.
 2. General Secretary, Govt. of India Press Photo Litho wing Karamchari Sangh, 128/18-C, Chand Mohalla Gandhi Nagar, Delhi-31.
- (iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any representing the workmen in question
- Govt. of India Press Photo Litho Wing Karamchari Sangh.
- (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected. 2760
- (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute. Four

We agree that the decision of the arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of six months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Witnesses :

Sd/-

(V. P. Bhargava) Steno to ALC(C)

Sd/-

(Roop Lal Sharma)

Clerk in Govt. of India Press

Dated 13-11-1975.

Sd/-

1. G. BHAGWAN, Asstt. Manager, Press

Sd/-

2. PREM PARKASH, G. Secy. of Union

[No. L-16012(4)/75-D-II(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Special)

New Delhi, the 17th November, 1975

S.O. 5215.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Binny Limited, Steamer Agents, Cochin and their Coopers, which was received by the Central Government on the 14th November, 1975.

(AWARD)

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L.,
PRESIDING OFFICER, : INDUSTRIAL TRIBUNAL

MADRAS.

(Constituted by the Central Government)

Monday, the 27th day of October, 1975

Industrial Dispute No. 30 of 1974.

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947 between the workmen and the management of M/s. Binny Limited, Steamer Agents, Cochin.)

BETWEEN

The workmen represented by The Secretary, Cochin Dock Employees' Association, Door No. VI/71, Calvethy, Cochin-1.

AND

The Manager, M/s. Binny Ltd., VI/57, Calvethy Road, Post Box No. 6, Cochin-682001.

Reference :

Order No. L. 35011/1/74/P&D/IR. III, Dated 16-7-1974 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Saturday the 18th day of October, 1975, upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of M/s. M. P. Menon and M. Ramachandran, Advocates for the workmen and of Thiru K. V. R. Shenoi for M/s. Menon and Pal, Advocates for the Management and having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India, by its order No. L. 35011/1/74/P&D/IR. III, dated 16-7-1974 of the Ministry of Labour have referred the following industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Binny Limited, Steamer Agents, Cochin and their Coopers for adjudication.

2. The issue is as follows :—

"Whether the action of the management of Messrs Binny Limited, Steamer Agents, Cochin in denying weekly off with wages to their Coopers is justified? If not, to what relief are the Coopers entitled?"

3. The General Secretary of the Cochin Dock Employees' Association has filed a claim statement alleging that the Coopers concerned in this dispute are dock workers engaged by Binny Limited a Cochin Port and that they have got work only for 15 days in a month and for the days on which they have no work, they are paid attendance allowance, that no Wages are paid on the weekly off day after the 6th day. It is also alleged that on the basis of the demand of the workmen in the Madras Dock Labour Board, the Arbitrator Sri O. Venkatachalam in his award has held that the employees of the Madras Dock Labour Board should be given weekly off with wages. The conditions of employment of Dock Workers in Madras and Cochin are almost identical and that the provisions of the award passed by Sri Venkatachalam should be ordered to be extended to Cochin as well.

4. The Management has filed a counter statement alleging that the three Coopers attached to the Clearing and Forwarding Department of Binny Limited, Cochin are not entitled to the weekly off with wages demanded by them and that the Coopers are daily-rated workers and their terms and conditions are governed by Settlement dated 1-8-1970 entered into between the West Coast Employers' Federation, Cochin, representing the employers and the several unions representing them. The management contends that the Coopers are casual labourers and they can be provided work only when work is available and as they do not work continuously on all

the working days of a week or month, the demand for weekly off with wages is unreasonable. The Dock Workers at the Cochin Port are not getting weekly off with wages. Moreover, on days on which the Coopers have no work they are free to engage themselves in outside employment and they accept outside work when it is more advantageous to them. The Management also contends that the award passed by Sri O. Venkatachalam in respect of Madras Dock Workers has no application to the Cochin Port.

5. The Union has filed a rejoinder alleging that the Coopers are dock workers and there is no justification in treating them on a different footing than other categories of workmen to enjoy the weekly off with wages. It is also alleged that the Coopers are not mere casual employees and that they covered by provident fund scheme and have to report in their allotted place of work on all working days. Lastly, it is alleged that the Willingdon Island is a place to which the provisions of Kerala Shops Act have been extended and the employees concerned are entitled to get the resulting benefits also.

6. ISSUE : The simple point to be decided under this issue is, whether the Coopers employed by Messrs. Binny Limited at Cochin Port for attending to the rectifying the defects in packing cases, and also at times opening the packing chests for purposes of inspection at the time of export are entitled to weekly off with wages. I will now discuss the several points put forward on behalf of the employees relating to the claim for weekly off with wages. The first ground that was urged was that the Coopers have guaranteed work only for 15 days in a month and on such days they get Rs. 9.38 as wages and for the rest of the days they are given only attendance money at the rate of Rs. 5/- per day and that they attend for 6 days in a week and the 7th day is a weekly off day and no wages are paid to the weekly off day. There is no merit in this claim for the following reasons :—Firstly, the Coopers are only casual workers. Admittedly, their work is connected with the shipping of export cargo of cashew cartons. The Coopers can get work only on days on which the Management can provide work and it depends upon the value of shipments of cashew cartons handled by the Management. It is also admitted that on days on which no work is provided to these Coopers, they are paid only attendance money. Under those circumstances, it cannot be said that they are permanent employees or that the management can provide work continuously for 6 days in a week. The employers represented by the West Coast Employers' Federation, Cochin-3 and the Shore Tally Clerks and Coopers represented by the four unions, namely, Cochin Thirumugha Thozhilali Union, Cochin Port Cargo Labour Union, Cochin Port Thozhilali Union and Brooke Bond Employees' Association have entered into a settlement on 25th August, 1975. Ex. M-2 is the cyclostyled copy of that agreement. In Ex. M-2, the party No. 2 represented the employers of M/s. Binny Limited, Cochin-1. Admittedly, the Coopers are working under the Management of M/s. Binny Limited. Clause (4) of this agreement relates to leave of all kinds. There is no whisper in this agreement about the Coopers getting any weekly off with wages. This agreement does not make mention of the fact that the Coopers are not entitled to get weekly off with wages. The learned counsel for the Union argued that the weekly off with wages was not the subject matter of this agreement and so it cannot be said that the workers were denied weekly off with wages; that this agreement seen in clause (4) in Ex. M-2 relates to the fact how leave should be accounted for 240 days of attendance and National and Festival Holidays and the accumulation of leave etc., and this clause (4) cannot be invoked for contending that the Coopers were denied weekly off with wages. It is true that there is no mention about weekly off with wages, in Ex. M-2. But the entire memorandum has to be read. Clause (8) of this agreement reads that the Management will have discretion to decide on the number of workers required for work on Sundays and holidays, for overtime work on all days and for night shift work. Clause (10) of the agreement relates to the overtime work and night shift work whenever available for Shore Tally Clerks and Coopers. When Clause (8) shows that the Management has got a discretion to decide on the number of workers required for work on Sundays and holidays, the Coopers are not entitled to get any weekly off with wages as a matter of right. This agreement Ex. M-2 is binding on the Coopers. Ex. M-2 does not confer any right

on the Coopers to get weekly off with wages, and so they are not entitled to demand weekly off with wages.

7. The second ground that was urged was that the Arbitrator Sri O. Venkatachalam in his Award in respect of Madras Dock Labour Board has decided that the employees of the Madras Dock Labour Board are entitled to weekly off with wages. Admittedly, the Madras Port is a very busy Port than Cochin Port. The conditions that are prevalent in Madras cannot be the same in Cochin. Further there is averment in the counter in para (7) to the effect that Dock Workers at the Cochin Port are not getting weekly off with wages. There is no evidence to rebut this allegation. Under those circumstances, if any weekly off with wages are given to these Cochin Dock Employees, then it would lead to industrial unrest.

8. The 3rd point that was urged on behalf of the employees is that Willingdon Island is a place to which the Provisions of Kerala Shops Act has been extended, and that that the employees are entitled to the provisions of Kerala Shops Act. In other words, the employees invoke the benefits of the provisions of the Kerala Shops Act to get the weekly off with wages. Admittedly, the work of the Coopers relate to the cashew cartons and also opening the packing chests and at times, for purposes of inspection. Their work is not in any establishment or in any factory. Moreover, they are only casual employees asked to work in the Port at the time of loading the cargo. Under those circumstances, there is no scope for application of the provisions of Kerala Shops Act. In view of the discussion above I hold that the Coopers are not entitled to weekly off with wages. This issue is found in favour of the management.

9. In the result, an award is passed holding that the action of the management of Messrs. Binny Limited, Steamer Agents, Cochin in denying weekly off with wages to their Coopers is justified. There will be no order as to costs. Dated, this 27th day of October, 1975.

(Sd/-)

T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal.
WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

For workmen : Nil.

For Management :

Ex. M-1/1-8-1970—Memo of settlement under section 12(3) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers represented by the West Coast Employers' Federation, Cochin-3 and the Tally Clerks and Coopers represented by the unions. (copy).

Ex. M-2/25-8-1975—Memorandum of settlement arrived at under section 12(3) of the Industrial Disputes Act, 1947 in the course of conciliation proceedings held by the Assistant Labour Commissioner (Central) Ernakulam in the industrial dispute between certain employees represented by the West Coast Employers' Federation, Cochin-3 and the Shore Tally clerks and coopers represented by the Unions (copy).

(Sd/-).

T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal.

Note : Parties are directed to take return of their documents within six months from the date of the award.

True Copy Forwarded

(By order)

Head Ministerial Officer,
Industrial Tribunal, Madras.

[No. I-35011/1/74/P&D/LR.III/D-IV(A)]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

New Delhi, the 21st November, 1975

S.O. 5216.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th November, 1975.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
AT CALCUTTA**

Reference No. 54 of 1975

PARTIES :

Employers in relation to the State Bank of India,

AND

Their Workmen

APPEARANCE :

On behalf of Employers.—Shri A. K. Mitra Law Officer.

On behalf of Workmen.—Shri Ranajit Das, General Secretary, State Bank of India Employees' Association.

STATE : West Bengal

INDUSTRY : Banking.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by Order No L. 12012/30/74/IRIII, dated 18th August, 1975, referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, to this Tribunal for adjudication. The reference reads as follows :

"Whether the management of the State Bank of India, Calcutta is justified in discontinuing the payment of Dafttry allowance from 1st January 1974 to Shri Gour Modak ? If not to what relief is the said workman entitled ?"

2. The State Bank of India filed a written statement dated 6th October, 1975 raising various contentions. They also stated that the workman in question is not entitled to claim any Dafttry allowance from 1st January, 1974 or any other relief. Long before the written statement of the Bank was filed before the Tribunal, the General Secretary of the State Bank of India Employees' Association filed a statement on 29-9-1975 before this Tribunal alleging that the grievance of the employee concerned in the reference has been redressed by the management and that, therefore, there is no grievance in existence to be adjudicated upon under the reference. The workman had also filed a similar statement before the State Bank of India on 6-10-1975 stating that his grievances contained in the Reference had been redressed and that he may be permitted to withdraw the grievance placed before the Tribunal.

3. Any way, at the time of hearing the case to-day, both sides appeared and stated that the Reference need not be enquired into as the matter has been settled between the parties.

In the result the reference is rejected.

[No. L. 12012/30/74/LR III]

E. K. MOIDU, Presiding Officer

Dated, Calcutta, the 7th November, 1975

S.O. 5217.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay in the Industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th November, 1975.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL AT BOMBAY**

Reference No. CGIT-9 of 1974

PARTIES :—

Employers in relation to the Bank of Maharashtra
And

Their Workmen.

PRESENT :

Shri B. Ramlal Kishen, I.L.M., Bar-at-Law, Presiding Officer.

APPEARANCE :

For the employers.—Shri N. D. Juvekar, Advocate.

For the workmen.—Shri S. M. Dharap, Advocate with Shri R. D. Jog, Vice-President, Bank of Maharashtra Workers' Organisation, Poona and Shri S. P. Bhide the workman in person.

STATE.—Maharashtra.

INDUSTRY.—Banking.

Bombay, dated 3-10-1975

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, have by their Order No. L. 12012/73/74/LR III dated 21st November, 1974, made in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the Bank of Maharashtra and their workmen in respect of the matter specified in the following schedule annexed to the order of reference.

SCHEDULE

"Whether the Action of the Management of the Bank of Maharashtra, Chandrapur Branch, Chandrapur, Maharashtra State, in refusing to continue the services of Shri S.P. Bhide, Clerk in the said Bank from the 27th June, 1974 onwards is justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. After the receipt of the order of reference notices were issued to the parties to file their statements. The general Secretary, Union of Maharashtra Bank Employees, Nagpur filed the statement of claim on behalf of the workman. It is submitted that Shri Suresh Purshottam Bhide was appointed at Sitabuldi, Nagpur branch on 16.12.1972. Later it is stated that he worked as temporary clerk till 21-2-1973 on expiry of which he was given further extension till 30-10-1973. It is submitted that on 29-10-1973 Shri Bhide was given an appointment order for a period of three months with instructions to report at Chandrapur Branch on 5th November, 1973. It is also stated that in this order he was assured that he would be taken up on probation if his work and conduct was found satisfactory but although he worked at Chandrapur Branch till 27-7-1974 his services were finally illegally terminated on 28-7-1974. Hence it is contended that it is in contravention of the provisions of section 33 of the Industrial Disputes Act, 1947. It is also stated that the management was fully aware of the fact that the service of Shri Bhide cannot be terminated during the pendency of conciliation proceedings and the management had attempted similarly on 28-6-1974 when the proceedings before the Assistant Labour Commissioner (C) were pending and relieved the employee illegally on that date. The union, it is stated, lodged a complaint under section 33A of the Act and the management reinstated the workman on 29-6-1974 treating 28-6-1974 as casual leave.

3. It is stated that Shri Bhide was working in a clear and permanent vacancy from 22-2-1973 onwards till the date of final termination on 28th July, 1974 and from the records it will be evident that the Bank was a tempting to utilise his services in a permanent and clear vacancy with mal intention to circumvent the provisions of the Bank Awards and Settlements and further to deprive him of all the benefits permissible to confirmed employees. It is the case of the union that 14 days' notice was to given to Shri Bhide when his services were terminated on different occasions. As such these were

in violation of the Bank Awards and balance illegal and null and void. It is submitted that Shri Bhide was selected for permanent appointment after he was given test and interview. But the bank kept him on the waiting list according to the union to pursue its unfair labour practice and mal intention to deprive him of the benefits of annual increment, leave facilities, medical aid, provident fund, gratuity etc. As the management did not confirm the employee an industrial dispute was raised before the A.I.C. (Central) Nagpur on 4-6-1974 but the conciliation ended in failure and the failure report was submitted on 29-7-1974, but the management terminated the services of Shri Bhide on 28-7-1974 during the pendency of conciliation proceedings. The union has referred to the provisions of the Sastry Award, Desai Award and the Bi-Partite Settlements and prayed that Shri Bhide should be reinstated with effect from 28-7-1974.

4. The Bank has by its written statement in reply submitted that the statement of claim of the union is based on misconception of law and has denied most of the averments made in the statement of claim. It is contended by the bank that the present order of reference is illegal and void and the Tribunal does not derive the jurisdiction to entertain or adjudicate upon the industrial dispute referred to by the invalid order. It is also contended that the reference is hit by the principle of res-judicata particularly in view of the pleadings in para 10 of the statement of claim and reference to the complaint under section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947. It is contended that the complaint under section 33A for a violation of the provisions of section 33 is an industrial dispute and also shall be deemed to be an industrial dispute for the purpose of the complaint under the provisions of section 33A. In view of the said complaint it is contended that the present reference under section 10(1)(d) is hit by the principles of constructive res-judicata and on this premise also the reference is not tenable. Therefore, it is contended that by virtue of the pleadings in para 10 of the statement of claim the union is not entitled to rake up the issue under the colourable exercise of powers under section 10(1)(d) of the Act and on this score also the reference is bad in law. It is the bank's case that on account of the adverse confidential reports and on account of his unsatisfactory work Shri Bhide was not continued in employment after the period of his temporary tenure of employment. As regards the relief claimed it is contended that the order of reference has not specifically or expressly mentioned the relief of reinstatement and this Tribunal has no jurisdiction to reinstate the employee who is discontinued for unsatisfactory work.

5. The union then filed a rejoinder rebutting the contentions of the bank made in its written statement. It also filed an application calling for certain documents and records from the bank. The bank took objection to the filing of the rejoinder by the union and contended that it should be rejected as not legally tenable and if the rejoinder is allowed the bank should be permitted to file a counter to the same.

6. The matter was then fixed for hearing on a few occasions but had to be adjourned at the request of the parties. At the hearing on 30-7-1975 both parties stated that the dispute was likely to be compromised and requested for time to file terms of settlement. The hearing was then adjourned to 28-8-1975 and later to 3-10-1975 on which date the parties filed terms of settlement and a joint application praying that an award may be made in terms of the settlement. Under the terms of settlement, the Bank of Maharashtra Poona, has agreed to take in its employment Shri S. P. Bhide, immediately not later than 15-10-1975 as a permanent clerk in the grade under the Bi-Partite Settlement. The Bank has further agreed to pay Rs. 2000 (Rupees two thousand only) to Shri Bhide as ex-gratia payment for the loss of his employment from 28-7-1974 to 15-10-1975 in full and final settlement. The settlement further provides that Shri Bhide's probationary period shall be six months prior to 15-10-1975 or the date on which the appointment order is issued by the Bank to him earlier.

7. In my opinion the terms of settlement are fair and reasonable and I therefore make an award in terms of the settlement annexure 'A' which shall form part of this award.

The reference is answered accordingly.
No order as to costs.

Sd/-

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

BEFOR SHRI B. RAMLAL KISHAN

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,

BOMBAY

Ref. (CGIT) No. 9/74

BOMBAY

BETWEEN

BANK OF MAHARASHTRA, POONA

AND

WORKMEN EMPLOYED UNDER IT

May it please the Hon. Tribunal,

The parties to this reference has settled the dispute amicably on the terms hereunder. It is therefore prayed that the Award may please be passed in Terms of Settlement.

TERMS OF SETTLEMENT

(i) Bank of Maharashtra, Poona agrees to take in its employment Shri S. P. Bhide, C/o G. R. Karmarkar, Gopal Nagar, Joshi Wadi, Nagpur, immediately not later than 15-10-1975 as a permanent Clerk in the grade under Bi-partite Settlement.

(ii) Bank further agrees to pay to Shri S. P. Bhide Rs. 2,000 (Rupees two thousand only) as ex-gratia payment for the loss of his employment from 28-7-1974 to 15-10-1975 in full and final settlement.

(iii) that S. P. Bhide's probationary period shall be six months prior to 15-10-1975 or the date on which the appointment order is issued by the Bank to him earlier.

This Settlement is arrived at Bombay on this 3rd day of October, 1975.

[No. L. 12012/73/74/LR III]

Sd/-

S. P. BHIDE,

Sd/-

Sd/-

N. D. JUVEKAR,

Advocate

(with instructions to settle)
For Bank of Maharashtra.

R. D. JOG, Vice, President,

Bank of Maharashtra,

Workers Organization,

Poona.

S.O. 5218.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th November, 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL AT BOMBAY

Reference No. CGIT-8 of 1974

PARTIES :

Employers in relation to the Bank of Maharashtra

AND

Their Workmen.

PRESENT :

• Shri B. Ramlal Kishen, LL.M., Bar-at-Law,

Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the employers :—Shri N.D. Juvekar, Advocate.

For the workmen :—Shri S.M. Dharap, Advocate.

State :— Maharashtra.

Industry :— Banking.

Bombay, 4th October, 1975

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L. 12012/68/74/LR III dated 15th November, 1974, made in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the Bank of Maharashtra and their workmen in respect of the subject matter specified in the following schedule:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bank of Maharashtra, Poona in terminating the services of Smt. A.D. Dabade, Sweeper of Navi Peth Branch at Sholapur with effect from the 1st December, 1973 is justified? If not, to what relief is she entitled?"

2. After the receipt of the order of reference, notices were issued to the parties for filing their respective statements. The Vice-President of the Bank of Maharashtra Karamchari Sangh by his statement of claim on behalf of the workman has submitted that on or about 1st September, 1971 Smt. A.D. Dabade was appointed as a part-time employee (Sweeper) at Navi Peth branch of Bank of Maharashtra at Sholapur. It is submitted that in the Bank Awards as well as in the Bi-Partite Settlements there is a provision for appointment of any person as a part-time employee and except in the mode of payment there is no other provision of appointment of any person in the bank in any other capacity than in the capacity of an employee. According to the statement the bank paid the workman a salary of Rs. 40/- only and even though she was entitled to get increments, medical aid, bonus etc., she was refused the same. The union has further submitted that in the year 1972 one Smt. Kusum Punekar widow of an employee peon Shri Punekar was also appointed as a part-time sweeper in the same branch. She was paid Rs. 35/- per month as salary. By about the same time Smt. Dabade became the member of the Bank of Maharashtra Karamchari Sangh and on 1st December, 1973 the services of Smt. Dabade were terminated by the bank without assigning any cogent reason or without holding any enquiry against her or without giving any proper notice in respect of the termination of her services. The union further submits that surprisingly enough after the termination of services of Mrs. Dabade, Mrs. Kusum Punekar was appointed in place of Mrs. Dabade and she was paid a salary of Rs. 100/- per month from the date of termination of services of Smt. Dabade. It is the case of the Union that in the existing circumstances the termination of services of Smt. Dabade has been done to provide for more emoluments to Smt. Punekar, and it is submitted that the termination of services of Dabade was made with a view to put down the trade union activities undertaken by the various employees of the bank at Sholapur under the leadership and guidance of the Bank of Maharashtra Karamchari Sangh. It is finally submitted that the act of termination of Smt. Dabade was mala fide, was an unfair labour practice and victimisation and therefore an illegal act. It is therefore prayed that the Tribunal may be pleased to direct the reinstatement of Smt. Dabade with continuity of service and back wages with effect from 1st December, 1973 till the award became effective.

3. The bank by its written statement in reply has contended that the order of reference is neither legal nor proper as the said reference is made in respect of a non-workman and as such it is bad in law and this Tribunal has no jurisdiction to entertain and try to reference. It is further contended that the employee Mrs. A.D. Dabade of Sholapur Branch was not a workman within the meaning of section 2(6) of the Industrial Disputes Act and also she is not an employee within the

meaning of section 2(6) of the Bombay Shops and Establishments Act and the reference order under section 10 in respect of a non-workman is not legal and proper. It is the submission of the bank that the facts stated in the statement of claim are incorrect and according to the bank the facts are as follows :—

4. The work of sweeping of the Branch Office at Sholapur and filling drinking water was being carried out by a maid servant; that the work of sweeper was only for a short period, for about an hour in the morning and an hour in the evening and as such there was no post of sweeper in the schedule of the said branch. It is contended by the bank that the work was entrusted to Mrs. Dabade on job work basis and her salary was debited to the charges called P/L sundry charges. She was paid Rs. 40/- per month for the job work for one hour in the morning and one hour in the evening as this branch was working on double shifts during the day and she was working as a job worker from September, 1971 to October, 1973. It is stated that she used to depute some family members for this purpose and so there was no employer-employee relationship. It is further submitted that the charter of demands under section 2A of the Industrial Disputes Act was not served by the concerned employee on the bank and as such the present reference is not tenable in law. In the first instance she approached the Government Labour Officer, Sholapur of the State of Maharashtra who had no jurisdiction to entertain the dispute. It is further submitted that as Smt. Dabade was not an employee her name was not borne on the muster roll of the bank nor were her wages paid on the wage register. It is stated that she might have been paid for job work for which she appears to have been paid by the Agent of the Sholapur branch and such type of job workers are not covered either by the Bank Award or by the subsequent settlements and the Desai Award has by virtue of paragraph 16 : 9 specifically excluded such type of employees. The Bank has contended that the sweeper's job is a category by itself and usually these jobs are done by persons in the family and the payment goes to the family; that they are more or less contractual jobs which are not regulated by awards. It is contended that the job of Mrs. Dabade was not a part of the work of the Banking Industry nor was it incidental thereto and the persons performing such jobs are not covered under the scheme of the Industrial Disputes Act, 1947. In this connection attention is invited to Item 14 of paragraph 16 : 5 of the Desai Award in which the case of the union itself was that such type of categories should not be given the benefit of the Bank Award and the Desai Award therefore in paragraph 16 : 9 has clearly directed as follows :—

"The State Bank of India has claimed that casual workers or job workers should be excluded from the operation of this award. I have made no provision in any part of this Award in connection with them and the persons who are casual employees or who are employed to do job work are excluded from the operation of this award."

It is therefore submitted that the employees who are doing job work are excluded from the operation of the award. It is further submitted that paragraph 123 of the Sastry Award and para 20 : 4 of the Bi-Partite Settlement have also considered the category of part-time employees. There is no prohibition in the Bi-Partite Settlement for appointment of part-time employees for casual or job work and for this reason also Mrs. Dabade is not a workman under the Act. The Bank has admitted that Smt. Kusum Punekar widow of a bank employee, Peon, Punekar, was appointed on one-third salary basis of Rs. 90/- p.m. according to the bank rules, whereas Mrs. Dabade's p.m. remuneration was Rs. 40/- flat per month. Therefore the case of Smt. Punekar has no application in the present case and even on that analogy the same cannot be made applicable to a person who is employed for job work. Regarding the union's allegation of victimization for trade union activities it is submitted that it is purely an afterthought as no such submissions were made before the Conciliation Officer. The allegations of mala fide and unfair labour practice are also denied and it is stated that they are made with an ulterior motive to prejudice the Tribunal. Finally, it is submitted that the relief of reinstatement claimed by the union is in excess of the schedule appended to the order of reference as it does not provide for reinstatement. The only question according to the bank is as to what relief she is entitled to and as she is not a workman and not protected by any

of the provisions of the award and settlement she is not entitled to claim reinstatement.

5. The workman has examined herself and she has stated that she was working in the Bank of Maharashtra, Sholapur Branch for three years upto December, 1973. She used to work from 6-30 to 8-30 a.m. and from 3-30 to 4-30 p.m. In the morning she used to sweep, clean the tables and clean the clothes used for cleaning and in the evening she used to clean and sweep the floors and furniture. She was getting Rs. 40/- for this work which she used to do herself. She had never asked any of her family members to do this work and it was not correct to suggest that she was on job basis or on contract basis. No notice of termination was given to her and one Mrs. Kusumbai Punekar was given this work after her termination. She had requested the bank and also sent one letter to take her in employment. She filed a copy of a letter which she says is signed by her. She has stated that after termination of her service till today she was not in service anywhere and her salary was not deducted for absence from duty. She wants to be reinstated with continuity of service and back wages.

6. EW-1 Shri S. G. Sardesai was examined on behalf of the bank and he has stated that she was working in the Sholapur branch of the Bank of Maharashtra from 1970, to 1973 as an Agent. He knows the workman who was appointed by him as a sweeper and water-carrier. She was not cleaning the tables and there was one hall of 60X40 approx. Two rooms were underground; one was used for stationery and other for safe vault. The stationery room was to be cleaned once in a week and she used to take one hour to sweep the hall in the morning. She used to come at 2-30 p.m. again and used to work for half an hour. She was appointed as a sweeper on a salary of Rs. 40/- per month fixed by him on the basis of work. She was not getting her wages according to any award or settlement and her name was not entered in the muster roll or any register. He has stated that Rs. 40/- was paid to her under sundry charges in the profit and loss account. She was not given any appointment letter and in her absence the workman deputed her daughter to discharge her duties. The amount of Rs. 40/- was paid under a voucher. Witness was not an agent of the bank at the time when her work was stopped.

7. Before going into the merits of the dispute, pausing here I shall deal with the preliminary objections relating to jurisdiction raised by the management. It is pleaded by the management in paragraph 6 of the written statement that the charter of demands under section 2A of the Industrial Disputes Act was not served by the concerned employee of the Bank and therefore the present reference is not tenable in law. In the first instance she approached the Government Labour Officer, Sholapur, State of Maharashtra who has no jurisdiction to entertain the present dispute. It is contended before me by the learned Counsel for the management that as no demand was raised by the workman with the employer, it does not become an industrial dispute and therefore the reference of the dispute to this Tribunal was bad in law and untenable.

8. On the other hand it is contended by the learned Counsel for the workman that it is for the Government to form an opinion as to whether an industrial dispute exists or is apprehended and once it forms an opinion that an industrial dispute exists, it can validly refer the dispute to the Tribunal and the Tribunal cannot question the opinion of the Government as to the existence of an industrial dispute. It is further contended that the dispute was raised before the Conciliation Officer by the workman and the Conciliation Officer had submitted his failure reports to the Government and thereafter the Government had made the reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act. In the alternative it is argued that there is evidence of the workman that she had made a request for reinstatement to the bank and the workman had filed a copy of a letter before this Tribunal which is addressed to the Agent, Bank of Maharashtra, Navi Peth, Sholapur which reads as follows:—

"Please find below herewith a demand which is being served on you today on 5-4-1974 for being granted to me.

I am waiting for a suitable reply from you in respect of this demand till 15-4-1974, failing which I shall be constrained for want of an amicable settlement to take legal course of action under section 2-A of the I.D. Act, 1947, which please note."

DEMAND

"I, Smt. Ambubai Dattatraya Dabade, should be reinstated in my original post in the Navi Peth Br. Sholapur of the Bank of Maharashtra, with continuity of service and full back wages from 1-12-1973."

It is contended that this letter showed that a demand was made on the management for reinstating the workman.

9. Two preliminary issues arise for consideration at this stage in view of the stand taken by the employer viz.,

- (1) Whether the Bank of Maharashtra Kuramchuri Sangh had made a valid demand on the management for the reinstatement of the workman Smt. A. D. Dabade? and
- (2) Whether the reference is incompetent as alleged by the management?

10. The question that now poses for determination is whether Smt. Dabade raised a demand with the management and whether the reference is competent. The Delhi High Court in 1973 II LLJ 307 held that the first question is a preliminary issue of jurisdiction. The object of the Industrial Disputes Act, 1947, is to provide for the investigation and settlement of industrial disputes. An industrial dispute as defined in section 2(k) of the Industrial Disputes Act exists or is apprehended before it could be considered by the Conciliation Officer under section 12 of the Act and then referred to the Labour Court by the appropriate Government under section 12(5) read with section 10(1) of the Act. The concept of 'industrial dispute' is that a demand is made by the workman and is rejected by the employer. It is this demand and rejection which constitutes a dispute between these two parties. Following the judgement of the Supreme Court in *Sindhu Resettlement Corporation Ltd., v. Industrial Tribunal of Gujarat* (1968 1 LLJ 834) A.I.R. 1968 S.C. 529 the Division Bench of the Delhi High Court in *Feddres Lloyd Cor., (p) Ltd., v. Lieut. Governor, Delhi*, A.I.R. 1970 Delhi 60 held that an industrial dispute could not be said to exist unless and until a demand was made by the workman on the employer and it was rejected by the employer. Their Lordship observed that if the workman does not make a demand on the employer but directly goes to the Conciliation Officer then even if the demand is made before the Conciliation Officer then and is not acceded to by the employer in the conciliation proceedings, it could not be said that an 'industrial dispute' within the meaning of section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947, existed between the workman and the employer. Though the reference is made by the Government on a consideration of the report of the Conciliation Officer under section 12(5) of the Industrial Disputes Act, 1947, the power of the Government to make the reference is derived from section 10(1) of the said Act which reads as follows:—

"Where the appropriate Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended, it may at any time, by order in writing,

- (a) refer the dispute to a Board for promoting a settlement thereof; or
- (b) refer any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute to a Court for inquiry; or
- (c) refer the dispute or any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute; if it relates to any matter specified in the second schedule to a Labour Court for adjudication."

The only basis of the jurisdiction of the Industrial Tribunal is the reference of the dispute made to it by the Government. If the Government does not make the reference the Industrial Tribunal does not get the jurisdiction to adjudicate on an industrial dispute under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947. The subject matter of the dispute

may relate to any of the matters specified in the second schedule to the Act. These are within the exclusive jurisdiction of the Industrial Tribunal. But the fact and legality of the reference fall outside the subject matter of the dispute and is therefore not a matter which falls within the exclusive jurisdiction of the Industrial Tribunal. The question whether a demand was raised by the workman with the employer and was rejected by the employer is a jurisdictional fact being part of the definition of 'industrial dispute' which must exist before the reference can be made by the Government. The challenge to the legality of the reference by the employer both before the Labour Court and in this Court is based on the ground that no industrial dispute existed within the meaning of S. 2(k) of the Act."

11. The Supreme Court in *Jaipur Udyog Ltd., v. The Cement Works Karamchari Sangh, Sahu Nagar* (1972 1 LLJ 437) following the decision in the *Sindhu Resettlement Corporation Ltd., v. The Industrial Tribunal of Gujarat* and others 1968 1 LLJ 834 held that unless a dispute was raised by the workman with the employer it could not become an industrial dispute.

12. These two decisions of the Supreme Court therefore finally establish that a mere demand on the Government without a demand on their employers cannot become an industrial dispute. The above decisions also establish beyond doubt that the legality of a reference can be impugned by disproving its factual basis.

13. These two decisions of the Supreme Court were followed by the Delhi High Court in *Delhi Transport Corporation v. Delhi Administration* and other 1973 II LLJ 307. It is true that in the State of Madras *v. C. P. Sarathy* 1953 1 LLJ 174 the Supreme Court had observed that the Government acting under section 10(1) is doing an administrative act and the fact that it has to form an opinion as to the factual existence of an industrial dispute cannot be questioned by the court while it is open to the employers to show that what was referred by government was not an industrial dispute within the meaning of the Act. But in *Newspapers Ltd. v. State Industrial Tribunal U. P.* AIR 1957 SC 532 it was held that the right of an aggrieved party to show that what was referred was not an industrial dispute at all even though the factual existence of a dispute may not be subject to such a challenge. Did the Supreme Court intend to exclude judicial review of facts in testing the legality of a reference under reference under section 10(1) of the Industrial Disputes Act, 1947? With great respect, it appears that no such rigid conclusion was reached by the Court in the above mentioned two decisions. In *C. P. Sarathy's* case (supra) the contention of Prabhat Talkies was that no dispute existed between them and their workmen and therefore they should not have been included along with the other cinema theatres in the reference made by the Government to the Industrial Tribunal. This contention was negated by the Court on two grounds. Firstly, it was said that the Labour Commissioner's report showed that an industrial dispute existed between the management and the employees of the cinema theatres. Secondly, a reference could be made even when a dispute was apprehended (though it may not be existing) and therefore Government had jurisdiction to make the reference even in respect of the Prabhat Talkies.

14. In the case before me the question of dispute being apprehended did not arise at all. Either the dispute existed or it did not. In *C. P. Sarathy's* case (supra) a dispute was apprehended and it was not, therefore, necessary to decide if it existed. In *Newspapers Ltd., v. State Industrial Tribunal* (supra) the question was purely one of law, namely whether the dispute between single workman and the employer was an 'industrial dispute'. It would appear therefore that neither of these two decisions finally establish that judicial review of the factual basis of the reference was precluded in all circumstances. The observations pointing in that direction may, therefore, be respectfully regarded as obiter. However, in view of the decision of the Supreme Court in *Sindhu Resettlement Corporation Ltd., v. Industrial Tribunal*, 1968 1 LLJ 834, it will be futile to discuss the matter any further. It is now finally established by the Supreme Court that a mere demand to the Government without a dispute being raised with the employer cannot become an industrial dispute.

15. In this case there is no positive evidence that any demand was made either by the workman or the union on the management for the reinstatement of Smt. Dabade prior to the dispute being raised by the workman before the Conciliation Officer. No reliance could be placed on the copy of the letter purported to have been written by the workman to the Agent of the Bank at Sholapur and produced before this Tribunal. The letter does not bear any date. No attempt was made by the union to produce any proof of the alleged letter having been sent to the management. It is stated by WW-1 in her cross-examination that she had made a request for reinstatement with the head office of the bank; she does not remember the exact date or month or year of such application; she also could not say how many days prior to her giving evidence before this Tribunal she had sent the demand letter. If the letter was in fact sent by the workman to the management the original would be in their possession and the union could have called upon the management to produce it before the Tribunal. Therefore no reliance can be placed on the copy of the letter filed by the workman before this Tribunal and it can therefore be safely concluded on the evidence on record that no demand was raised by the workman on the management prior to the dispute being referred by the Government for adjudication to this Tribunal. As no dispute was raised by the workman with the management prior to the dispute being referred by the Government for adjudication the Government was not competent to make this reference. The preliminary objections raised by the management are sustained. The reference made by the Government is therefore incompetent and has to be rejected.

16. As the parties have led evidence before me on the merits and have addressed arguments, I propose to deal with the merits of the reference also as to whether the action of the management of the Bank of Maharashtra, Poona, in terminating the services of Smt. A. D. Dabade, sweeper of Navi Peth Branch, Sholapur, with effect from the 1st December, 1973 is justified? if not, to what relief she is entitled?

17. It is argued before me by the learned Counsel for the management that no relationship of employer and employee existed between the management and the workman. It is contended that the workman was not an employee and her name was not borne on the muster roll of the bank nor her wages paid on the wage register. She might have been doing job work for which she appears to have been paid by the Agent of the Sholapur Branch and such type of job workers are not covered either by the Bank Award or the subsequent settlement. It is further contended that the Desai Award had specially excluded such type of employees by virtue of para 16 : 9.

18. The learned Counsel for the management has drawn my attention to the definition of 'employee' in the Bombay Shops and Establishments Act, which says :

"Employee' means a person wholly or principally employed in, and in connection with, any establishment and includes an apprentice but does not include a member of the employer's family."

It is argued that it cannot be said that the workman was employed wholly in connection with the work of the bank as she was only employed as a sweeper. It is further canvassed that the various awards and settlements do not provide for the employment of a part-time workman. As she was only doing job work her services could have been validly terminated and even if she is considered to be a part-time employee her services could be validly terminated.

19. On the other hand learned Counsel for workman argues that Smt. Dabade was duly employed as a part-time workman and her services were terminated on 1st December, 1973 without assigning any cogent reasons or without holding any enquiry against her or without giving any proper notice only to provide for Mrs. Kusum Punekar the widow of a bank employee.

20. The first issue that arises for consideration in view of the pleadings of the parties is whether Smt. Dabade was a

workman within the meaning of section 2(s) of the Industrial Disputes Act. Section 2(s) of the Act defines :

"Workman" means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any skilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be expressed or implied, and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with or as a consequence of, that dispute or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such person.....

- (i) who is subject to the Army Act, 1950, or the Air Force Act, 1950 or the Navy (Discipline) Act, 1934 ;
- (ii) who is employed in the police service or an officer or employee of a prison; or
- (iii) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity ; or
- (iv) who, being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding five hundred rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature."

21. I am only concerned with the definition of 'workman' given in the Industrial Disputes Act and not the definition of 'Employee' given in the Bombay Shops and Establishments Act which cannot be taken into account and which is wholly irrelevant for the purpose.

22. Paragraph 123 of the Sastry Award clearly provided for part-time employees, and fixed a minimum of one-third of the appropriate rate of pay and dearness allowance if such part-time persons worked for not less than 7 hours per week.

The Desai Award in paragraph 23 : 15 has stated :

"For the purpose of this award it would not be out of place to classify workman and to define the various classes in which workman fall. Having considered all the demands made both by workman and the banks, I direct that workman for the purpose of this award be generally classified as (a) permanent employees (b) probationers (c) temporary employees and (d) part-time employees."

The Tribunal has defined a part-time employee to mean :—

"An employee who does not or is not required to work for the full period for which an employee is ordinarily required to work and who is paid on the basis that he is or may be engaged in doing work elsewhere."

The Tribunal then went on to point out :

"Having considered all aspects of the matter the demands that there should not be any part-time workmen in any category except sweepers and cleaners, that there should not be any part-time workmen at all in any category and that part-time employees working for more than 3 1/2 hours a day should be treated as full time ones are rejected."

23. Paragraph 4.5 of the Bi-Partite Settlement on Part-Time workmen is as follows :—

"In supersession of paragraph 5.191 of the Desai Award, part-time workmen shall be entitled to graduated incremental pay scales related to their working hours, as follows :—

- (a) Part-time workmen other than those belonging to the subordinate staff shall be paid one-third of the basis pay, special allowance, house rent allowance and other allowance, if any, and dearness allowance and shall also be entitled to one-third of the annual increments payable under this settle-

ment to full time-workmen provided that the total working hours of such part-time workmen shall not exceed 12 per week.

- (b) Part-time workmen who are members of the subordinate staff shall (subject to clause 20.5) be paid :—

If their normal total working hours per week are :—

Upto 3 hours	At Bank's discretion.
More than 3 hours but less than 6 hours,	At Bank's discretion but Minimum Rs. 15 per month.
6 hours to 13 hours	One-third of the scale wages with proportionate annual increment.
More than 13 hours to 19 hours,	One-half of the scale wages with proportionate annual increment.
More than 19 hours to 29 hours,	Three-fourth of the scale wages with proportionate annual increment.
Beyond 29 hours,	Full scale wages.

Paragraph 20.4 of the Bi-Partite Settlement provided that notwithstanding anything contained in paragraph 498 of the Sastry Award or pass-book writing, all banks will be free to employ part-time clerks as pass-book writers.

24. The Bi-Partite Settlement therefore did not rule out the appointment of part-time sweepers and cleaners.

25. In paragraph 498 of the Sastry Award it is stated that according to the workman's demand there should be no provision for the employment of part-time employees, and this demand was in the course of arguments modified to apply to categories of services for which normally full time employees are engaged as it was pointed out to them that by the nature of work some employees as Bhats and Bhisties who supply water and sweepers need not be whole-time employees. It may also be not necessary for a small branch of the bank to have a full-time stenographer. Therefore, the employment of part-time sweepers was provided for both in the Sastry Award and the Desai Award and also in the Bi-Partite Settlement.

26. It is true that in paragraph 16.9 of the Desai Award it is stated as follows :—

"The State Bank of India has claimed that casual workers and job workers should be excluded from the operation of this award. I have made no provision in any part of this award in connection with them and persons who are casual employees or who are employed to do job work are excluded from the operation of this award."

27. Drawing inspiration from the above it was pointed out by the learned Counsel for the management that Smt. Dabade was merely doing job work and she is not a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act and is also not covered by the settlements and awards. The learned Counsel for the management has referred to the evidence of the workman in which she has stated :—

"It is true that for sweeping and filling in the water I was paid Rs. 40 per month. I was working two hours in the morning and one hour in the evening

It was said between me and the Manager that I will get Rs. 40/- for three hours work. When I was absent my daughter used to work. It is true that I was permitted to utilise the services of my daughter for doing my work during my absence from duty."

The workman however denied the suggestion that her wages of Rs. 40/- were fixed on job basis.

28. Reliance is placed by the management on the evidence of EW-1 who has stated :

"She used to take one hour to sweep the hall. She used to sweep the hall for one hour in the morning. She used to come at 2.30 p.m. again. She used to work for half an hour. She was appointed as a sweeper on a salary of Rs. 40/- per month. Rs. 40/- was fixed by me on the basis of the work. She was not getting wages according to any award or settlement. Her name was not entered in muster roll or any register. The Rs. 40/- was paid to her under sundry charges under the profit and loss account. She was not given any appointment letter. In her absence the workman deputed her daughter to discharge her duties. The amount of Rs. 40/- was paid under a voucher."

He has further stated :—

"I did not obtain any permission before the workman was appointed."

29. It was argued by the learned Counsel for the management that there was no order of the head office appointing the workman and she was also only merely doing job work and therefore she cannot be considered to be a workman.

30. These arguments fail to impress me. The mere fact that there was no appointment letter by the Head Office and the fact that she was deputed her daughter to do the sweeping work in her absence does not go to show that she was doing merely job work. No satisfactory evidence is placed before this Tribunal to this effect. If the management failed to enter her name in the muster roll or any register the workman cannot be penalised and the omission therefore of her name in the register or muster roll will not be of any consequence in determining her status.

31. It is admitted by EW-1 that prior to the appointment of the workman Smt. Dabade one person by name Shri Mama was appointed as part time sweeper by him. He does not remember the actual amount but he was paid one-third of the emoluments paid to full time sub-staff and Mama's appointment was converted into a full time appointment in some other branch. After the termination of services of Smt. Dabade it is admitted by the management that one Smt. Kusum Punekar the widow of a bank employee was appointed as part-time sweeper on one-third salary basis. This clearly goes to show that Smt. Dabade was appointed as a part-time sweeper, and she will be therefore deemed to be a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act. The mere fact that she was only employed on a part-time basis does not entitle the bank to arbitrarily terminate her services without any cogent reasons and following the due procedure and giving her due notice. In this case no order of termination was served on the workman, no enquiry was conducted and very arbitrarily she was removed from service in December, 1973. No authority or rule has been cited by the learned Counsel for the management that the management can terminate at will the services of part time employees. I therefore hold that the termination of services of Smt. Dabade with effect from 1st December, 1973 by the management of the Bank of Maharashtra is not justified.

32. The next question that arises is as to what relief the workman would be entitled. If the reference was competent, I would have made an award giving the relief of reinstatement with back wages to the workman. But I have already held on the preliminary objections raised by the employers that as no dispute was raised by the workman with the management prior to the dispute being referred by the Government for adjudication the Government was not competent to make this reference and it is therefore not possible for me to give

any relief to the workman in this award. The reference is rejected.

Award is made accordingly.

No order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer

Central Government Industrial Tribunal, Bombay.

[No. 12012/68/74/LR III]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1975

का० भा० 5219 :—गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों सम्बन्धी वेतन-बोर्ड में गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के प्रतिनिधि श्री के० एल० कपूर ने उक्त बोर्ड की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कार्यशील पत्रकार वेतन बोर्ड नियम, 1956 के नियम 13 के उप-नियम (i) के अनुसरण में, उक्त श्री के० एल० कपूर, द्वारा धारित स्थान, उस तारीख से अर्थात्, 2-11-75 से रिक्त समझा जायेगा जिस तारीख को केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त त्यागपत्र स्वीकृत किया गया है।

[संख्या बी०-24026/8/75-इक्यू० बी० (i)]

New Delhi, the 10th November, 1975

S.O. 5219.—Shri K. L. Kapur, representative of non-journalist newspaper employees on the Wage Board for non-journalist newspaper employees has resigned his membership of the said Board and it is hereby notified that the seat held by the said Shri K. L. Kapur shall, in pursuance of sub-rule (1) of the rule 13 of the working Journalists Wage Board Rules, 1956 be deemed to have fallen vacant with effect from the date the said resignation has been accepted by the Central Government, namely 2-11-1975.

[No. V-24026/8/75-WB(i)]

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

का० भा० 5220 :—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारत समाचार पत्र कर्मचारी फेडरेशन, नई दिल्ली की केन्द्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य श्री हिन्दुस्तान टाइम्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष, श्री एम० के० रामा-मूर्ति को गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी सम्बन्धी मजदूरी बोर्ड में श्री के० एल० कपूर के स्थान पर गैर-समाचार पत्र कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है, और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप खंड(ii) तारीख 21 जून, 1973 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० भा० 1958, तारीख 11 जून, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, क्रमांक 4 के मामले, कालम 2 की प्रविष्टि के लिये, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"श्री एम० के० रामामूर्ति, अखिल भारत समाचार पत्र कर्मचारी, फेडरेशन, नई दिल्ली की केन्द्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य और अध्यक्ष, हिन्दुस्तान टाइम्स कर्मचारी यूनियन, 16-नीति बाग, नई दिल्ली-110049"

[संख्या बी० 24026/8/75-इक्यू० बी०(ii)]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 11th November, 1975

S.O. 5220.—The Central Government hereby appoints Shri M. K. Ramamurthi, member of the Central Working Committee of the All India Newspaper Employees Federation, New Delhi, and President of the Hindustan Times Employees Union as a representative of the non-journalist newspaper employees on the Wage Board for non-journalist newspaper employees, vice Shri K. L. Kapur, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, No. S.O. 1958 dated the 11th June, 1975, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 21st June, 1975, namely:—

In the said notification, against serial No. 4, for the entry in column 2, the following entry shall be substituted namely:—

“Shri M. K. Ramamurthi, Member of the Central Working Committee of the All India Newspaper Employees Federation, New Delhi and President, the Hindustan Times Employees Union, 16, Ncti Bagh, New Delhi-110049.

[No. V-24026/8/75-WB(ii)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1975

का० आ० 5221.—जान अधिनियम 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री डी० एस० निमि को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[का. सं० ए०-12025/2/75-एम० I]

जै० सी० सक्सेना, धवर सचिव

New Delhi, the 31st October, 1975

S.O. 5221.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952, (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri D. S. Nimi as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[File No. A-12025/2/75-MII]

J. C. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1975

का० आ० 5222.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान इस्पात एंड बाटलिंग लिमिटेड बागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, थाना (इसके अन्तर्गत तारदेव, मुम्बई स्थित शाखा माल गोवाम भी है) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अप्रैल के तीसरे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[सं० एस०-35018(92)/74-पी० एफ० 2 (i)]

New Delhi, the 6th November, 1975

S.O. 5222.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hindustan

Breweries and Bottling Limited, Wagle Industrial Estate, Thana (including branch, Godown at Tradeo, Bombay) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1974.

[No. S. 35018(92)/74-PF.II(i)]

का० आ० 5223.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परलुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 30 अप्रैल, 1974 से मैसर्स हिन्दुस्तान इस्पात एंड बाटलिंग लिमिटेड बागले इंडस्ट्रियल एस्टेट थाना (इसके अन्तर्गत तारदेव मुम्बई स्थित इसकी शाखा मालगोदाम भी है) नामक स्थापन को उक्त परलुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35018(92)/74-पी० एफ० 2(ii)]

आर० पी० नरूला, धवर सचिव

S.O. 5223.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of April, 1974 the establishment known as Messrs Hindustan Breweries and Bottling Limited, Wagle Industrial Estate, Thana (including Branch Godown at Tardeo, Bombay) for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(92)/74-PF.II(ii)]

R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

का० आ० 5224.—केन्द्रीय सरकार, भूना-परथर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1973 के नियम 2 के उपनियम (5) के साथ पठित भूना परथर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० एम० 42011/1/73-एम०-iii एम० V (ii) तारीख 30 नवम्बर, 1973 को अंशतः उपान्तरित करते हुये श्री के० डी० हजेल उप कल्याण प्रायुक्त, अग्रक खान श्रम कल्याण संगठन, करखा, बिहार को श्री डी० के० सैन (उपरोक्त अधिसूचना में क्रम सं० 3) के स्थान पर उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों में भूना-परथर और डोलोमाइट खान कल्याण और उपकर प्रायुक्त के रूप में नियुक्त करती है जिसका मुख्यालय करमा हाकधर झुमरी तलैया जिला हजारीबाग (बिहार) में होगा।

[सं० ए०-11011/2/75-एम की]

सी० आर० निम, धवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 1975

S.O. 5224.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, (62 of 1972), read with sub-rule (5) of rule 2, of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973 and in partial modification of the notification of the Government of India

in the Ministry of Labour No. M. 42011/1/73-MIII/MV(Pt.), dated the 30th November, 1973, the Central Government hereby appoints Shri K. D. Hajela, Deputy Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare Organisation, Karma, Bihar, as Limestone and Dolomite Mines Welfare and Cess Commissioner for the purpose, of the said Act in the States of Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, and Jammu and Kashmir with headquarters at Karma, P.O. Jhumritaliya, Distt. Hazaribagh (Bihar). Vice Shri B. K. Sen (Sl. No. 3 of the above said notification).

[No. A-11011/2/75-MV]

C. R. NIM, Under Secy.

पति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1975

का० आ० 5225.—निष्कांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राजस्थान राज्य के कलक्टरों को उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत उनके अपने अपने जिलों में निष्कांत सम्पत्तियों के संबंध में उप अभिरक्षकों को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए उनके अपने अपने जिले के उप अभिरक्षक, निष्कांत सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1 (30)/विशेष सेल/75-एस० एस०-11]

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 12th November, 1975

S.O. 5225.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints the Collectors in the State of Rajasthan as Deputy Custodian of Evacuee Property for their respective Districts for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodians by or under the said Act in respect of evacuee properties in their respective Districts.

[No. 1(30)/Spl. Cell/75-SS. II]

का० आ० 5226. निष्कांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री शेर सिंह, आयुक्त-व-सचिव, पुनर्वास विभाग, राजस्थान सरकार को उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत उस राज्य में निष्कांत सम्पत्तियों के संबंध में उप महा अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए राजस्थान राज्य के लिए उप महा अभिरक्षक, निष्कांत सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1 (30)/विशेष सेल/75-एस० एस० 11]

S.O. 5226.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Sher Singh, Commissioner-cum-Secretary, Rehabilitation Department, Government of Rajasthan, as Deputy Custodian General of Evacuee Property for the State of Rajasthan for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian General by or under the said Act in respect of evacuee properties in the State.

[No. 1(30)/Spl. Cell/75-SS. II]

का० आ० 5227.—निष्कांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री पी० आर० अग्रवाल, उप सचिव, राजस्थान सरकार, पुनर्वास विभाग को उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत उस राज्य में निष्कांत सम्पत्तियों के संबंध में अतिरिक्त अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए राजस्थान राज्य के लिए अतिरिक्त अभिरक्षक, निष्कांत सम्पत्ति के रूप में नियुक्त करती है।

[1 (30)/बि० से०/75-एस० एस० -11]

दीना नाथ असीजा, अवर सचिव

S.O. 5227.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri P. R. Aggarwal, Deputy Secretary, Government of Rajasthan, Rehabilitation Department, as Additional Custodian of Evacuee Property for the State of Rajasthan for the purpose of discharging the duties imposed on Additional Custodian by or under the said Act in respect of evacuee properties in that State.

[No. 1(30)/Spl. Cell/75-SS. II]

D. N. ASIJA, Under Secy.

वारिण्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1975

का० आ० 5228.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार घरेलू रेफ्रिजरेटर्स का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम घरेलू रेफ्रिजरेटर्स का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) घरेलू रेफ्रिजरेटर्स का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1974 में नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्—

“6. निरीक्षण फीस—घोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के हर एक सौ रुपये के लिये 50 पैसे की दर से, न्यूनतम सौ रुपये के अधीन रहते हुए, फीस एक ही समय पर तथा एक ही परिसर में प्रस्तुत किये गये एक या अधिक परेषणों के लिये निरीक्षण फीस के रूप में निर्यात कर्ता, द्वारा अभिकरण को संदत्त की जायेगी।

[सं० 6(4)/72-नि० नि० तथा नि० सं०]

के० बी० बाल सुब्रमण्यम, उप निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 6th December, 1975

S.O. 5228.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the

following rules to amend the Export of Domestic Refrigerators (Quality Control and Inspection) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Domestic Refrigerators (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1975.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Export of Domestic Refrigerators (Quality Control and Inspection) Rules, 1974, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Inspection Fee.—Subject to a minimum of rupees one hundred, a fee at the rate of fifty paise per every hundred rupees of the f.o.b. value shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee for one or more consignment offered at one time and at one premises."

[No. 6(4)/72-EI & EP]

K. V. BALASUBRAMANIAN, Dy. Director.

उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1975

का० आ० 5229.—विकास परिषद (प्रक्रिया सम्बन्धी) नियम, 1952 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वित्त प्रायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, चण्डीगढ़ को 12 जून, 1976 तक की अवधि के लिये, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, शर्करा उद्योग विकास परिषद् का सचिव नियुक्त करती है, और भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1687/आई डी आर ए/6/4/75 तारीख 13 जून, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, पैरा 1 में क्रम संख्या 27 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"28 बिहत प्रायुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग,
चण्डीगढ़।"

[आई० डी० आर० ए० 6/10/75-सं० 8/4/74-सी० डी० एन०]

प्रेम नारायण, धवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY OF CIVIL SUPPLY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th November, 1975

S.O. 2529.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), read with rules 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Financial Commissioner and Secretary to the Government of Haryana, Agriculture Department, Chandigarh, as a member of the Development Council for Sugar Industry for a period up to and inclusive of 12th June, 1976, and makes the following amendment in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 1687/IDRA/6/4/74, dated the 13th June, 1974, namely :—

In the said Order, in paragraph 1, after serial number 27 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted namely :—

"28. The Financial Commission and Secretary to the Government of Haryana, Agriculture Department, Chandigarh."

[IDRA/6/9/75 No. 8/4/74-CDN]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1975

का० आ० 5230.—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार, उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2819 दिनांक 30 अगस्त, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(क) "3-बिहार" शीर्षक के अधीन रांची के सामने दी गई प्रविष्टियों के दूगरे कालम में दी गई वर्तमान प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"बिहट उप-महाप्रवक्षक, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, धुर्वा"

(ख) "5-गुजरात" शीर्षक के पश्चात् और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित को अन्तर्निविष्ट किया जायेगा ; अर्थात् :—

"5-क-हरियाणा

फरीदाबाद प्रधान, अनुसंधान और विकास केन्द्र, इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, सेक्टर-13, फरीदाबाद।"

(ग) "12-पंजाब" शीर्षक के अधीन फरीदाबाद में संबंधित प्रविष्टियों को समाप्त कर दिया जायेगा।"

[काहल संख्या 18(22)/74-पी० एण्ड सी०]

एन० बी० मुशमण्यन, धवर सचिव

New Delhi, the 28th November, 1975

S.O. 5230.—In exercise of the powers conferred by section 152 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 2819 dated the 30th August, 1975, namely :—

In the said notification,

(a) under the heading "3. Bihar", in the entries against Ranchi, for the existing entry in the second column, the following entry shall be substituted, namely :—

"The Senior Deputy General Manager, Heavy Machine Building Plant, Heavy Engineering Corporation Ltd., Dhurwa";

(b) after the heading "5. Gujarat" and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"5A. Haryana
Faridabad

Head, Research and Development Centre, Indian Oil Corporation Ltd., Sector 13, Faridabad."

(c) under the heading "12. Punjab", the entries relating to Faridabad shall be omitted.

[F. No. 18(22)/74/P&C]

S. B. SUBRAMANIAN, Under Secy.

